वैश्विक संवाद

16.1

अनेक भाषाओं में एक वर्ष में 3 अंक

समाजशास्त्र पर बातचीत अब्दी काजेमीपुर के साथ

नाजनीन शाहरोकनी

ईरान में समाजशास्त्र पर पुनर्विचार

नाजनीन शाहरोकनी
रेहानेह जावदी
इस्माइल खलीली
जोहरेह बयात्रिजी
अघिल दघाघेलेह
शिवा अलीनाकियान
नफीसेह आजाद
मराल लतीफी
महबूबेह मोघदम
फतेमेह मोगादासी
लाडन रहबारी
रेजा सोहराबी

राजनैतिक और सामाजिक अर्थव्यवस्था में श्रम प्रवासन

कैरन शायर
हेइडी गॉटफ्राइड
रीना अग्रवाल
अश्विन कुमार
मारिया कैमिला वेगा–सलाजार
कैरोलिना मोरेनो
सुएलेन कैस्टिब्लैंको–मोरेनो
जेवियर ए. पिनेडा डी.
लिन यू लिंग एनजी
युनहुई ये
अंजू मैरी पॉल
मुस्तफा यावस
सेजिन पार्क
फेंग जू
त्सज चुंग लाइ
कैक्सटन सिउ

खुला अनुभाग

> उलझी हुई संचय प्रक्रिया के रूप में युद्धः गाजा का मामला

पत्रिका

GD
अंक 16 / क्रमांक 1 / अप्रैल 2026
https://globaldialogue.isa-sociology.org/

isa International Sociological Association

> सम्पादकीय

ग्लोबल डायलॉग के खंड 16 का यह पहला अंक निरंतरता और नवीनीकरण दोनों से चिह्नित एक नए क्षण की शुरुआत करता है। तीन वर्षों के गहन और प्रतिबद्ध कार्य के बाद, कैरोलिना वेस्टेना और विटोरिया रोड्रिग्स *ग्लोबल डायलॉग* के संपादकीय सहायक के रूप में अपनी भूमिका समाप्त कर रहे हैं। वैश्विक समाजशास्त्र के लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण अवधि के दौरान पत्रिका को बनाए रखने और मजबूत करने में उनका समर्पण, संपादकीय देखभाल और महत्वपूर्ण दृष्टि आवश्यक थी। संपादकीय दल की ओर से, मैं उन दोनों के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। साथ ही, ISCTE – इंस्टीट्यूटो यूनिवर्सिटारियो डी लिस्बोआ के शोधकर्ता मार्सिया रेंजेल कैंडिडो का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, जो अब से यह भूमिका संभालेंगी। व्यापक संपादकीय अनुभव, सार्वजनिक समाजशास्त्र के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता और एक तुलनात्मक और वैश्विक दृष्टिकोण के साथ, मार्सिया निस्संदेह पत्रिका के प्रक्षेपवक्र में इस नए चरण में महत्वपूर्ण योगदान देंगी।

पिछला अंक, जो *ग्लोबल डायलॉग* के संस्थापक संपादक माइकल बुरावॉय की बौद्धिक, राजनीतिक और मानवीय विरासत को सामूहिक श्रद्धांजलि थी, के बाद इस नए अंक में, हम अपनी नियमित संरचना पर वापस आ गए हैं। यह हमारे ऐतिहासिक पल को बनाने वाली दो जरूरी चिंताओं से सीधी बातचीत करता है; ईरान की स्थिति और श्रम प्रवासन से जुड़े वैश्विक बदलाव।

'समाजशास्त्र पर बातचीत' खंड का प्रारम्भ नाजनीन शाहरोकनी के अब्दोलमोहम्मद (अब्दी) काजेमीपुर के साथ लिए गए एक साक्षात्कार से होता है, जिसमें राष्ट्रीय समाजशास्त्र पर बहस, सामाजिक परिवर्तन, धार्मिक और धर्मनिर्पेक्षा के मध्य चुनौतीपूर्ण सीमायें, और आज ईरानी समाजशास्त्र को आकारित करने वाले उभरते प्रश्नों पर चिंतन किया गया है।

इस बातचीत के बाद 'ईरान में समाजशास्त्र पर पुनर्विचार' खंड में कई लेख हैं, जिन्हें नाजनीन शाहरोकनी और रेहानेह जावदी ने ध्यान से सम्पादित किया है। ये लेख राजनैतिक दबाव, ज्ञानमीमांसीय निगरानी और गहरे सांस्कृतिक झगड़ों वाले माहौल में समाजशास्त्र करने के तनाव और उलझनों पर ध्यान दिलाते हैं। समाजशास्त्र की सार्वजनिक प्रासंगिकता और इस क्षेत्र के (गैर–) संस्थाकरण से लेकर, शिक्षण के निजीकरण, जातीय प्रश्न, जेंडर अध्ययन को लेकर संघर्ष और आलोचनात्मक शोध पर रुकावटों तक, यह खंड आज ईरानी समाजशास्त्र के सामने आने वाली चुनौतियों पर एक बहुआयामी नजरिया देता है। इसमें एक डायनैमिक राउंडटेबल भी है जो अलग–अलग जगहों पर मौजूद विद्वानों को इकट्ठा करती है, जो ईरान पर और ईरान से ज्ञान निर्माण की एक स्थित और सामूहिक तस्वीर बनाने में योगदान देते हैं।

ऐसे समय में जब ईरान एक बार फिर दुनिया भर में सुर्खियों में है, अक्सर चुनिंदा कहानियों, भूराजनैतिक सरलीकरण या संकीर्ण सुरक्षा लेंस के जरिए – जमीनी, सार्वजनिक और वैश्विक समाजशास्त्रीय नजरिए से जुड़ना और भी जरूरी हो जाता है। मुख्यधारायी मीडिया में घूम रही तस्वीरों के अलावा, ईरानी समाज राजनीतिक मुकाबले के जटिल रूपों, जीवंत बौद्धिक परंपराओं, सम्मान के लिए रोजमर्रा के संघर्षों और राज्य की शक्ति और सामाजिक लामबंदी के बदलते स्वरूपों से पहचाना जाता है। इन गतिशीलता को समझने के लिए उन विद्वानों की बात सुनने की जरूरत है जो ईरान *में*, ईरान *पर* और ईरान के *साथ* काम करते हैं, और जो मौजूदा घटनाओं को दमन, प्रतिरोध, ज्ञान उत्पादन और सामाजिक परिवर्तन के व्यापक इतिहास के भीतर रख सकते हैं। हालाँकि यह खंड सबसे हाल की घटनाओं का विश्लेषण करने के लिए समर्पित नहीं है, लेकिन यह स्थिति की एक व्यापक, ऐतिहासिक रूप से आधारित समझ प्रदान करने में बहुत योगदान देता है।

दूसरा बड़ा खंड, 'द पॉलिटिकल एंड सोशल इकॉनमी ऑफ लेबर माइग्रेशन', जिसे कैरेन ए. शायर, हेइडी गॉटफ्राइड और रीना अग्रवाल ने सम्पादित किया है, हमारे समय के सबसे अहम मुद्दों: वैश्विक पूंजीवाद के पुनःसंगठन में श्रम प्रवासन की केंद्रीय भूमिका, में से एक की जांच करता है। भारत में "सुरक्षित और व्यवस्थित" गतिशीलता कार्यक्रम से लेकर, वेनेजुएला और कोलंबिया को जोड़ने वाली वैश्विक देखभाल श्रंखला तक, चीन, सिंगापुर, दुबई और कंबोडिया में प्रवासी श्रम की व्यवस्था तक, ये लेख दिखाते हैं कि कैसे असमानता, जेंडर, नृजातीयता, सीमा, और राज्य शक्ति मिलकर अनिश्चितता के नए रूप पैदा करते हैं – और एजेंसी और निवासियों के लिए नई संभावनाएं पैदा करते हैं।

'खुला अनुभाग' में, यह मुद्दा गाजा में युद्ध पर गिलहर्मे लेइट गोंसाल्वेस के एक दमदार विश्लेषण के साथ खत्म होता है, जिसे राजनैतिक, आर्थिक, और औपनिवेशिक गतिकी में उलझे हुए जमाव के रूप में समझा गया है, जो युद्ध के मैदान से कहीं आगे तक फैला हुआ है।

इस अंक के साथ, *ग्लोबल डायलॉग* एक सार्वजनिक और वैश्विक समाजशास्त्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है जो मौजूदा, बहुल, और संवादी परिपेक्ष्य के माध्यम से समकालीन प्रक्रियाओं का विश्लेषण कर सके। हमें उम्मीद है कि यहां एकत्रित किए गए विचार, बहस और शोध बातचीत को बढ़ाने, नेटवर्क को मजबूत करने और असमानता, हिंसा और विस्थापन से बनी दुनिया में नए सवाल खोलने में मदद करेंगे – लेकिन साथ ही विरोध, विवेचनात्मक कल्पना और ज्यादा न्यायपूर्ण भविष्य के लिए मिलकर की गई कोशिशों से भी। ■

ब्रेनो ब्रिंगेल, संपादक, *ग्लोबल डायलॉग*

> वैश्विक संवाद जी.डी. वेबसाइट पर अनेक भाषाओं में देखा जा सकता है।

> प्रस्तुतियाँ <globaldialogue@isa-sociology.org> पर भेजी जा सकती हैं।

International Sociological Association

GLOBAL DIALOGUE

> संपादक मण्डल

संपादक : ब्रेनो ब्रिंगेल

सह–संपादक : क्रिस्टोफर इवांस

मैनेजिंग एडिटर : लोला बुसुटिल, ऑगस्ट बागा

सलाहकार : ब्रिगिट ऑलेनबैकर, क्लॉस डोरे

क्षेत्रीय संपादक

अरब दुनिया : (*लेबनान*) सारी हनफी, (*ट्यूनीशिया*) फातिमा राधौनी, सफौने ट्रैबेल्सी, सिवार हर्राबी, अहमद जेमा

अर्जेंटीना : मैग्डेलेना लेमस, जुआन पार्सियो, डांटे मार्चिसियो

बांग्लादेश : हबीबुल हक खोंडकर, खैरुल चौधरी, बिजॉय कृष्ण बानिक, शेख मोहम्मद कैस, मोहम्मद जहीरुल इस्लाम, हेलाल उद्दीन, मसुदुर रहमान, रसेल हुसैन, यास्मीन सुल्ताना, मोहम्मद शाहिदुल इस्लाम, फरहीन अख्तर भुइयां, रूमा परवीन, आरिफुर रहमान, मोहम्मद नसीम उद्दीन, आलमगीर कबीर, तस्लीमा नसरीन, सुरैया अख्तर, नुसांता औदरी, एकरामुल कबीर राणा, एस. मोहम्मद शाहीन

ब्राजील : फैब्रिसियो मैसिएल, आंद्रेजा गैली, जोस गुइराडो नेटो, जेसिका मैजिनी मेंडेस, कैरीन पासोस

फ्रांस/स्पेन : लोला बुसुटिल

भारत : रश्मि जैन, मनीष यादव

ईरान : रेहानेह जावदी, नियायेश डोलती, एल्हाम शुश्तरीजादे, अली राघेब

पोलैंड : एलेक्जेंड्रा बिएर्नाका, जोआना बेडनारेक, सेबेस्टियन सोसनोव्स्की

रूस : एलेना जद्रावोमिस्लोवा, डारिया खोलोदोवा

ताइवान : वानजू ली, युन–ह्सुआन चाउ, जी हाओ केर्क, यी–शुओ हुआंग, युन–जौ लिन, ताओ–युंग लू, चिएन–यिंग चिएन, यू–वेन लियाओ, नी ली

तुर्की : गुल कोरबासिओग्लू

*"समाजशास्त्र पर बातचीत" में, नाजनीन शाहरोकनी, **अब्दी काजेमीपुर** से ईरानी समाजशास्त्र को आकार देने वाले उभरते सवालों के बारे में बात करती हैं।*

*थीमैटिक सेक्शन **"ईरान में समाजशास्त्र पर पुनर्विचार"** दमन, ज्ञानमीमांसीय निगरानी और सांस्कृतिक संघर्ष के मध्य समाजशास्त्र करने के तनावों का अन्वेषण करता है।*

*थीमैटिक खंड **'श्रम प्रवासन की राजनैतिक और सामाजिक अर्थव्यवस्था'** वैश्विक पूंजीवाद के पुनर्गठन में श्रम प्रवासन की केंद्रीय भूमिका की जांच करता है।*

कवर चित्र : हैंस–पीटर गॉस्टर, अनस्प्लैश के जरिए

GD

सेज प्रकाशन की उदार ग्रांट से
वैश्विक संवाद का प्रकाशन संभव है।

> इस अंक में

संपादकीय 2

> समाजशास्त्र पर बातचीत

विशिष्ट की अंधभक्ति, और धर्मनिरपेक्ष के रूप में पवित्र
अब्दी काजेमीपुर के साथ एक साक्षात्कार
नाजनीन शाहरोकनी कनाडा द्वारा 5

> ईरान में समाजशास्त्र पर पुनर्विचार

दमन और प्रासंगिकता के बीच: ईरान के नजरिए से समाजशास्त्र पर पुनर्विचार
नाजनीन शाहरोकनी, और रेहानेह जावदी, कनाडा द्वारा 8

ईरानी समाजशास्त्रीय संघ और गैर–संस्थागतीकरण का संस्थागतीकरण
इस्माइल खलीली, ईरान द्वारा 11

राजनीति और लाभ के मध्य:
ईरान में समाजशास्त्र की निजी कक्षायें
रेहानेह जावदी और जोहरेह बयात्रिजी, कनाडा द्वारा 14

ईरान में नृजातीयता: वह प्रश्न जिसे ईरानी समाजशास्त्र टालता है
अघिल दघाघेलेह, यू.एस.ए. द्वारा 17

स्थित जीवन, विवादित ज्ञान:
ईरान में जेंडर अध्ययनों को पुन: हासिल करना
शिवा अलीनाकियान, ईरान द्वारा 20

दबाव के अंतर्गत: ईरान पर समाजशास्त्रीय शोध
– एक राउंड टेबल
नफ़ीसेह आज़ाद, मराल लतीफ़ी और फ़तेमेह मोघदासी, ईरान; महबुबेह मोघदाम, यूएसए; लाडन रहबरी, नीदरलैंड; और रेज़ा सोहराबी, नाज़नीन शाहरोकनी, और रेहानेह जावदी, कनाडा के साथ 22

> राजनैतिक और सामाजिक अर्थव्यवस्था में श्रम प्रवासन

राजनैतिक और सामाजिक अर्थव्यवस्था में श्रम प्रवासन
कैरन शायर, जर्मनी, हेइडी गॉटफ्राइड और रीना अग्रवाल, यू.एस.ए. द्वारा 30

प्रवासन चुनौती में समाजशास्त्रीय योगदान
रीना अग्रवाल, यू.एस.ए. द्वारा 33

भारतीय राज्य सुरक्षित और व्यवस्थित माइग्रेशन की कल्पना कैसे करता है
इल अश्विन कुमार, यू.एस.ए. द्वारा 35

वैश्विक देखभाल श्रृंखलाओं पर पुनर्विचार:
वैश्विक दक्षिण की प्रवासी महिलाएँ
मारिया कैमिला वेगा–सालाजार, कैरोलीना मोरेनो, सूएलन कैस्तिब्लांको–मोरेनो, और हावियर ए. पिनेडा डी. कोलंबिया द्वारा 37

चीन और सिंगापुर में देखभाल श्रम प्रवासन का "मोबाइल डेवलपमेंटलिज्म"
लिन यू लिंग, और यूनहुई ये, कनाडा द्वारा 39

गैर–पश्चिमी प्रवासियों के लिए दुबई का विशिष्ट आकर्षण
अंजू मैरी पॉल, मुस्तफा यावाश, और सेजिन पार्क, यूएई द्वारा 41

चीन के शिक्षा–प्रवासी: देश में, विदेश में और वापसी के बाद
फेंग श्यू, कनाडा द्वारा 43

कंबोडियाई परिधान प्रवासी श्रमिक : अनिश्चितता और प्रतिरोध
ट्ज चूंग लाई एवं कैक्स्टन सियू, हांगकांग द्वारा 46

> खुला अनुभाग

उलझी हुई संचय प्रक्रिया के रूप में युद्ध: गाजा का मामला
गोंसाल्वेस, ब्राजील द्वारा 48

“जबकि राष्ट्रीय या क्षेत्रीय समाजशास्त्र सही मायने में प्रमुख प्रतिमानों को चुनौती देते हैं, वे उन बहिष्कारों को भी दोहरा सकते हैं जिनका वे विरोध करते हैं – संदर्भों को अनिवार्य बनाना या एक सार्वभौमिकता को दूसरे से बदलना।”

अब्दी काजेमीपुर

> विशिष्ट की अंधभक्ति, और धर्मनिरपेक्ष के रूप में पवित्र

अब्दी काजेमीपुर के साथ एक साक्षात्कार

अब्दी काजेमीपुर का चित्र श्रेयः अब्दी काजेमीपुर

हाल के वर्षों में 'राष्ट्रीय समाजशास्त्र', 'दक्षिणी सिद्धांत' और 'क्षेत्रीय परंपराओं' में बढ़ती रुचि के साथ, समाजशास्त्रीय ज्ञान उत्पादन की वैश्विक गतिशीलता पर बहस तेज हो गई है। ईरान इन चर्चाओं के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान करता है, जैसा कि कैलगरी विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर और नृजातीय अध्ययन के अध्यक्ष और कनाडाई समाजशास्त्रीय एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष **डॉ अब्दोलमोहम्मद (अब्दी) काजेमीपुर** के साथ एक साक्षात्कार में खोजा गया है। उनके हालिया कृत्य परीक्षण करते हैं कि आधुनिक ईरान में पवित्र और धर्मनिरपेक्ष कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और कैसे प्रवासन इसके सामाजिक परिदृश्य को पुनः आकारित कर रहा है। इस विस्तृत बातचीत में, डॉ. काजेमीपुर ईरानी समाजशास्त्र की स्थिति – इसकी चुनौतियों, योगदानों, और स्थानीय स्तर पर आधारित लेकिन वैश्विक रूप से जुड़े विषय की खोज पर विचार करते हैं। यहां उनका साक्षात्कार कनाडा के साइमन फ्रेजर विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन की एसोसिएट प्रोफेसर **डॉ. नाजनीन शाहरोकनी** द्वारा लिया गया है।

नाजनीन शाहरोकनी (एनएस): कई समाजशास्त्रियों ने "सार्वभौम" समाजशास्त्र के विचार को चुनौती दी है, और बताया कि जिसे लंबे समय से सार्वभौम के तौर पर दिखाया जाता रहा है, वह असल में यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी अनुभवों में निहित एक खास परंपरा है। इसके जवाब में, विशिष्टता की ओर रुख – राष्ट्रीय समाजशास्त्र, क्षेत्रीय दृष्टिकोण और दक्षिणी सिद्धांत के माध्यम से – वैकल्पिक ज्ञानमीमांसा को सामने लाने का प्रयास करता है। आप इस बदलाव को कैसे देखते हैं, और ईरानी संदर्भ में 'राष्ट्रीय समाजशास्त्र' की बात करने का क्या मतलब है?

अब्दी काजेमीपुर (एके): मुझे यह अंतर, डिस्क्रिप्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव, दोनों तरह से समस्यात्मक लगता है। जबकि राष्ट्रीय या क्षेत्रीय समाजशास्त्र सही मायने में प्रमुख प्रतिमानों को चुनौती देते हैं, वे उन बहिष्कारों को भी दोहरा सकते हैं जिनका वे विरोध करते हैं – संदर्भों को अनिवार्य बनाना या एक सार्वभौमिकता को दूसरे से बदलना। सार्वभौमिकतावाद के खिलाफ बहस करना अब अविवादास्पद है, लेकिन हम एक नए 'विशिष्ट की अंधभक्ति' के प्रति जुनून" का खतरा उठा रहे हैं।

सबसे पहले, हर "विशिष्ट" में अंदरूनी विविधता होती है। इसकी सभी उप–श्रेणियों के लिए बोलने का दावा करना वही गलती दोहराता है जो सार्वभौमिकतावाद में होती है। ईरान और तुर्की – जो सीधे तौर पर उपनिवेश नहीं हैं – को आसानी से अल्जीरिया, भारत या मिस्र जैसे पूर्व उपनिवेशित देशों के साथ समूहीकृत नहीं किया जा सकता है, और यहां तक कि अरब मध्य पूर्व के भीतर भी, जैसा कि सारी हनफी ने उल्लेख किया है, क्षेत्र के पूर्वी और पश्चिमी भाग स्पष्ट रूप से भिन्न हैं।

दूसरा, 'राष्ट्रीय समाजशास्त्र' या दक्षिणी सिद्धांत को मुख्य रूप से उत्तरी प्रतिमानों के विरोध के तौर पर दिखाना अक्सर ज्ञानमीमांसीय

>>

लक्ष्यों से ज्यादा पहचान–केंद्रित राजनीतिक लक्ष्यों को पूरा करता है। इससे उन प्रतीकात्मक चरित्रों को बढ़ावा मिल सकता है जिनकी क्रांतिकारी अपील समय के साथ फीकी पड़ जाती है। उदाहरण के लिए, रेविन कॉनेल ने ईरान की 1979 की क्रांति से पहले अली शरीयती को पश्चिमी सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के खिलाफ एक प्रमुख आवाज के रूप में उद्धृत किया है। फिर भी, जल्द ही उनका बौद्धिक असर कम हो गया, जिससे पता चलता है कि पहचान के दावे राजनीतिक रूप से तो लामबंद हो सकते हैं, लेकिन समाजशास्त्रीय ज्ञान के लगातार विकास में उनका कोई खास योगदान नहीं होता।

एनएसः किसी विशिष्ट के लिए अंधभक्ति को लेकर आपकी चिंताओं को देखते हुए, क्या आपको लगता है कि हमें राष्ट्रीय समाजशास्त्र के विचार को पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए? क्या "ईरानी समाजशास्त्र" जैसी कोई अवधारणा विश्लेषणात्मक रूप से उपयोगी है, या क्या यह उस ज्ञानमीमांसीय खाई को और मजबूत करने का जोखिम उठाता है जिन्हें यह दूर करना चाहता है?

एके: राष्ट्रीय समाजशास्त्र अस्तित्व में हैं और होने भी चाहिए, लेकिन सैद्धांतिक अन्तः क्षेत्र के तौर पर नहीं। उनका मूल्य विशिष्ट सिद्धांतों या तरीकों को प्राप्त करने में नहीं है, बल्कि अपने समाज की खास परिस्थितियों में स्थित विशिष्ट प्रश्न पैदा करने में है। "अच्छा" समाजशास्त्र साफ तौर पर तय, स्थानीय प्रश्नों से शुरू होता है; और उनके जवाब देने के लिए सभी मौजूद बौद्धिक स्त्रोत – उत्तरी या दक्षिणी, पूर्वी या पश्चिमी – का इस्तेमाल करना होता है, बिना किसी पहले से तय बात को गलत ठहराए। ऐसे उत्तर विचारों और यथार्थ के मध्य बातचीत की लम्बी प्रक्रिया और बौद्धिक परंपराओं के मध्य लेन–देन से निकलते हैं। इसलिए हमें सैद्धांतिक अज्ञेयवाद और सारसंग्रहवाद का अभ्यास करना चाहिए – विशिष्ट सिद्धांतों को पवित्र मानने या खारिज करने के बजाय बहुल परम्पराओं से अवधारणाओं को अपनाना चाहिए।

एनएसः मैं दो सवाल पूछना चाहती हूँ। आप कहते हैं कि राष्ट्रीय समाजशास्त्र का मूल्य विशिष्ट सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के बजाय उनके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों में है। लेकिन जैसा कि नारीवादी समाजशास्त्रियों ने लंबे समय से तर्क दिया है, कोई तटस्थ दृष्टिकोण नहीं है; हम जो सवाल पूछते हैं, वे हमारे पास उपलब्ध वैचारिक उपकरणों और विश्लेषणात्मक लेंसों से निर्धारित होते हैं। हावी प्रतिमान कुछ सवालों को पूछे जाने से भी रोक सकते हैं। उस नजरिए से, राष्ट्रीय या क्षेत्रीय समाजशास्त्र सिर्फ स्थानीय प्रश्न पूछने के बारे में नहीं हैं, बल्कि ऐसे वैकल्पिक फ्रेमवर्क विकसित करने के बारे में भी हैं जो नई तरह की जांच को मुमकिन बनाते हैं। आप इस पर किस प्रकार प्रतिक्रिया करते हैं?

एके: मैं सहमत हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यह दोनों तरह से काम करता है। जैसे तथाकथित "सार्वभौमिकता" परिपेक्ष्य हमारे पूछे जा सकने वाले प्रश्नों को सीमित कर सकते हैं, वैसे ही "राष्ट्रीय" परिपेक्ष्य भी जांच की अन्य रेखाओं को रोक सकते हैं। यह तनाव खास तौर पर नारीवादी विद्वत्ता में स्पष्ट देखा गया है। हालांकि वैश्विक उत्तर में नारीवादी के कुछ हिस्सों के सार्वभौमिक रुख ने अक्सर उन्हें दक्षिण से उभरने वाली दूसरी समस्याओं और सैद्धांतिक संभावनाओं के प्रति अंधा कर दिया है, दक्षिण में ज्यादातर नारीवादी जागरूकता असल में उत्तर में मौजूद नारीवादी एजेंडा से जुड़ने से बनी है। यही कारण है कि अलग–अलग नजरियों के बीच लगातार और एक्टिव बातचीत जरूरी है।

एनएसः चूँकि आप इस बात पर जोर देते हैं कि राष्ट्रीय समाजशास्त्र उन प्रश्नों से उभरता है जो वे उठाते हैं, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, क्या आप उन प्रश्नों और थीम के बारे में बता सकते हैं जिन्होंने हाल के दशकों में ईरानी समाजशास्त्र को परिभाषित किया है?

एके: पिछले 50–60 सालों में ईरानी समाज में बहुत बड़े बदलाव आए हैं, जिन्होंने समाजशास्त्रियों के प्रश्नों को आकारित किया है। इनमें पूर्व–क्रांति काल में तेजी से राज्य के नेतृत्व में आधुनिकीकरण और धर्मनिरपेक्षता शामिल है; 1979 की इस्लामिक क्रांति के दौरान धर्म का एक ताकतवर राजनैतिक और निजी ताकत के तौर पर अचानक उभरना, जिसने ईरान–इराक युद्धः जो बीसवीं सदी का सबसे लंबा युद्ध था, में लगभग 10 प्रतिशत आबादी को इकट्ठा किया।

हाल के दशकों में दोनों तरह के धर्मनिरपेक्षीकरण – या तो धर्म को पूरी तरह से छोड़ देना या संस्थाओं, रीति–रिवाजों, पादरी संस्तरण और धर्मशास्त्र से मुक्त एक निजीकृत आध्यात्मिकता को अपनाना – एक तरह का धर्मनिरपेक्षीकरण जिसमें धर्म सरकार के अधीन है; यह तेजी से हो रहे इस्लामीकरण के तहत उनके मिलने का एक अनचाहा नतीजा है।

ईरान का भी एक अनूठा प्रवासन प्रोफाइल है : यह प्रवासी प्रेषित करने वाला और प्रवासी–प्राप्त करने वाला देश दोनों है, जिसमें लगभग 450 लाख शरणार्थी (आबादी का लगभग 5%) रहते हैं, जबकि लगभग 80 लाख ईरानी विदेश में रहते हैं (लगभग 9%)। सर्वेक्षण बताते हैं कि यदि संभव हो तो आधी से ज्यादा आबादी उत्प्रवास कर जाएगी, जिससे ईरान अप्रवासन और उत्प्रवासन दोनों का एक साथ अध्ययन करने वाला एक दुर्लभ मामला बन जाता है।

अंततः, व्यवस्थागत लैंगिक असमानताओं और सांस्कृतिक पितृसत्तात्मकता के प्रत्युत्तर में एक शक्तिशाली और प्रामाणिक महिला आंदोलन उभरा है जिसने देश में सामाजिक आन्दोलनों की प्रकृति, क्षेत्र और मांगों को पुनः आकारित किया है। इन दिलचस्प और परस्पर काटती हुई गतिशीलता – वैचारिक परिवर्तन, धार्मिक परिवर्तन, युद्ध, प्रवास और लिंग – ने ईरान के अंदर और ईरानी प्रवासी के बीच, खासकर प्रवासन, पहचान, जेंडर और सामाजिक पूंजी के समाजशास्त्र में, जोरदार समाजशास्त्रीय अन्वेषण को बढ़ावा दिया है।

एनएसः इस गतिशील इतिहास को देखते हुए, आज ईरान में समाजशास्त्र के विकास में आपको सबसे बड़ी रुकावटें क्या लगती हैं, और ये चुनौतियाँ उन प्रश्नों को कैसे आकार देती हैं जो पूछे या नहीं पूछे जा सकते हैं?

एके: सबसे बड़ी चुनौती सरकार की आजादी से जांच पर रोक है। सामाजिक समस्याओं के जाने–माने समाजशास्त्री, डॉ. सईद मदनी, अभी जेल में हैं; फ्रांस निवासी मानवविज्ञानी डॉ. फरीबा अदेलखाह, रिहा होने से पहले कई साल जेल में रहीं। कई औरों को विश्विद्यालयों से निष्कासित कर दिया गया है, फिर भी वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।

ईरानियों की बौद्धिक कल्पना में राज्य और "राजनीतिक" की निरंतर प्रधानता, जिसमें कई सामाजिक वैज्ञानिक भी शामिल हैं, इससे बहुत करीब से जुड़ा हुआ है। पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति और अपनाई जाने वाली विश्लेषणात्मक दिशाओं को सीमित करते हुए इस चिंता ने स्वयं 'सामाजिक' पर ही ग्रहण लगा दिया है।

>>

विशेष रूप से, ऐसी स्थिति में, जब राज्य उम्मीद के मुताबिक काम करने को तैयार नहीं है या असमर्थ है, तो समुदाय सशक्तिकरण या स्थानीय स्तर पर की जाने वाली पहलों पर शोध की कमी है।

एक और बाधा दोहरी बीमारी है; गैर–सैद्धांतिक आनुभविक काम के साथ जुड़ा सिद्धांत के प्रति अति–आकर्षण – लगभग अंधभक्ति, जिसे सी. राइट मिल्स ने "अमूर्त अनुभववाद" कहा था। ईरानी समाजशास्त्र को अधिक सिद्धांत–चलित आनुभविक शोध की आवश्यकता है जो जमीनी और अवधारणात्मक रूप से मजबूत दोनों हो।

अंततः, ईरानी समाजशास्त्र वैश्विक समाजशास्त्र और तुलनात्मक शोध से काफी हद तक अलग–थलग है – यहां तक कि तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब जैसे क्षेत्रीय और/या ऐतिहासिक रूप से तुलनीय संदर्भों के साथ भी।

यह कहने के बाद भी, उभरते तरीके ईरानी समाजशास्त्र को व्यापक बौद्धिक संवाद से जोड़ रहे हैं। ईरान के बाहर रहने वाले युवा, अक्सर दूसरी पीढ़ी के अप्रवासी समाजशास्त्रियों का बढ़ता समूह ईरानी समाज के अध्ययन में नई ऊर्जा और जिज्ञासा लाता है। हालांकि उनके काम को कभी–कभी रोमांटिक तरीके से देखा जाता है, लेकिन ईरान की सामाजिक सच्चाई को दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचाने और इस क्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय पहचान बढ़ाने में उनका काम बहुत जरूरी रहा है। दूसरा ईरान में चल रहा अनुवाद आंदोलन है, जिसने शास्त्रीय और समकालीन समाजशास्त्रीय कृत्यों को बहुत तेजी से फारसी में उपलब्ध कराया है। इसने स्थानीय अकादमिक विमर्श को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है और ईरानी विद्वानों को वैश्विक बहसों से अवगत कराया है – हालांकि अभी भी यह योगदान के बजाय स्वागत के स्तर पर है।

एनएसः यह अनुवाद आंदोलन अवश्य प्रभावशाली है, लेकिन यह एक गहरी असमानता को भी उजागर करता है; अनुवाद का बहाव ज्यादातर एकतरफा रहता है। ईरान के बाहर लिखे कृत्य – विशेषकर अंग्रेजी – फारसी में अनुवादित किए जाते हैं, जबकि फारसी में छपा बहुत कम समाजशास्त्रीय कार्य का विदेश में अनुवादित किया जाता है, और न ही ईरान के भीतर अरबी, तुर्की, कुर्द या अन्य क्षेत्रीय समाजशास्त्रों को अधिक अपनाया जाता है। यह भाषायी और ज्ञानमीमांसीय असंतुलन व्यापक प्रश्न उठाता है। इसे ध्यान में रखते हुए, आप वैश्विक दक्षिण के समाजशास्त्र के बड़े प्रोजेक्ट में ईरान की जगह को कैसे देखते हैं, और खासकर मध्य–पूर्व समाजशास्त्र के संबंध में?

एकेः आप सही कह रहे हैंः यह एकतरफा बहाव ईरानी समाजशास्त्र के लिए ठीक नहीं है। इस इलाके और उससे बाहर अपने साथियों के साथ ज्यादा व्यवस्थित, नियमित सम्बन्ध बनाकर ईरानी समाजशास्त्रीय संघ मदद कर सकते हैं, जिससे दोनों तरफ को फायदा होगा।

जैसा कि माइकल बुरावॉय ने तर्क दिया है, निजी पहचान की तरह राष्ट्रीय समाजशास्त्र, संबंधों से बनता है और दूसरों के साथ जुड़ने से खुद को समझ पाते हैं। उनके शब्दों मेंः "हम अब किसी भी विशेष – चाहे वह अमेरिका हो या फ्रांस, इंसान हों या उपनिवेशवादी – को सार्वभौम के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं। तथापि, हम असम्बद्ध विशेषों के दलदल में वापस नहीं जा सकते हैं। वैश्विक समाजशास्त्र को विशेषों के मध्य संवाद पर निर्माण करना होगा।"

मिशेल फूको की की बात को थोड़ा घुमाते हुए कहें तो, समाजशास्त्र का भविष्य मुठभेड़ की जगहों पर है – जहाँ यूरोप और गैर–यूरोप, पश्चिम और पूरब, उत्तर और दक्षिण, और हर एक के अलग–अलग हिस्से मिलते हैं और एक–दूसरे को परेशान करते हैं। उस भविष्य में ईरानी समाजशास्त्र का योगदान एक ऐसे विषय को विकसित करने पर निर्भर करता है जो असली, सन्दर्भ–विशिष्ट प्रश्नों पर आधारित होः न तो बाहर से लाए गए सैद्धांतिक प्रारूप में फंसा हो और न ही देश के राष्ट्रीय अपवादवाद तक सीमित हो। ■

संपर्क करेंः
नाजनीन शाहरोकनी <nazanin_shahrokni@sfu.ca>

> दमन और प्रासंगिकता के बीच:

ईरान के नजरिए से समाजशास्त्र पर पुनर्विचार

नाजनीन शाहरोकनी, साइमन फ्रेजर विश्वविद्यालय, कनाडा और **रेहानेह जावदी**, अल्बर्टा विश्वविद्यालय, कनाडा द्वारा

ईरान के समाजशास्त्र पर यह संगोष्ठी ऐसे समय में सामने आई है, जब देश में ज्ञान के सृजन पर असाधारण दबाव है। ईरानी समाजशास्त्र लंबे समय से अपनी सार्वजनिक भूमिका को लेकर होने वाली बहसों से जीवंत रहा है – कि क्या इसे एक आलोचनात्मक आवाज़ के रूप में काम करना चाहिए, सामाजिक संकटों के लिए एक नैदानिक उपकरण बनना चाहिए, या राज्य और समाज के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका निभानी चाहिए। हालाँकि, आज वह ज़मीन, जिस पर ये बहसें होती हैं, नाटकीय रूप से सिकुड़ गई है। राजनीतिक दमन, एक खंडित सार्वजनिक दायरे में असहमति रखने वाली अकादमिक आवाज़ों को चुप कराना, आर्थिक अस्थिरता, वैश्विक प्रतिबंध, और आवाजाही तथा वीज़ा संबंधी कड़े नियम – इन सबने मिलकर उन संस्थागत और बौद्धिक ढाँचों को कमज़ोर कर दिया है, जो विद्वतापूर्ण जीवन को बनाए रखते हैं। विश्वविद्यालय कड़े राजनीतिक प्रतिबंधों के तहत काम कर रहे हैं, शोध के लिए धन की कमी है, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। फिर भी ईरानी समाजशास्त्र कायम है; इसे उन विद्वानों का सहारा मिला हुआ है, जो अपने समाज को आकार देने वाले गहरे बदलावों का विश्लेषण, दस्तावेज़ीकरण और उन पर चर्चा करना जारी रखे हुए हैं।

जब हम इस संगोष्ठी की तैयारी कर रहे थे, तो इस परिदृश्य की अस्थिरता को नज़रअंदाज़ करना असंभव हो गया था। ईरान संकटों की एक ऐसी शृंखला से गुज़रा, जिसने अकादमिक जीवन और ज्ञान के सृजन की अनिश्चितता को उजागर कर दिया। जून 2025 में, इज़रायल ने ईरान पर बारह दिनों का युद्ध छेड़ दिया, और पूरे देश में सैन्य तथा नागरिक ढाँचे पर हमले किए। महीनों बाद, जनवरी 2026 में विद्रोह भड़क उठे, जिनका सामना राज्य के क्रूर दमन से हुआ, जिसमें हज़ारों नागरिक मारे गए। इन विरोध प्रदर्शनों और राज्य की हिंसक प्रतिक्रिया को ईरानी समाजशास्त्रीय संघ ने न तो अभूतपूर्व बताया और न ही अप्रत्याशित। संघ ने चेतावनी दी कि सामान्य हो चुकी हिंसा सामाजिक एकजुटता और मानवीय गरिमा के लिए खतरा है। इस संदर्भ में, समाजशास्त्र और भी अधिक – कम नहीं – आवश्यक हो जाता है; यह संकटों का दस्तावेज़ीकरण करने, उनकी संरचनात्मक जड़ों की व्याख्या करने, और संभावित भविष्य के बारे में सार्वजनिक चर्चा को बनाए रखने का एक माध्यम बन जाता है।

फिर भी, इन सीमित परिस्थितियों को और भी अधिक कमज़ोर कर दिया गया है। जब यह संगोष्ठी प्रकाशन के लिए जा रही है, ठीक उसी समय अमेरिका और इज़रायल के समन्वित सैन्य हमलों के एक नए दौर ने पूरे देश में फिर से नागरिकों को अंधाधुंध तरीके से मार डाला है। पीड़ितों में 12 वर्ष से कम उम्र की 100 से अधिक स्कूली छात्राएँ भी शामिल हैं, जो मिनाब नामक दक्षिणी शहर के एक छोटे से प्राथमिक विद्यालय पर हुए एक विनाशकारी हमले में मारी गईं। इन बमबारी हमलों ने बुनियादी ढाँचे को और भी अधिक तबाह कर दिया है, जिससे पहले से ही नाजुक संस्थागत परिदृश्य की स्थिति और भी बिगड़ गई है; साथ ही, इसने उन बौद्धिक नींवों को भी खतरे में डाल दिया है, जिन्हें ईरानी समाजशास्त्रियों की कई पीढ़ियों ने बड़ी मेहनत से बनाया और सँवारा था।

कुल मिलाकर, ये घटनाक्रम उस परिदृश्य को दर्शाते हैं जिसमें ईरान में समाजशास्त्र को काम करना है। विद्वानों को एक ही समय में कई दिशाओं से दबावों का सामना करना पड़ता है – एक ओर घरेलू दमन है जो बौद्धिक स्वायत्तता और सार्वजनिक बहस को सीमित करता है, तो दूसरी ओर बाहरी सैन्य और आर्थिक दबाव हैं जो उन संस्थाओं को और भी अधिक अस्थिर कर देते हैं जिन पर विद्वत्तापूर्ण जीवन निर्भर करता है। इस प्रकार, यह संगोष्ठी न केवल ईरानी समाज पर, बल्कि उन परिस्थितियों पर भी विचार करती है

>>

जिनके तहत समाजशास्त्र को स्वयं भी कायम रहना है और अपनी बात कहनी है।

> ईरान के अंदर और बाहर, दोनों जगह मजदूरों और अवसंरचना पर बार–बार हमले हो रहे हैं

इन हालातों की नाजुकता शायद ईरानी समाजशास्त्र संघ के कमजोर भौतिक अस्तित्व में सबसे ज्यादा दिखती है। तेहरान विश्वविद्यालय में इसका आधिकारिक कार्यालय सरकार की जांच के दायरे में रहता है और यह संघ की स्वायत्ता पर लगातार दबाब डालता है। एक स्वतंत्र और स्थायी स्थान पाने की अवरोधित कोशिशें समाजशास्त्रीय और सार्वजनिक जीवन के व्यापक संकुचन को और दिखाती हैं। ये संस्थागत अनिश्चितताएं विद्वानों, अनुवादकों और शोधकर्त्ताओं को लक्षित करने वाली गिरफ्तारियों की आवर्ती लहरों के साथ साथ सामने आती हैं, जो न सिर्फ लोगों को बल्कि महत्वपूर्ण सोच को बनाए रखने वाली अवसंरचना को भी कमजोर करती हैं। इन हालातों में, समाजशास्त्रीय कार्य में अक्सर काफी निजी जोखिम होता है। इन दबावों की जड़ें बहुत पुरानी हैंः समाजशास्त्र को लंबे समय से विचारात्मक रूप से संदिग्ध माना जाता रहा है, जिसे बारम्बार बार–बार इस्लामीकरण, विषयगत "सफाई" और आग्रही प्रतिभूतिकरण के अधीन किया गया है।

ये विरोधाभास ईरान की सीमाओं से भी आगे तक विस्तृत होते हैं। ईरानी अमेरिकी और दूसरे प्रवासी विद्वान यात्रा और सह–कार्य को सीमित करने वाले अतिव्यापी सुरक्षा तर्क का सामना करते हुए ईरान और पश्चिमी शैक्षणिक संस्थानों दोनों में बढ़ती निगरानी और गतिशीलता की दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। ईरान के भीतर समाजशास्त्र को चिन्हित करने वाला संशय ईरान के बाहर भी भी तेजी से छाया हुआ है।

> लचीलेपन के अप्रत्याशित रूप

फिर भी, ये दबाव जरूरी बदलावों के साथ मौजूद हैं। 2025 में ईरानी समाजशास्त्रीय संघ की पहली महिला अध्यक्ष के तौर पर डॉ. शिरीन अहमदनिया के निर्वाचन ने कई प्रतिक्रियाओं को प्रारम्भ किया। इसने महिलाओं के समाजशास्त्रीय कार्य को देर से पहचान मिलना और ऐतिहासिक रूप से एक पुरुष संस्थागत स्थान, एक ऐसा विषय, जिसे अब ज्यादातर महिला विद्यार्थी चलाती हैं, को पुनः बनाने की संभावना दोनों का संकेत दिया। संस्थागत अनिश्चितता के मध्य ऐसे चुनाव का होना अपने आप में बताता है: भले ही संरचना कमजोर हों, लेकिन दृश्यता और सत्ता के नए दावे सामने आते हैं। इस तनाव के मध्य ईरानी समाजशास्त्र ने लचीलेपन के अप्रत्याशित स्वरुप विकसित किये हैं, जैसे विद्वान और छात्र विश्विद्यालयों, निजी संस्थानों, पढ़ने के समूह, प्रवासी नेटवर्क्स के पार विचार और बहस के लिए स्थान बना रहे हैं।

> इस संग्रह का उद्देश्य और एक ह्यूरिस्टिक सहायता

इस संग्रह के दो मकसद हैं। यह ईरानी समाजशास्त्र की बौद्धिक ताकत और इसके काम में आने वाली रुकावटों, दोनों को सामने लाता है, और और इन बहसों को शक्ति की असमान भौगोलिकता से जुड़े वैश्विक ढांचे के द्वारा समाजशास्त्र पर पुनर्विचार करने के व्यापक विषयगत प्रयासों के अंतर्गत रखता है।

एक ह्यूरिस्टिक मार्गदर्शक के तौर पर, हम ईरान में समाजशास्त्र और ईरान के समाजशास्त्र के बीच अंतर बताते हैं य एक भौगोलिक युग्मक के रूप में नहीं, बल्कि, इस क्षेत्र को आकार देने वाले ज्ञानमीमांसीय, पद्धतिगत, और राजनैतिक दरारों के अंकन के रूप में।

> समाजशास्त्र में और समाजशास्त्र का – संदर्भों में परिसंचरण

ईरान में समाजशास्त्र से हमारा मतलब उन विविध पेशेवर, शैक्षणिक और शोध अभ्यासों से है जो ईरान के विश्वविद्यालयों, संघों, निजी संस्थाओं और अनौपचारिक बौद्धिक नेटवर्क में आकारित होते हैं। इनमें न सिर्फ समाजशास्त्रीय ज्ञान का उत्पादन सम्मिलित है, बल्कि एक ओजस्वी अनुवाद उद्योग, सार्वजनिक भाषण, कार्यशालाओं, और अर्ध–स्वतंत्र शिक्षण स्थान के माध्यम से इसका परिसंचरण भी शामिल है, जो औपचारिक संस्थाओं से परे समाजशास्त्रीय संलग्नता को बनाए रखता है। ये व्यवहार सेंसरशिप, निगरानी, वैचारिक जांच, आर्थिक मितव्यतता और अंतर्राष्ट्रीय संस्थागत गेटकीपिंग के हालात में सामने आते हैं, जिसमें भाषा, इज्जत और भू–राजनैतिक रुकावटें शामिल हैं: वे रुकावटें जो आलोचनात्मक जांच को जोखिम और असमान बनाती हैं, फिर भी सह–कार्य, शिक्षण और सार्वजनिक बहस के लिए नवाचारी रणनीतियां भी बनाती हैं।

ईरान के समाजशास्त्र से हमारा मतलब उस विद्वता से है जो ईरान – इसकी सामाजिक संरचना, इतिहास और राजनैतिक अर्थव्यवस्था – चाहे वह देश के अंदर हो या बाहर, को समझने की कोशिश करती है। इस काम का ज्यादातर हिस्सा वैश्विक शैक्षणिक ढांचे में घूमता है और यह मुख्य विषयगत दर्शक के लिए "पठनीयता" की उम्मीदों से बनता है। ये दबाव ईरान के भीतर से उभरने वाली अवधारणाओं, प्राथमिकताओं और ज्ञानमीमांसीय शब्दकोष को दरकिनार कर सकते हैं, चाहे वे बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय दृश्यता और बहस को सुगम बना रहे हों।

खास बात यह है कि ये रुझान कोई तय क्षेत्र या विरोधी श्रेणियाँ नहीं हैं। विचार, पुरालेख, और पद्धतिगत समझ राजनीतिक और संस्थागत रुकावटों के बावजूद सीमाओं के पार फैलती है। अपने पेशे के दौरान विद्वान इन स्थितियों के मध्य घूमते रहते हैं और उनके कार्य पहुँच, अवरोध, और दर्शकों के बदलते संयोजन से आकारित होते हैं।

> दुनिया भर में शक के घेरे में और पाबंदियों से मजबूर

फिर भी दर्शनीयता, संसाधनों, और संस्थागत पहचान की असमानता महत्वपूर्ण बनी रहती हैं। ईरान के अंदर शोधकर्त्ता सेंसरशिप, निगरानी और सामग्री की अनिश्चितता से जूझते हैं; बाहर शोध करने वाले पाबंदियाँ, वीजा पाबंदियों और पश्चिमी संस्थानों की अनुशासनात्मक नजर का सामना करते हैं। कई प्रवासी विद्वानों के लिए, इसका अर्थ है दोनों स्थानों पर संदिग्ध माना जाना – ईरान में निगरानी और उत्तरी अमेरिका या यूरोप में छानबीन – इस तरह से कि जो अध्ययन, लेखन और साझा किया जा सकता है, उस पर भौतिक रूप से प्रभाव पड़ता है।

भू–राजनीति से ये दरारें और बढ़ जाती हैं। ईरान में रहने वाले विद्वानों के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों ने वैश्विक अकादमिक नेटवर्क में भाग लेना, पेशेवर संघों को फीस देना और संगोष्ठी में भाग लेना मुश्किल, कभी कभी असंभव बना दिया है। कभी सार्वजनिक बहस का एक मजबूत केंद्र रहा ईरानी समाजशास्त्रीय संघ, अब आर्थिक तनाव और संस्थागत दबाब के कारण बुनियादी कामों को भी बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। ये अपवर्जन न सिर्फ ईरानी समाजशास्त्र को बाधित करते हैं, बल्कि वे प्रतिबंधित, निगरानी में और संरचनात्मक रूप से हाशियेकृत सन्दर्भों से आवाजों की गैर–मौजूदगी को सामान्य करते हुए वैश्विक समाजशास्त्र को भी कमतर करते हैं।

>>

> ज्ञानात्मक, पद्धतिगत और संस्थागत तनाव

इस संगोष्ठी में योगदान इन मुश्किलों को कई नजरिये से देखते हैं। कुछ लोग उन संस्थागत हालातों की जांच करते हैं जिनमें समाजशास्त्र का अभ्यास होता है; अन्य बुनियादी ज्ञान से जुड़े सवालों की जांच करते हैं; और अब्दुलमोहम्मद काजेमीपुर के साथ साक्षात्कार ईरानी बहसों को विशिष्टता और सार्वभौमिकता पर व्यापक सैद्धांतिक बहस के मध्य रखता है।

अधिल दघाघेलेह और शिवा अलीनाकियान के निबंध नृजातीयता और जेंडर के आस–पास की ज्ञान–मीमांसा वाली चुप्पी को दिखाते हैं, और बताते हैं कि कैसे एक हावी नियामक केंद्र – जो जेंडर, नृजातीयता और वर्ग के क्रम से बनता है – ने लंबे समय से ईरानी समाजशास्त्र को बनाया है, और बाहरी और नारीवादी परिपेक्ष्य को हाशिए पर या संदिग्ध के तौर पर रखा है। अपवर्जन केवल बौद्धिक नहीं बल्कि संस्थागत भी हैं। जैसा कि इस्माइल खलीली दिखाते हैं, ईरानी समाजशास्त्र संघ 'गैर–संस्थाकरण का संस्थाकरण' दिखाता है; संगठनात्मक जीवन का एक स्वरुप जिसमें समाजशास्त्र को संस्थागत करने की आकांक्षा बनी रहती है, चाहे उसे पोषित करने वाली संरचनाओं को निरंतर कमजोर किया जा रहा हो। उनका विश्लेषण इस विरोधाभास को उजागर करता है कि, जहाँ क्षेत्र की अधिकांश ऊर्जा टिकाऊ संस्थागत स्वरूपों निर्माण की तरफ निर्देशित होती है, यही कोशिशें उन स्थितियों में खुलती हैं जो असली स्वायत्ता तो बाधित करती हैं और उन सीमाओं का पुनरुत्पादन करती हैं जिन्हे पार करना चाहते हैं।

निजीकरण पर कार्य में भी इसी प्रकार का तनाव उभरता है; रेहानेह जावदी और जोहरेह बयात्रिजी दिखाते हैं कि कैसे समाजशास्त्र का निजीकरण, जिसे शुरू में अकादमिक स्वायत्ता के अभाव में आंशिक उपाय के तौर पर देखा गया था, ने शिक्षा को एक लोक हित की वस्तु न मान कर इसे साख बाजार में परिवर्तित कर वस्तुकरण के नव–उदारवादी तर्क को गहरा कर दिया है।

"बाधाओं के अंतर्गतः ईरान पर समाजशास्त्रीय शोध" पर राउंडटेबल में जिन पद्धतिगत संघर्षों पर बात हुई, वे इस विश्लेषण को शोध के दैनिक अभ्यास में भी शामिल करते हैं। क्षेत्रीय कार्य की सीमाओं और अपारदर्शी नैतिक प्रक्रियायों से लेकर अपराधीकरण के खतरे तक, प्रतिभागी दिखाते हैं कि कैसे राजनैतिक माहौल – जहाँ चाहे ईरान में या प्रवासी और संस्थागत सेटिंग्स में ईरान का अध्ययन किया जाता है – न सिर्फ यह तय करते हैं कि क्या जांचा जा सकता है, बल्कि यह भी कि आंकड़ों को कैसे एकत्रित, संग्रहित और फैलाया जा सकता है।

> उभरते परिवर्तनकारी तरीके और संलग्नता के नवाचारी तरीके

फिर भी, यह संगोष्ठी उन संभावनाओं पर भी रोशनी डालता है जो पाबंदियों के अंदर और उनके खिलाफ बनती हैं। सरकारी संस्थाओं में हाशिये पर होने के बावजूद नारीवादी विद्वान जेंडर, धर्म और राज्य शक्ति का तीक्ष्ण विश्लेषण करते रहते हैं। इस बात पर जोर देते हुए कि नृजातीय भिन्नता को राज्य निर्माण, सम्प्रभुता और दैनिक प्रतिरोध के इतिहास के अंतर्गत स्थित होना चाहिए, नृजातीयता पर कार्य राष्ट्रवादी रूढ़िवादिता के विरुद्ध दबाब डालता है।

अपनी असुरक्षित जगह और सरकारी विश्वविद्यालयों या नगरपालिका गुडविल पर निर्भरता के बावजूद – ईरानी समाजशास्त्रीय संघ कॉन्फ्रेंस, प्रकाशन और सार्वजनिक–अभिमुखन के कार्य के लिए मंच प्रदान करना जारी रखता है। निजी और अध्र्ध–निजी समाजशास्त्र कक्षाएं संकर शिक्षण स्थान का निर्माण करती हैं जो विरोध और नव–उदारवादी पुनरुत्पादन के बीच झूलती रहती हैं। इन सभी सन्दर्भों में, समाजशास्त्री सीमाओं को पद्धति और अवधारणात्मक नवाचार में बदल देते हैं।

एक साथ मिलकर, ये सभी योगदान एक ऐसे क्षेत्र को उजागर करते हैं जो विविध और संलग्नता के नवाचारी तरीकों के साथ जटिल, बहु–स्तरीय बाधाओं से चिन्हित है। वे दिखाते हैं कि यह क्षेत्र संरचनात्मक दबाबों और विद्वानों द्वारा टिकने, सामंजस्य बनाने वाले और दखल देने वाले युक्ति–संपन्न व्यवहारों के अंतर्संबंध से पुनर्निर्मित होता है।

> ईरान के साथ समाजशास्त्र की ओर

इस संगोष्ठी का मकसद ईरानी समाजशास्त्र को पूरी तरह से मैप करना नहीं है, बल्कि इन दबावों को विषयगत सवालों के एक बड़े कुलक के अंदर रखना है। ईरान में/ईरान के समाजशास्त्र के सामने जो मुश्किलें हैं, वे वैश्विक दक्षिण के बड़े पैटर्न से मेल खाती हैं, जहाँ समाजशास्त्री तानाशाही शासन, बाजार के दबाव और ज्ञान के वैश्विक सर्किट तक असमान पहुँच से जूझते हैं। इन हस्तक्षेपों को एकत्रित करके, हम न केवल इन चुनौतियों को डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं, बल्कि पाठकों को इस विषय के लिए मिलने वाली अवधारणात्मक और पद्धतिगत अंतर्दृष्टि पर और बड़े पैमाने पर विचार करने के लिए भी आमंत्रित करना चाहते हैं। इस मायने में, ईरानी समाजशास्त्र की कहानी खुद समाजशास्त्र की कहानी बन जाती है; इसकी सीमाएँ, इसकी संभावनाएँ, और उन समाजों के प्रति उत्तरदायी बने रहने का इसका लगातार संघर्ष जहाँ से यह निकला है।

इसलिए, हम जो प्रस्ताव देते हैं, वह ईरान के साथ समाजशास्त्र की ओर एक इशारा है: सहयोग, आपसी लेन–देन और परिवर्तनीयता पर आधारित जुड़ाव का एक तरीका। यह दृष्टिकोण ईरानमें समाजशास्त्र और ईरान के समाजशास्त्र के बीच के तनाव को दूर नहीं करता है, बल्कि यह उनके जरिए और उनके पार काम करने पर जोर देता है। यह ईरानी समाजशास्त्र को विषय के वैश्विक प्रक्षेपपथ पर पुनर्विचार करने और समाजशास्त्रीय ज्ञान के उत्पादन और प्रसार को आकार देने वाले बहिष्करणों को चुनौती देने के लिए केंद्रीय – परिधीय नहीं – के रूप में मान्यता देता है।

ऐसा नजरिया ईरानी समाजशास्त्र को बाहरी जांच का मामला या चीज मानने से रोकता है। इसके बजाय, यह इस बात पर जोर देता है कि ईरानी समाजशास्त्रियों के बौद्धिक श्रम, संस्थागत संघर्ष और पद्धति सम्बन्धी नवाचार समाजशास्त्र में बहुत जरूरी योगदान देते हैं। ऐसे समय में जब ईरानी आवाजों को अंतर्राष्ट्रीय मंच से व्यवस्थित तरीके से बाहर रखा जा रहा है, ईरान के साथ समाजशास्त्र का निर्माण करना वैषयिक न्याय के लिए भी आवश्यक है। ■

संपर्क करें:
नाजनीन शाहरोकनी <nazanin_shahrokni@sfu.ca>
रेहानेह जावदी <javadi1@ualberta.ca>

> ईरानी समाजशास्त्रीय संघ और गैर–संस्थागतीकरण का संस्थागतीकरण

इस्माइल खलीली, इंस्टीट्यूट फॉर सिविलाइजेशनल एंड सोशियो–कल्चरल स्टडीज के पूर्व संकाय सदस्य और ईरानी समाजशास्त्रीय संघ (2021–25), ईरान के उपाध्यक्ष द्वारा

ईरानी समाज पर वैचारिक और आलोचनात्मक चिंतन का छठा सम्मेलन, सितंबर 2025। श्रेय: मोहदेसेह गजविनी

सन् 1934 में तेहरान विश्विद्यालय के स्थापना के माध्यम से समाजशास्त्र ने ईरान के उच्च शिक्षा परिदृश्य में प्रवेश किया, जहाँ सोरबोन से परास्नातक गुलामहुस्सैन सादिघी ने 1940 में यह विषय पढ़ाना शुरू किया। अपने शुरुआती दशकों में, ईरान में समाजशास्त्र एक छोटा और संभ्रांत क्षेत्र था, जिसे फ्रेंच बौद्धिक प्रभावों ने आकारित किया था और यह पहलवी राज्य के आधुनिक राष्ट्र–निर्माण प्रोजेक्ट से जुड़ा था। यह तेहरान के अकादमिक अभिजात वर्ग के बीच ही विकसित एक विषय बना रहा, जिसकी संस्थागत पहुंच सीमित थी और पेशेवर समुदाय भी संकीर्ण था।

1979 की क्रांति और उसके बाद 1980–1983 की सांस्कृतिक क्रांति दरार और फैलाव दोनों लाए। नए इस्लामिक गणतंत्र ने विचारधारायी रूप से संदिग्ध शिक्षकों को निष्कासित कर, विश्वविद्यालय को पुनः संगठित करने के लिए बंद कर, और अकादमिक जीवन के प्रत्येक चरण पर वैचारिक जांच को शामिल कर विश्वविद्यालय व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया। अन्य सामाजिक विज्ञानों की तरह समाजशास्त्र की भी गहरी जांच की गई, पूरे बौद्धिक सोच को हटा दिया गया और इस्लामिक और क्रांतिकारी मूल्यों को दिखाने के लिए पाठ्यक्रम को फिर से लिखा गया।

अजीब बात है कि 1980 और 1990 के दशक के अंत में ईरान–इराक युद्ध खत्म होने के बाद, युद्ध–पश्चात् पुनर्निर्माण के समय में उच्च शिक्षा का तेजी से विस्तार हुआ और समाजशास्त्र में नामांकन में काफी बढ़ोतरी हुई। यद्यपि, इस क्षेत्र की संस्थागत प्रगति, किराएदार सरकार के नौकरशाही और वैचारिक व्यवस्था में गहराई से जुड़ी हुई थी। शैक्षणिक तरक्की, शोध निधियन, और विभागीय नियुक्तियां बौद्धिक स्वायत्ता अथवा विद्धवतापूर्ण योग्यता से कम और राजनैतिक वफादारी, व्यक्तिगत नेटवर्क्स, और अफसरशाही अनुपलानों से अधिक शासित थे। हालांकि समाजशास्त्र विभाग और विद्यार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई, लेकिन बौद्धिक जीवन की की गुणवत्ता औपचारिक विस्तार और वैचारिक नियंत्रण की बाधाओं के मध्य तनाव के द्वारा आकारित हो रही थी।

> एक विविध नौकरशाही अनुपालन मुख्यधारा और एक विविध अकादमिक परिधि

क्रांति के बाद के इस माहौल में, ईरानी समाजशास्त्र तेजी से अलग होता गया। वैचारिक जांच, नौकरशाही औपचारिकता और किरायदार विश्विद्यालय की प्रतिष्ठित अर्थव्यवस्था ने एक ऐसे पेशे का निर्माण किया जिसमें विद्वान् अलग –और कभी कभी तीव्र रूप से भिन्न – दृष्टिकोण अपनाते हैं। कुछ लोग औपचारिक विचारधारा से जुड़े रेंटियर चौनलों के जरिए इस फील्ड में आए, और कुलीन अकादमिक नेटवर्क में प्रबंधकीय पदों के लिए राजनैतिक वफादारी का फायदा उठाया। अन्य लोग, जो विचारधारा के मामले में कम पक्के थे, फिर भी व्यवहारिक लाभ के लिए अफसरशाही भूमिकाएँ निभाने लगे, और वे व्यवस्था के मौजूदा नियमों के अंदर सुरक्षा और तरक्की चाहते थे।

कुछ कट्टर विचारक भी थे – चाहे धार्मिक, वामपंथी अथवा राष्ट्रवादी – जिन्होंने खुद को विश्वविद्यालय की मुख्यधारा से बाहर रखा, और लगातार आनुभाविक जांच के बजाय राजनैतिक दावों

>>

पर ध्यान केंद्रित किया। अकादमिक केंद्र से परे, स्वतंत्र शोधकर्त्ता, जिनमें से कई को 1980 के दशक में निर्वासित कर दिया गया था, औपचारिक जुड़ाव न होने के बावजूद दीर्घ बौद्धिक मूल्य वाली कृतियों का निर्माण करते रहे।

"विश्वविद्यालयी परिधि" में शोध संस्थानों या वैज्ञानिक निकायों में काम करने वाले लोग शामिल थे, जो अक्सर सार्वजनिक भाषण, प्रकाशन और ऑनलाइन फोरम के जरिए ज्यादा लोगों से जुड़ते थे। विश्वविद्यालय के बाहर का एक युवा समूह भी उभरा– जिनमें से कुछ नियमों के कारण बौद्धिक जगत से अलग कर दिए गए थे, अन्य, जो महत्वपूर्ण वैश्विक बौद्धिक सोच के साथ संवाद में लगे रहे, अपनी मर्जी से इससे दूर रहते थे। ईरानी प्रवासी में दो अलग–अलग समूह शामिल थे: वे लोग जिन्होंने ईरान में प्रशिक्षण लिया था लेकिन राजनैतिक पाबन्दी की वजह से वापस नहीं आ सके, और वे लोग जो विदेश में पैदा हुए या पले–बढ़े, फिर भी उनका बौद्धिक कार्य ईरानी समाज से गहराई से जुड़ा था। आखिर में, कुछ "आइडेंटिटी सीकर्स" थेः ऐसे स्नातक जिनके लिए समाजशास्त्र एक लगातार बौद्धिक कार्य से ज्यादा निजी या प्रतीकात्मक जुड़ाव का जरिया था, जो लगातार बौद्धिक योगदान के बजाय पहचान, स्टेटस या अपनेपन का एहसास देता था।

> विरासत

यह परत वाला और बिखरा पेशेवर क्षेत्र ईरानी समशास्त्रीय संघ के निर्माण से पूर्व का है लेकिन इसने इसकी संस्कृति और आतंरिक राजनीति को निर्णायक रूप से आकारित किया है। नौकरशाही वफादारी से लेकर कट्टरपंथी आजादी तक, वैश्विक बौद्धिक जुड़ाव से लेकर पूरी तरह से व्यक्तिगत पहचान तक, ऐसे विविध झुकावों के सह–अस्तित्व ने यह सुनिश्चित किया कि ईरानी समाजशास्त्र संघ के संस्थागत जीवन की विशेषता बहुलता और तनाव दोनों होगी।

इन विरासतों ने तथाकथित गैर–संस्थाकरण का संस्थाकरण का माहौल तैयार किया: एक ऐसी पेशेवर संस्कृति जहाँ ज्ञान का दिखावा ज्ञान के वास्तविक उत्पादन से कहीं ज्यादा होता है।

> स्वरूप और सार के मध्य

औपचारिक बेंचमार्क के मुकाबले, ईरानी समाजशास्त्रीय संघ ने संस्थागतीकरण की दिशा में स्पष्ट तौर पर तरक्की की है; इसकी सदस्यता बढ़ी है, इसकी सालाना कॉन्फ्रेंस का विस्तार हुआ है, और सार्वजनिक बहस में इसकी दृश्यता बढ़ी है। औपचारिक पेशेवर संघ की तरफ पहला और अहम कदम 1991 में उठाया गया था, जब सत्रह ईरानी समाजशास्त्री, जिन्हें ज्यादातर यूरोप और अमेरिका में प्रशिक्षण मिला था, ने ईरानी समाजशास्त्र संघ की स्थापना की। अपने प्रारंभिक दौर में ईरानी संघ ने एक अधिक संरचित आतंरिक संगठन विकसित किया। प्रशासकीय कार्यों जैसे कि अपनी कॉन्फ्रेंस और प्रकाशनों को संयोजित करना, के अलावा इसने समाजशास्त्र के अलग–अलग उप–क्षेत्रों साथ जुड़े कार्यशील समूह बनाए। फिर भी, इनमें से कई समूह बिना किसी साफ फोकस या मकसद के काम करते रहे हैं।

यहां जो बात सामने आती है, वह एक उलझन है जिसे गैर–संस्थागतीकरण का संस्थागतीकरण कहा जा सकता है। वैज्ञानिक संघ अक्सर इस तरह काम करते हैं कि सार के बजाय स्वरुप को अहमियत दी जाती है; कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप और बैठकों के जरिए ज्ञान निर्माण का दिखावा वैधता का पैमाना बन जाता है, जबकि नई अंतर्दृष्टियां द्वितीयक रह जाती है। इस मायने में, परतंत्रता न सिर्फ बाहरी ताकतों पर निर्भरता से बल्कि उन व्यहारों के रूटीन में भी आकार लेती है जो बिना कोई ठोस नतीजा दिए, दिमागी मेहनत की नकल करते हैं।

> परंपरा की मजबूती के बाद समेकन

2000 से 2015 के बीच के वर्ष तुलनात्मक रूप से स्थिरता और मजबूती का समय थे, जिसके दौरान ईरानी समाजशास्त्र संघ ने अकादमिक और सामाजिक वैधता हासिल की। लेकिन बाद के वर्षों में एक पीढ़ीगत परिवर्तन आया : इस दौरान कई वरिष्ठ विद्वान् सक्रिय भागीदारी से पीछे हट गए और नए लोगों को– जो अक्सर एक सीमित शैक्षणिक माहौल में कार्य करते थे– व्यवस्थित प्रशिक्षण और पेशेवर नेटवर्क्स में एकीकृत होने के बहुत कम मौके मिले। जहाँ संख्यात्मक वृद्धि होती रही, संघ का बौद्धिक केंद्र कमजोर हो गया। स्थिरीकरण काल के दौरान बनाए गए संस्थागत नियम और व्यवहार मजबूत हो गए, जिससे एक ऐसी पहचान बनी जो कभी असरदार थी लेकिन अब बदलाव के लिए तैयार नहीं रही।

ईरानी समाजशास्त्र संघ का प्रारंभिक संगठन सम्बन्धी ब्लूप्रिंट सुनिश्चित योजना से ज्यादा मौन ज्ञान पर आधारित थाः इसके संस्थापक सदस्यों की अनौपचारिक आदतें और मान्यताएँ। ईरानी यथार्थ के हिसाब से संरचित होने के बजाय, इसने यूरोप और अमेरिका के पेशेवर संघों के बाहरी रूप की काफी हद तक नकल की। इस नकल ने संघ को एक औपचारिक संगठन जैसा बना दिया, लेकिन बिना चिंतनशील अनुकूलन और संहिताबद्ध नियमों के जो एक टिकाऊ संस्थागत पहचान में उसे जमा सके। परिणामस्वरूप, संघ के पास अपने बौद्धिक मिशन, नैतिक और वैज्ञानिक संहिता या दीर्घ कलिक दृष्टि को बताने वाले बुनियादी दस्तावेजों की कमी है। बौद्धिक जीवन के मुख्य मुद्दों जैसे प्रजातंत्र, संघीय नैतिकता, या कार्याशीक समूहों के मध्य काम का बंटवारा – पर बहस अभी भी कम हो पाई है।

संहिताबद्ध नियमों की कमी की वजह से ईरानी समाजशास्त्र संघ बिना कोडिफाइड परम्पराओं और निजी फैसले लेने के आधार पर काम कर रहा है। यह संस्था मॉडर्न कम और संकर ज्यादा है; औपचारिक रूप से संगठित लेकिन इसमें वह चिंतनशील स्व–समझ नहीं है जो संस्थागत स्थायित्व के लिए आवश्यक है। यह "संस्थागतीकरण के भीतर गैर–संस्थागतीकरण" इसकी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में दिखाई देता है; सदस्य शायद ही कभी संघ की दिशा के बारे में ठोस विचार–विमर्श में शामिल होते हैं, और ईरानी समाजशास्त्र संघ को अपने सदस्यों द्वारा एक साझा बौद्धिक और संगठनात्मक परियोजना के रूप में व्यापक रूप से मान्यता नहीं दी जाती है।

> प्रतिष्ठा बौद्धिक कठोरता और जिम्मेदारी से ज्यादा जरूरी है

साथ ही, संघ की अंदरूनी जिंदगी उलझनों से बनी है। ईरानी समाजशास्त्र संघ, एक बौद्धिक संघ के असली मकसद को पूरी तरह समझे बिना, संगठनात्मक जिंदगी के बाह्य रीति–रिवाजों – कॉन्फ्रेंस, चुनाव, प्रकाशन – को दोहराता है। सिद्धांतों, पद्धति या शोध की प्राथमिकताओं के बारे में मजबूत बौद्धिक बहस को बढ़ावा देने के बजाय, इसकी प्रतिस्पर्धात्मक ऊर्जा अक्सर प्रतिष्ठा, दर्शनीयता और पहचान के प्रश्नों की ओर खिंच जाती है। हाल के वर्षों में सक्रियता और पहचान–बनाने की इच्छा स्पष्ट दिखाई देने लगी है और जहाँ इन्होने संघ की सार्वजनिक प्रोफाइल का विस्तार किया है वहीँ इन्होने कभी कभी स्थायी संस्थागत क्षमता के निर्माण के कार्य को दबा दिया है।

ये गतिशीलता प्रतिस्पर्धा के तीन परस्परछेदी अक्षों: वैचारिक,

>>

प्रतिष्ठा–आधारित और सांस्थानिक में दिखाई देती है। विचारधारा के मतभेद, जो पहले प्रर्माभिक सदस्यों की एक जैसी सोच की वजह से कम थे, अब और स्पष्ट हो गए हैं, और अक्सर सक्रियता और पहचान की राजनीति से जुड़ जाते हैं। प्रतिष्ठा पर आधारित प्रतिस्पर्धा ईरान के व्यापक अकादमिक संस्कृति को दर्शाती है, जहाँ नेतृत्व के पद बौद्धिक उत्तरदायित्व के बजाय प्रतीकात्मक पूंजी के लिए अधिक चाहे जाते हैं। इस बीच, संस्थागत धुरी अभी भी अविकसित है; सेमिनार और कॉन्फ्रेंस के बावजूद, ईरानी समाजशास्त्रीय संघ में वैज्ञानिक प्रतिस्पर्धा – सिद्धांत, पद्धति या शोध एजेंडा पर बहस – का बहुत कम सबूत दिखाता है, जो एक मजबूत विद्वान् समुदाय को मजबूत कर सके।

ये पैटर्न सिर्फ अंदरूनी नहीं हैं, बल्कि ईरान के विश्वविद्यालय व्यवस्था की संरचनात्मक कमजोरियों से और मजबूत होते हैं: संघ की उपस्थिति से पहले असमान शैक्षणिक तैयारी, विश्विद्यालयों के अंदर सीमित मेंटरिंग, और रेंटियर तर्क और कुलीनतंत्र अकादमिक रूढ़ोक्ति का दबदबा। कुल मिलाकर, ये एक ऐसे संघ की उलझन को दिखाते हैं जो औपचारिक रूप से मौजूद है, सार्वजनिक रूप से दर्शनीय है, और संख्यात्मक रूप से बढ़ रहा है, फिर भी एक टिकाऊ बौद्धिक और संस्थागत नींव को मजबूत करने के लिए अभी भी संघर्ष कर रहा है, जिससे इसका भावी प्रक्षेपपथ एक खुला सवाल बना हुआ है।

> भावी संभावनाएं

ईरानी समाजशास्त्रीय संघ की संस्थागत उलझनों के बीच, बदलाव के मौके सामने आने लगे हैं। विवेचनात्मक विद्वानों का एक छोटा लेकिन बढ़ता हुआ समूह, जिसे अक्सर पिछली पीढ़ियों के खास अधिकार नहीं मिलते, वैश्विक विवेचनात्मक सोच से गहराई से जुड़ता है, पहचान से चलने वाली प्रतिष्ठा की चाहत का विरोध करता है, और मौजूदा अधिपत्य से आजाद होकर खुद को एक विद्वान् के तौर पर बनाने की कोशिश करता है। लोकतान्त्रिक व्यवहार, बौद्धिक बहुलता, और संस्थागत चिंतनशीलता में जड़ उनकी प्रतिबद्धताएं, संघ के हावी संस्कृति में सीमांतीय बानी रहती हैं लेकिन फिर भी नवीनीकरण के संभावित रास्तों का संकेत देती हैं।

ऐसे रुझानों को मजबूत करने के लिए, कई अंतर–निर्भर स्तम्भ आवश्यक हैं: लोकतंत्र, गुटबाजी के बजाय विविधता को सोच विचार में बदलनाय बहुलता, यह सुनिश्चित करना कि कार्यशील समूह विविध अभिमुखन दर्शाएं, संचालित स्वायत्ता, इन समूहों को तात्विक एजेंडा तय करने की अनुमति हो, और समय–समय पर होने वाली कॉन्फ्रेंस का जारी रहना, जो पहचान या प्रतिष्ठा पर आधारित एजेंडा के बजाय समस्या केंद्रित शोध पर आधारित हों। अधिक समस्या–अभिमुखन वाले कांफ्रेंस पत्रों की तरफ क्रमिक रुझान ऐसे परिवर्तन का सुझाव देता है जिसमें उस प्रघटना के परे सहयोग को बढ़ावा देने की क्षमता है।

> आगे की चुनौती

ईरानी समाजशास्त्रीय संघ आज कई परत वाली विरासत को दिखाता है; क्रांति से पहले के समय की कुलीन और विदेशियों से प्रभावित समाजशास्त्रय 1980 के दशक की वैचारिक दरारें और सफाईय युद्ध के बाद के दशकों में किराएदार–ब्यूरोक्रेटिक फैलाव; और आज की तेजी से बिखरती हुई बौद्धिक संस्कृति। इस इतिहास ने ईरानी समाजशास्त्रीय संघ को जिंदादिली और अस्थिरता दोनों दिया है; एक व्यापक सदस्यता आधार जिसमें अफसरशाही विश्वासपात्र, स्वतंत्र बुद्धिजन और वैश्विक रूप से संलग्न विवेचनात्मक विद्वान शामिल हैं, लेकिन बिना संहिताबद्ध स्व–समझ या टिकाऊ लोकतान्त्रिक बहस की संस्कृति के।

आगे चुनौती संख्या में बढ़ोतरी या लोगों के बीच अपनी पहचान बनाना नहीं है, बल्कि ऐसी आदतें, नियम और ढांचे बनाना है जो संघ को उसके गुटों के जोड़ से ज्यादा बनने में मदद करें। अन्य शब्दों में, बिना सार के स्वरुप के विरोधाभास के आगे बढ़ना है; उपलब्धि को व्यवहार में बदलना, और दिखावे को असली बौद्धिक उत्पादन में। यदि ईरानी समाजशास्त्रीय संघ स्वयं को बहुलता, लोकतान्त्रिक विमर्श, और बौद्धिक स्वायत्ता में स्थित कर सकता है, तो यह अपनी विविधता सामूहिक ताकत में बदल सकता है। ऐसे बदलाव के बिना, यह स्वरुप में संघ बने रहने का जोखिम उठता है; एक ऐसी संस्था जिसमें एकजुटता का दिखावा है लेकिन बिखराव का यथार्थ। यह जो रास्ता चुनेगा, वह ईरान में समाजशास्त्र की सामूहिक जिंदगी का अगला अध्याय तय करेगा। ■

संपर्क करें :
इस्माइल खलीली <esmaeil.khalili@gmail.com>

> राजनीति और लाभ के मध्य: ईरान में समाजशास्त्र की निजी कक्षायें

रेहानेह जावदी और **जोहरेह बयात्रिजी**, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा, कनाडा द्वारा

'सामाजिक विज्ञान संकाय, तेहरान विश्वविद्यालय'। 2009 के इस चित्र में, पुराना साइन बोर्ड संकाय अहाते के एक कोने में, टूटे हुए गेट से टिका पड़ा है। श्रेयः रेहानेह जावदी।

बाहरी, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय राजनैतिक और आर्थिक ताकतों ने लंबे समय से विश्वविद्यालय के शिक्षण और शोध को आकार दिया है, जिसके अक्सर अच्छे और बुरे, दोनों तरह के असर होते हैं। हाल के दशकों में, कम फंडिंग, नव–उदारवादी मॉडल, और शिक्षण एवं शोध के राजनीतिकीकरण ने कई देशों के विश्वविद्यालयों को व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ–साथ ऐसे शोध को प्राथमिकता देने पर मजबूर किया है जो सरकारी या निजी क्षेत्र की प्राथमिकता से जुड़े हों। शिक्षा के क्षेत्र में, सूक्ष्म–प्रमाणपत्रवाद, MOOCs (मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स), और सर्टिफिकेट–आधारित शिक्षा, कम से कम कुछ हद तक, इन बड़े राजनैतिक–आर्थिक दबावों का प्रत्युत्तर हैं, जिससे उच्च शिक्षा का ज्यादा वस्तुकरण हो रहा है, औपचारिक कक्षा में शिक्षा कमजोर हो रही है, और शिक्षा एवं जांच के कई क्षेत्रों का अवमूल्यन हो रहा है।

ये बड़े रुझान कभी–कभी स्थानीय सन्दर्भ में पहले से मौजूद

>>

गतिकी को बिगाड़ देते हैं और कभी–कभी उन्हें और मजबूत करते हैं। ईरान के मामले में, जिस पर हम यहां ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, राजनैतिक सेंसरशिप, कम फंडिंग, और अकादमिक मेरिट के बजाय विचारधारायी वफादारी को तरजीह देने वाली हायरिंग पॉलिसी ने लंबे समय से समाजशास्त्र की पढ़ाई को बाधित किया है। दूसरी ओर, इक्कीसवीं सदी की शुरुआत से ही छात्र–समर्थित सक्रियता ने उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और विचारों के मुक्त विनिमय पर जोर दिया है। विद्यार्थियों ने लोकप्रिय या प्रतिषिद्ध विषयों पर रीडिंग समूह बनाए हैं और राजनैतिक रूप से बहिष्कृत अकादमिक के साथ निजी कक्षायें बनाई हैं। समय के साथ, विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता की कमी को पूरा करने और वैकल्पिक शिक्षण मंच प्रदान करने के लिए निजी, शुल्क–आधारित पाठ्यक्रम उभरे हैं।

यह लेख ईरान में समाजशास्त्र के निजी पाठ्यक्रमों के बारे में बताता है, जिसमें उनके उद्‌भव, संरचना, प्रतिभागी, तथाकथित गुणवत्ता और व्यापक राजनैतिक और अकादमिक असर का विश्लेषण किया गया है। हमारा तर्क है कि ये कक्षायें शैक्षणिक जगत में वस्तुकरण और प्रतिरोध की दोहरी गतिकी को दिखाती हैं। हमने कई तरीकों का संयोजन इस्तेमाल किया है, जिसमें अभिलेखीय अध्ययन, वेब शोध, और समाजशास्त्र की कक्षा की पेशकश करने वाले आठ निजी संस्थाओं के 28 विद्यार्थी और प्रशिक्षकों के साथ अर्ध–संरचित साक्षात्कार सम्मिलित हैं। हमारे अध्ययन से पता चलता है कि, जहाँ इनमे से कुछ घटनाक्रम ईरान के लिए खास हैं, लेकिन कुछ मामलों में वे दुनिया भर में उच्च शिक्षा में होने वाले व्यापक बदलावों, खासकर ज्ञान के वस्तुकरण, से जुड़े हैं। हालांकि, ईरानी संदर्भ में, समाजशास्त्र की निजी कक्षायें भी सरकार द्वारा समर्थित पाबंदियों के खिलाफ संभावित विरोध की जगह के तौर पर काम करती हैं।

> निजी कक्षायें: पाठक मंडल से मुनाफाखोरी तक

ईरान में पाठक मंडल और व्याख्यान श्रंखला लंबे समय से मौजूद हैं। हालांकि, शुल्क–आधारित समाजशास्त्र पाठ्यक्रम मुख्य रूप से 2010 के दशक में निजी क्षेत्र में पोर्सेश और रोखदाद–ए–ताजेह (तेहरान के दो जानी मानी संस्थाएं) जैसे शिक्षण संस्था में शुरू हुए। ईरानी समाजशास्त्रीय संघ समेत अकादमिक संघों ने भी शुल्क–आधारित पाठ्यक्रम की पेशकश करना प्रारम्भ कर दिया है। इन मंचो पर प्रस्तुत पाठ्यक्रम विशिष्ट और फैशनेबल विषयों (स्पिरिट का प्रघटनाशास्त्र, प्लेटो की फार्मेसी में डेरिडा) से लेकर व्यावहारिक पद्धतिशास्त्र (विमर्ध विश्लेषण, एनवीवो, कोडिंगध्संकेतन) तक हैं। ये संस्थाएं "शैडो शिक्षा" का एक उदाहरण हैं, जो औपचारिक संस्थाओं के साथ काम करते हैं, लेकिन अलग–अलग प्रोत्साहन और तर्क से बनते हैं।

कई निजी पाठ्यक्रम, सीमित भागीदारी और कोई व्याख्यान आधारित होते हैं, जिनमें कम लोग हिस्सा लेते हैं और कोई पाठ्यचर्या, मूल्यांकन या समनुदेशन नहीं होता है। कुछ निजी संस्थाएं सर्टिफिकेट देती हैं, जिनका इस्तेमाल मुख्य रूप से चैक अभ्यर्थी अपने आवेदन को मजबूत करने के लिए करते हैं। कोर्स की फीस, जो बहुत अलग–अलग होती है, और क्लास रिकॉर्डिंग से होने वाली सीमित आय इन संस्थाओं के लिए मुनाफे का जरिया है। यद्यपि, वित्तीय प्रोत्साहन मौजूद हैं, समाजशास्त्र की निजी संस्थाएं ज्यादा मुनाफे वाली नहीं हैं; हमारे द्वारा चिन्हित आठ संस्थाओं में से दो दिवालिया हो गई है।

इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि संस्थाएं कम लागत वाले, व्याख्यान–आधारित और लोकप्रिय टॉपिक को प्राथमिकता देते हैं। शुरू में, ये फैशनेबल सैद्धांतिक टॉपिक थे जिनकी तेहरान जैसे बड़े शहरी सेंटर, जहाँ कई बड़े विश्विद्यालय हैं और जहाँ बौद्धिक सर्कल लंबे समय से फल–फूल रहे हैं, के बौद्धिक हलकों के लोगों में गारंटित श्रोता थे। लेकिन इन कक्षाओं के अपने आलोचक भी हैं। साक्षात्कारदाता में से एक ने बताया कि कैसे मुनाफे के मकसद से निजी संस्थान विशिष्ट पश्चिमी सैद्धांतिक बहस को बड़ा प्लेटफॉर्म देते हैं: "ये संस्थान एजेंडा तय करते हैं। वे शक्तिशाली कारोबार हैं और व्यापारियों की तरह काम करते हैं। और माल क्या है? ख्सोशल, सोच माल है; हमारी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के लिए सिद्धांत अप्रासंगिक है।" (साक्षात्कारदाता #5)।

> निजीकृत अधीनस्थ प्रति–सार्वजनिक/कॉउंटरपब्लिक्स

ये जगहें वैसे ही काम करती हैं जिसे फ्रेजर अधीनस्थ काउंटरपब्लिक कहेंगे: अर्ध–सेमी–स्वायत्तशासी फोरम जहाँ अधिकारहीन आवाजें सरकार के नियंत्रण से बाहर आलोचनात्मक विमर्श में शामिल होती हैं। प्रतिभागी अलग–अलग शैक्षणिक पृष्ठभूमि से आते हैं, और उनकी अभिप्रेरणा में शैक्षणिक जांच, राजनैतिक कुंठा, नेटवर्किंग और विश्विद्यालय के दबाव से बचना शामिल है। कई लोग इन कक्षाओं को बौद्धिक शरणस्थल के रूप में देखते हैं, खासकर 2009 के ग्रीन मूवमेंट के दमन के बाद 2010 के दशक में, जिसका विश्वविद्यालयों पर गहरा असर पड़ा था। राजनीतिक रूप से परित्यक्त समाजशास्त्रियों के लिए, निजी पाठ्यक्रम अकादमिक संलग्नता और वित्तीय सहारा दोनों देते हैं, जबकि सुरक्षित आय वाले विश्वविद्यालय के आचार्य भी ये कक्षा पढ़ाते है। वे इन कक्षाओं को आलोचनात्मक विचार व्यक्त करने के लिए मुक्त स्थान के रूप में देखते है।

सरकारी परमिट की जरूरत होने के बावजूद, निजी संस्थान विश्वविद्यालय के मुकाबले ज्यादा खुली बातचीत की इजाजत देते हैं। विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के सख्त संस्तरण के उलट, आरामदेह शक्ति गतिकी पसंद आते हैं। कुछ लोग इन संस्थाओं को बौद्धिक प्रतिष्ठा का स्त्रोत मानते हैं, खासकर अब निष्क्रिय पोर्सेश को, जिसके पास अपने अच्छे दिनों में काफी प्रतीकात्मक पूंजी और कुलीन सामाजिक पूंजी थी। निजी कक्षायें उन विद्यार्थियों को भी आकर्षित करती हैं जो अपने विश्वविद्यालय के बाहर आचार्यों से सीखने के मौके ढूंढते हैं।

निजी कक्षाओं में हिस्सा लेने वाले अक्सर विश्वविद्यालयी समाजशास्त्र प्रोग्राम को अप्रभावी बताकर उनकी आलोचना करते हैं, जिससे वे दूसरे प्रोग्राम ढूंढने लगते हैं। निजी कक्षाओं में अधिक ज्यादा सहभागिता मिलती है, लेकिन गुणवत्ता को लेकर राय अलग–अलग होती है। कुछ लोग विशेषीकृत ज्ञान को महत्व देते हैं, जबकि दूसरों को लगता है कि ये पाठ्यक्रम बहुत कम ऐसी चीजें दे कर जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध न हो, बौद्धिकता का सिर्फ व्यवसायीकरण करते हैं। आलोचक सोच को ही वस्तु बनाने का खतरा देखते हैं, जिससे जटिल सैद्धांतिक कार्य को निजी इस्तेमाल के लिए विपणनयोग्य सामग्री में बदल दिया जाता है।

कई निजी कक्षायें उन विद्यार्थियों के लिए एक बौद्धिक स्पेस प्रदान करती हैं जो सीमित विश्विद्यालय पाठ्यक्रम से आगे गहरा सैद्धांतिक संलग्नता चाहते हैं, हालांकि आलोचकों का कहना है कि वे अक्सर ईरानी सन्दर्भ की प्रासंगिकता को सम्बोधित किये बिना अक्सर पश्चिमी विचारधारा के गुणगान करते हैं। एक साक्षात्कारदाता ने इस अनुभव की तुलना आध्यात्मिक भाव–विवेचन से की, जहाँ प्रतिभागी बिना कुछ ज्यादा सीखे खुद को बौद्धिक रूप से बेहतर महसूस करते हैं। उस साक्षात्कारदाता ने आधिकारिक विश्वविद्यालयी

>>

शिक्षा का बचाव करते हुए कहा कि कई निजी कक्षाओं के अलग सैद्धांतिक फोकस के विपरीत यह ईरान में विद्यार्थियों को सामाजिक शोध से रूबरू कराती है।

> प्रभाव

निजी कक्षायें ईरान के प्रतिबंधात्मक अकादमिक माहौल के लिए एक विवादित लेकिन जरूरी विकल्प देती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये कक्षायें उच्च गुणवत्ता विकल्प प्रदान कर विश्वविद्यालयों को कमजोर करती हैं और इसलिए, शैक्षणिक जगत में विद्यार्थी सक्रियता को कमजोर करती हैं। दूसरे लोग मानते हैं कि सरकार के नियंत्रण वाले अकादमिक माहौल में स्वतंत्र समाजशास्त्रीय विमर्श को बनाए रखने के लिए निजी कक्षायें आवश्यक हैं। उनका कहना है कि विश्विद्यालय बदलने के लिए बहुत सख्त हैं, जिससे बाहरी बौद्धिक स्पेस आवश्यक हो जाती हैं। कुछ लोग निजी कक्षाओं को आलोचनात्मक संलग्नता के लिए एक नया, यद्यपि कमियों वाला, प्लेटफॉर्म मानते हैं: "अगर ये संस्थान बंद हो गए, तो दूसरा विकल्प क्या है? सरकार सब कुछ नियंत्रित कर लेगी" (साक्षात्कारदाता #23)।

निजी कक्षाओं का सामाजिक—आर्थिक असर भी ध्यान देने लायक है। दशकों के बाजार—चलित बदलावों ने ईरान के उच्च शिक्षा के परिदृश्य को पुनःआकारित किया है, जिसके कारण पहुँच अत्यधिक स्तरीकृत हो गयी है। मुख्य, सरकारी विश्वविद्यालयों में प्रवेश बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धात्मक हो गया है और उच्च—आय वाले परिवारों के लिए गेमिंग का रास्ता खुल गया है। इसके अलावा, जहाँ इन विश्वविद्यालयों को निशुल्क पढाई करनी चाहिए, कमियां ढूंढी जा रही हैं और फीस वसूलने के लिए उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकारी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई की गुणवत्ता में गिरावट और निजी, शुल्क—आधारित पाठ्यक्रमों के बढ़ने से मौजूदा असमानताएं और मजबूत हुई हैं और अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा तक पहुंच और भी कम हो गई है।

कई देशों में, सूक्ष्म—क्रेडेंशियलिज्म विश्वविद्यालयों पर कॉर्पोरेट दबाव से पैदा होता है। ईरान में, शुल्क—आधारित पाठ्यक्रम राजनीतिक झगड़े और सरकार के नियंत्रण वाले अकादमिक की कमजोरियों से पैदा होते हैं। शुरू में, वे सैद्धांतिक बहस के लिए बौद्धिक स्पेस के रूप में काम करते थे, लेकिन अब उनमें कौशल—आधारित प्रशिक्षण और सर्टिफिकेट शामिल हैं जो अकादमिक और नौकरी की संभावनाओं को बढ़ाते हैं।

> निष्कर्ष

ईरान में समाजशस्त्र की निजी कक्षायें मार्केट का सिर्फ बदलाव नहीं हैं; वे एक ऐसी विवादित जगह पर हैं जहाँ कमोडिटी बनने का विरोध होता है। शैडो एजुकेशन के स्वरुप के तौर पर, काउंटरपब्लिक स्पेस, जो राज्य नियंत्रण और बौद्धिक अनुरूपता को चुनौती देते हैं, का निर्माण करते हुए वे क्रेडेंशियलिज्म के नव—उदारवादी तर्क को दिखाते हैं। व्यस्थित राजनैतिक बाधाओं के ये निजी प्रत्युत्तर ईरानी उच्च शिक्षा में बड़े बदलावों को दिखाते हैं, जहाँ सरकारी संस्थान कम फंडिंग, विचारधारायी दखल और बढ़ती असमानता की वजह से कमजोर हो रहे हैं।

भावी शोध में यह देखा जाना चाहिए कि बौद्धिक संलग्नता के लिए एक स्थान के रूप में सोशल मीडिया का उभार सार्वजनिक ज्ञान गतिकी को कैसे प्रभावित करता है, और औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के मध्य की सीमाओं को फिर से परिभाषित करता है। सोशल मीडिया आलोचनात्मक विमर्श को कक्षा के बाहर विस्तारित कर लोक समाजशास्त्र को बढ़ा सकते हैं। इससे ब्रांडिंग और अंतर्वस्तु मुद्रीकरण के जरिए ज्ञान को और अधिक व्यावसायिक कर सकते हैं। क्या यह बदलाव समाजशास्त्रीय अंतर्दृष्टि तक पहुंच को लोकतान्त्रिक बनाता है या सिर्फ डिजिटल रूप में मार्केट लॉजिक को कॉपी करता है, यह एक खुला सवाल है। ■

संपर्क करेंरू
रेहानेह जावदी <javadi1@ualberta.ca>
जोहरेह बयात्रिजी <bayatriz@ualberta.ca>

> ईरान में नृजातीयता:

वह प्रश्न जिसे ईरानी समाजशास्त्र टालता है

अघिल दघाघेलेह, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्दर्न कोलोराडो, यू.एस.ए द्वारा

प्रमुख समूहों को दर्शाते हुए ईरान का जातीय विविधता मानचित्र। श्रेयः ईरान में जातीय समूह, मैपर 01 द्वारा, विकिमीडिआ कॉमन्स, CC BY-SA 4.0.

ईरान में नृजातीयता एक बहुत बड़ी बात है — कम से कम जब मुख्यधारायी समाजशास्त्र की बात आती है। ईरान में कई नृजातीय समूह रहते हैं, जिनमें पर्शियन, कुर्द, तुर्क, अरब और बलूची शामिल हैं। मध्य पठार में ज्यादातर पर्शियन हैं, जबकि दूसरे नृजातीय समूह आस—पास के इलाकों में संकेंद्रित हैं। ये नृजातीय विभाजन धार्मिक मतभेदों से जुड़े हैं, क्योंकि मध्यध्केंद्र में शिया इस्लाम ज्यादा है, और परिधीय इलाकों में सुन्नी आबादी ज्यादा है। यह संक्षिप्त विवरण भी समाजशास्त्रीय प्रश्नों को उठाता है, जैसे कि ऐसे नृजातीय और धार्मिक भेदभाव और परस्परछेदन सामाजिक अनुभवों को कैसे आकार देते हैं। फिर भी, हैरानी की बात है कि ईरान में विद्वता में इन बिखराव को नजरअंदाज कर दिया जाता है।

इसका मतलब यह नहीं है कि नृजातीयता पर बढ़ते साहित्य को नकारा जाए, जिसके बारे में मैं बाद में बताऊँगा, लेकिन आम समाजशास्त्रीय अध्ययनों में, नृजातीयता को एक विश्लेषणात्मक श्रेणी जो ईरान में सामाजिक अनुभव को अलग करती है, के तौर पर काफी हद तक नकारा जाता है। ईरानी क्रांतियों से लेकर महिलाओं के संघर्ष, सामाजिक आंदोलनों, अधीनस्थ राजनीति और देश के सामने मौजूद अन्य सामाजिक—राजनीतिक चुनौतियों तक, अलग—अलग विषयों पर अध्ययन प्रकाशित हो रहे हैं। हालाँकि, इस साहित्य में से अधिकांश में, यह विषय एकल 'ईरानी लोग' बना रहता है, जबकि नृजातीयता दबी हुई है।

एक तरफ, यह इनकार राष्ट्रवादी नजरिए से आता है जो ईरान को ऐतिहासिक रूप से एक एकजुट और सजातीय राष्ट्र के रूप में चित्रित करता है। इस तरह, नृजातीयता को सामाजिक अनुभव के संरचनात्मक आयाम के बजाय सांस्कृतिक विविधताओं के मामले के रूप में देखा जाता है। यह नजरिया अक्सर देश की एकता को स्वाभाविक बनाने और राष्ट्रीय बिखराव के अस्तित्व को नकारने के लिए प्राचीन ईरान की महिमा के आख्यानों के साथ—साथ आर्य वंश के मिथकों का सहारा लेता है। इस ढांचे के भीतर, देश में दैनिक यथार्थ को समझने के लिए नृजातीयता को एक विश्लेषणात्मक धुरी के रूप में जातीयता को शामिल करना अप्रासंगिक और यहां तक कि खतरनाक माना जाता है, क्योंकि नृजातीयता को स्वीकार करने से ऐसे भेदों के मजबूत होने और एक एकीकृत पूरे की कल्पना के खंडित करने का डर है।

आलोचनात्मक विद्वान राष्ट्र के आधुनिक निर्माण को स्वीकार करने की अधिक संभावना रखते हैं। उनमें से अधिकांश यह मानते हैं कि राष्ट्र—राज्य गठन के वैश्विक इतिहास में ईरान कोई अपवाद नहीं है। हालाँकि, इस परंपरा में, ईरानी सामाजिक—राजनीतिक जीवन के एक संरचनात्मक आयाम के तौर पर नृजातीयता पर बहुत कम ध्यान दिया गया है, यद्यपि हाल के कुछ कामों ने इस कमी को पूरा करना शुरू कर दिया है। उदाहरण के लिए, कादिवर एट अल. (2025) के एक हालिया शोध पत्र में ईरान में प्रतिरोध की हालिया लहरों के विश्लेषण में नृजातीयता को एक आयाम के तौर

>>

पर शामिल किया गया है। फिर भी यह दृष्टिकोण अभी भी हाशिये पर है।

यह विश्लेषणात्मक चुप्पी अचानक नहीं है, बल्कि ईरानी समाजशास्त्र के आस्थापकता में ही स्थित है। ऐतिहासिक रूप से इस क्षेत्र को फारसी, शिया और मध्य–वर्ग की बौद्धिक परम्पराओं ने आकार दिया है। यह परंपरा देश को ईरान के मध्य पठार की संस्कृति, भाषा और ऐतिहासिक अनुभव के बराबर मानती है, जिससे भिन्न सामाजिक यथार्थों की संभावना को नजरअंदाज कर दिया जाता है। यह बात तब और भी जरूरी हो जाती है जब हम जाति और धर्म के परस्परछेदन पर विचार करते हैं, क्योंकि बड़ी परिधीय आबादी सुन्नी और गैर–फारसी दोनों है। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि परिधीय समुदायों ने मध्य ईरानी राज्य के साथ अपने संबंधों में विभिन्न प्रकार के प्रक्षेपवक्र देखे हैं। उदाहरण के लिए, आधुनिक ईरानी राज्य का बनना, जिसे बड़े पैमाने पर आधुनिक ईरानी राष्ट्र के जन्म और मध्य में प्रादेशिक सत्यनिष्ठा के तौर पर मनाया जाता है, को परिधीय इलाकों में स्वायत्ता के नुकसान के तौर पर याद किया जाता है। यही बात 1979 की इस्लामिक क्रांति के बारे में भी कही जा सकती है, जब शिया धर्म पर जोर देने से बाहरी इलाकों में विरोध और हिंसक दमन शुरू हो गया था। बेशक, यह सूची और भी लंबी हो सकती है। लेकिन बात यह है कि ईरानी इतिहासकार, अराश खजेनी के शब्दों में, किनारे से देखे गए ये विचार इस पांडित्य में ज्यादातर गायब रहते हैं। यहाँ समस्या यह नहीं है कि इन परिपेक्ष्यों में तालमेल बिठाना मुश्किल है, और न ही यह सामाजिक जगत को हाशिए पर रहने वालों की नजर से देखने की हमारी अपनी इच्छा की कमी है। बल्कि, मुद्दा यह है कि मध्य में गहराई से जमे हुए नजरिए से परिधीय नजरिये के बारे में विचारना अधिकतर अकल्पनीय रहता है। बेशक, इन सबके पीछे गहरे शक्ति सम्बन्ध हैं, जिन्हें मैं अभी के लिए अलग रख रहा हूँ।

> ईरान में नृजातीयता को आम तौर पर असमानता की धुरी के बजाय एक बीमारी के तौर पर देखा जाता है

इस व्यापक विश्लेषण चुप्पी के बावजूद, ईरान में नृजातीयता पर विद्वता एक संकीर्ण, अलग, तथापि बढ़ते हुए क्षेत्र के तौर पर विकसित हुई है। देश के अंदर नृजातीयता पर अधिकतर शोध नीति–अभिमुखित, रोगात्मक नजरिए से होता है। नृजातीयता को एक 'समस्या' के रूप में देखा जाता है, जो देश की एकता के लिए एक अस्तित्वगत खतरा है, जिस की निगरानी होनी चाहिए, उसे रोकना चाहिए या उसे बेअसर करना चाहिए। शोधकर्ता नृजातीय समूहों में ऐसे घूमते हैं जैसे जोखिम क्षेत्रों की जांच कर रहे हों। यह देखते हुए कि नृजातीय जुड़ाव राष्ट्रीय जुड़ावों से कैसे मिलते हैं या अलग होते हैं, और क्या वे इस समय कोई खतरा हैं, वे लगातार राष्ट्रीय पहचान के स्तरों का आकलन करते हैं।

अलगाववाद, राष्ट्रीय एकजुटता और नृवंशवाद (*कौमगेरायी*) जैसे विषय इस क्षेत्र में हावी हैं। इसे कुलीन या देश को अस्थिर करने के इरादे से विदेशी कर्त्ताओं द्वारा बनाया गया एक मिथक बताते हुए कुछ अध्ययन ईरान में नृजातीयता के अस्तित्व को ही नकारते हैं। अन्य इसे एक उभरता हुआ संकट मानते हैं: सम्प्रभुता के लिए अप्रकट खतरा, एक "सुरक्षा–रुग्णता" (बीमारी–ये अमनियाती) जिसका पता लगाया जाना और इलाज किया जाना है, भविष्य के झगड़े का एक फ्लैशपॉइंट, या एक सुरक्षा चुनौती जिसका प्रबंधन किया जाना चाहिए। यह, वास्तव में, एक ऐसा समाजशास्त्र है जो जेम्स स्कॉट के वाक्यांश केअनुसार 'एक राज्य की तरह देखता है', जो नृजातीय आबादी को उनके अपने शब्दों में समझने के बजाय, नियंत्रण के उद्देश्यों के लिए सुपाठ्य और प्रबंधनीय बनाने का प्रयास करता है।

इसके साथ ही, एक अधिक विवेचनात्मक और व्याख्यात्मक काम सामने आया है, जिसमें यह विश्लेषण किया है कि व्यापक राज्य–निर्माण के प्रोजेक्ट्स द्वारा नृजातीय नीतियों को कैसे आकार दिया गया है। नृजातीयता को एक रुग्णता जिसका प्रबंधन किया जाना है के रूप में देखने के बजाय, यह विद्वता नृजातीय पहचान को राष्ट्र–निर्माण, बाध्यकारी एकीकरण और असमान विकास की ऐतिहासिक प्रक्रिया के अंदर स्थित करती है। इस परंपरा के काम इस बात की जांच करते हैं कि कैसे सरकारी विमर्श और संस्थाओं ने भाषाई एकरूपता, अल्पसंख्यक इतिहास को दबाने और गैर–फारसी समुदायों को सुरक्षित बनाने जैसे तरीकों से पार्श्वीकरण को विकसित किया है। कुछ विद्वानों ने रोजमर्रा के प्रतिरोध के तरीकों को भी उजागर किया है; कैसे नृजातीय अल्पसंख्यक राष्ट्रीय पहचान के प्राधान्य आख्यान पर बातचीत करते हैं, उन्हें तोड़ते हैं, या उनका विरोध करते हैं। इसके अलावा, आनुभविक शोध का एक बढ़ता हुआ, यद्यपि अभी भी सीमित, हिस्सा है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य–सेवा और आर्थिक अवसरों में जातीय भेदभाव की जांच करने लगा है, जिससे यह चुनौतीपूर्ण, यद्यपि अभी भी अधिकतर अनुत्तरित प्रश्न उठता है कि क्या नृजातीयता समकालीन ईरान में असमानता की धुरी के तौर पर काम करती है।

> नृजातीयता लंबे समय से चले आ रहे संघर्षों से उलझी हुई है

महत्वपूर्ण अंतर अभी भी बने हुए हैं। पहली कमी अवधारणात्मक है; ईरानी संदर्भ में नृजातीयता अभी भी समझ से बाहर है, जिससे कुछ विद्वान् राजनैतिक और सैद्धांतिक तनाव से बचने के लिए 'अल्पसंख्यक' जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं।

"अल्पसंख्यक" का मतलब आम तौर पर संख्यानुसार हाशिए पर होना या संरचनात्मक तौर पर कमजोर होना होता है, लेकिन यह किसी नृजातीय समूह को कैसे परिभाषित किया जाये, उसकी सीमाएं कहां खींची जाएं, या पहचान को जरूरी बनाने से कैसे बचा जाए, जैसे विवादित सवालों से कम जुड़ा होता है। यह बदलाव विद्वानों को रोजर्स ब्रूबेकर के शब्दों में "बिना समूहवाद के नृजातीयता" (जैसा कि एलिंग के काम में देखा गया है) को आगे बढ़ाने की इजाजत देता है, जो सामूहिक पहचान के दावों या सम्प्रभुता को चुनौती दिए बिना, हाशियेकारण का विश्लेषण करने में मदद कर सकता है।

तथापि, प्रश्न बना हुआ है("नृजातीयता" का – भले ही इसे ज्यादा सावधानी से "अल्पसंख्यक" के रूप में परिभाषित किया जाए – ईरानी संदर्भ में वास्तव में क्या अर्थ है? यह बात तब और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जब पाश्चात्य फ्रेमवर्क को बिना पर्याप्त आलोचना के लागू किया जाता है, ऐसे सिद्धांत जो अक्सर पहचान, सांस्कृतिक पहचान, या प्रतीकात्मक सीमाओं पर जोर देते हैं, लेकिन सम्प्रभुता के ऐतिहासिक प्रश्न पर बहुत कम ध्यान देते हैं। ईरान में, नृजातीयता सिर्फ सांस्कृतिक विशिष्टता के बारे में नहीं है। यह देश की सम्प्रभुता, क्षेत्रीय नियंत्रण, और परिधीय इलाकों को जबरदस्ती शामिल करने को लेकर लंबे समय से चले आ रहे संघर्षों से भी जुड़ा है। देश के मुख्य जातीय समूह – तुर्क, कुर्द, बलूची, अरब और तुर्कमेन – उस जगह पर केंद्रित हैं जिसे आम तौर पर "परिधि" कहा जाता है; ये ऐसे इलाके हैं जो तेहरान और मध्य पठार से भौगोलिक रूप से दूर हैं। इन क्षेत्रों और उनके समुदायों का अक्सर अर्ध–स्वायत्त शासन और केंद्रीय सरकार के साथ लंबे समय से तनाव का इतिहास रहा है; ऐसे क्षेत्र जिन्हें ईरानी सरकार के राजनैतिक व्यवस्था में शामिल करने के लिए सैन्य अभियान, जबरन आत्मसात करना और जनसंख्या नियंत्रण को काम में लेना पड़ा। फिर भी, इन इतिहासों को अक्सर नृजातीयता के समकालीन विश्लेषणों से बाहर

> >

रखा जाता है, जिससे वर्तमान की नृजातीय गतिकी की जटिलता को पूरी तरह से समझना मुश्किल हो जाता है।

> आदिवासी इतिहास को नृजातीय समाजशास्त्र में जोड़ने से पता चलता है कि ऐतिहासिक विरासत वर्तमान यथार्थ को कैसे आकार देती है

यह पक्का है कि राज्य का बाहरी इलाकों में फैलाव प्रलेखित है – खासकर अधीनस्थ अध्ययनों से प्रभावित साहित्य में। ये काम राज्य हिंसा और स्थानीय प्रतिरोध को चिन्हित करते हैं, जिसे आम तौर पर "जनजातीय राजनीति" कहा जाता है। हालांकि, जनजातीय राजनीति और नृजातीय अध्ययन अलग–अलग रहे हैं: पूर्ववर्ती इतिहास के साथ जुड़ा है और उत्तरवर्ती वर्तमान से। यह विभाजन यह स्पष्ट नहीं करता है कि ऐतिहासिक विरासतें वर्तमान यथार्थ को कैसे आकार देती हैं। इस अंतराल को भरने से ईरान में नृजातीय अध्ययन के लिए नए अवधारणात्मक मार्ग खुलेंगे।

पांडित्य का एक छोटा लेकिन बढ़ता हुआ समूह ठीक यही करने लगा है। राज्य–निर्माण के परिधीय इतिहास से प्रेरणा लेकर, ये काम ईरानी देश की स्वयं प्रकृति पर ही प्रश्न उठाते हैं। वे बाध्य–विस्थापन, सांस्कृतिक विलोपन और राज्य हिंसा के मामलों की जांच करते हैं, और तर्क देते हैं कि राज्य बनाने में सिर्फ आधुनिकीकरण ही नहीं, बल्कि औपनिवेशिक वर्चस्व का तर्क भी शामिल था। इस परिपेक्ष्य से, अपने नृजातीय रूप से विशिष्ट परिधि में ईरान का फैलना एक उपनिवेशवादी उपनिवेश प्रोजेक्ट जैसा है, और इसका प्रतिरोध विऔपनिवैषिक प्रयोग है। यह रीफ्रेमिंग मुख्य प्रतिमानों को अस्थिर करती है और आदिवासी इतिहास को नृजातीयता के समाजशास्त्र में शामिल करने की मांग करती है।

> आनुभविक शोध की सेंसरड आवश्यकता जो जीवन के अनुभव की बहुलता को पहचाने

फिर भी, सैद्धांतिक फ्रेमिंग के बावजूद, नृजातीयता को समझने के लिए आनुभविक समझ चाहिए। इसका एक जीती–जागती, बातचीत से तय और रोजमर्रा के व्यवहारों और विवादित अर्थों द्वारा आकारित प्रघटना के रूप में अध्ययन किया जाना चाहिये। इसके लिए दीर्घकालिक नृवंशविज्ञानी संलग्नता की आवश्यकता है। फिर भी ईरान में राजनैतिक और संरचनात्मक रुकावटों की वजह से ऐसा शोध बहुत ज्यादा अवरुद्ध है। नृजातीयता के प्रतिभूतिकरण ने डर और स्व–सेंसरशिप का माहौल बना दिया है। शोधकर्ता और संभाषी, दोनों पर अलगाववाद या राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ काम करने के आरोप लगने का खतरा रहता है। क्षेत्रीय कार्य मुश्किल हो जाता है, और संस्थाएं ऐसे शोध को सहयोग नहीं देती जो हावी आख्यानों को चुनौती देते हों।

नृजातीयता को केंद्र में रखने से ईरानी समाजशास्त्र को अपने अपवादों का सामना करने, हावी राष्ट्रीय कल्पना को चुनौती देने और जीवंत अनुभवों की बहुलता को पहचानने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह ईरानी राज्य की ज्यादा जमीनी समझ को भी बढ़ावा देता है – जो न सिर्फ क्रांति और विचारधारा से बल्कि विवादित भौगोलिकता, परिधीय इतिहास और सम्प्रभुता के लिए संघर्षों से भी आकारित होता है। ■

संपर्क करें:
अघिल दघघेलेह <aghil.daghagheleh@unco.edu>

> स्थित जीवन, विवादित ज्ञान:

ईरान में जेंडर अध्ययनों को पुन: हासिल करना

शिवा अलीनाकियान, स्वतंत्र शोधकर्ता, ईरान द्वारा

योनेसु द्वारा चित्रण

तेहरान के विश्वविद्यालयों में जेंडर, नृवंशविज्ञान और वृतांतों पर आठ वर्षों तक पाठ्यक्रम पढ़ाने के दौरान, मेरा निजी अनुभव लगातार संस्थागत बाधाओं और रोजमर्रा की राजनीति से उलझा रहा। 2022 में मेरा शिक्षण पद से निकाला जाना – ठीक उसी समय जब वुमन, लाइफ, फ्रीडम (जीना) विद्रोह शुरू हुआ – सिर्फ एक निजी/व्यक्तिगत अनबन नहीं था, बल्कि इसने यह भी स्पष्ट कर दिया कि ईरान में जेंडर पर आलोचनात्मक ज्ञान का उत्पादन शक्ति संबंधों और रोजमर्रा के विरोध के तरीकों से कैसे जुड़ा हुआ है। इन हालातों में, छोटे छोटे शैक्षणिक निर्णय–जैसे विद्यार्थियों को मिनी–नृवंशविज्ञान वर्णन लिखने के लिए आमंत्रित करना, जिए गए अनुभवों को अग्रभाग लाना, या स्थानीय आख्यानों के साथ वैश्विक नारीवादी सिद्धांतों पर चर्चा करना – बहुत अधिक राजनैतिक हो जाते हैं: वे संस्थागत अपेक्षा कि जेंडर कानूनी–प्रशासनिक या "सुरक्षित" पारिवारिक नीति फ्रेमवर्क तक ही सीमित रहे, को अस्थिर करते हैं।

तो, कक्षा कोई सुरक्षित अकादमिक स्थान जगह नहीं है; यह एक ऐसी जगह है जहाँ राज्य के अनुशासनात्मक तर्क और अपनी जिंदगी को समझने की विद्यार्थियों की इच्छा टकराती है। मेरे बर्खास्तगी ने उसी बात को उजागर किया जिसे कई प्रशिक्षक पहले से ही जानते थे: ईरान में जेंडर ज्ञान जोखिम है क्योंकि यह रोजमर्रा की जिंदगी से निकलता है, उसके बावजूद नहीं।

> ईरान में जेंडर अध्ययनों का कालक्रम: ऊपर से बना एक विषय

ईरान में जेंडर अध्ययनों में प्रयोग में लिए जाने वाले पढ़ाने के तरीकों के असर को समझने के लिए, उन्हें इस क्षेत्र की स्थानीय इतिहास में स्थित करना होगा। ईरान में जेंडर अध्ययन किसी खुले या स्वायत्त अकादमिक माहौल में शुरू नहीं हुए, बल्कि ऐसे माहौल में विकसित हुए जहाँ सामाजिक विज्ञान पर पहले से ही बहुत ज्यादा पाबंदियाँ थीं और राजनैतिक रूप से उन पर नजर रखी जा रही थी। सांस्कृतिक क्रांति का साया – 1980 और 1983 के मध्य विश्वविद्यालयों की पुनःसंरचना – आज भी ईरान में शैक्षणिक जीवन को प्रभावित करता है। मानविकी के विभागों की जांच की गई, पाठ्यचर्या पुनः लिखे गए, और जिन विषयों को संभावित रूप से हानिकारक माना गया, उन पर सख्ती से नियमन किया गया। शक के इसी माहौल में जेंडर अध्ययन का जन्म हुआ था।

इक्कीसवीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में, इस क्षेत्र को आधिकारिक रूप से राज्य–परियोजना के तौर पर लॉन्च किया गया था। मुख्य विश्वविद्यालयों में महिला अध्ययन पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये गए थे। शुरू से ही, इसका मकसद नारीवादी आलोचना को बढ़ावा देना नहीं था, बल्कि ज्ञान के उस क्षेत्र का नियमन करना था जो समाज में दर्शनीय हो रहा था। जैसे–जैसे महिलाओं की सक्रियता बढ़ी और जेंडर बहस सार्वजनिक जीवन में आई, सरकार ने 'महिला मुद्दों' का किन शर्तों पर अध्ययन किया जा सकता है को तय करके इस ऊर्जा को नियंत्रित करने का कार्य किय। यह विषय सामाजिक चिंताओं को आलोचनात्मक जांच में विकसित होने देने के बजाय विधि–प्रशासनिक और परिवार–केंद्रित फ्रेमवर्क में डालने का एक तरीका बन गया।

इस्लामिक मदरसों ने इस तनाव को और अधिक दर्शनीय बना दिया। इन धार्मिक जगहों में नारीवादी सिद्धांत प्रवेश कर गए, लेकिन सिर्फ इस्लामिक कानून के दायरे में। उन्हें जेंडर संस्तरण पर पुनः विचार करने के लिए नहीं, बल्कि "प्राकृतिक भूमिकाओं" की पुष्टि करने, सैद्धांतिक सीमाओं का बचाव करने, या धार्मिक आपत्तियों को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। विश्वविद्यालयों और मदरसे, दोनों में, नारीवादी संबोध फैले, लेकिन हमेशा ऐसे हालात में जिन्होंने उनके बदलने की क्षमता को बेअसर कर दिया।

इन संस्थागत चयनों को सामाजिक विज्ञानों को अधिशासित करने वाले व्यापक ज्ञानमीमांसीय व्यवस्था ने अधिक मजबूत किया। प्रत्यक्षवाद और शास्त्रीय मात्रात्मक पद्धतियों ने संस्थागत संस्तरण पर अपना दबदबा बनाया। इन्होने जिसे वैध ज्ञान माना जाता है उसे आकारित किया और जीवित अनुभव या मूर्त रूप पर आधारित दृष्टिकोणों को 'अवैज्ञानिक' कहकर खारिज किया। यह संस्तरण राज्य की एक वि–राजनैतिक, प्रशासनिक रूप से उपयोगी विषय की इच्छा के साथ जुड़ा हुआ था।

>>

> महत्वपूर्ण कमियों के मध्य, जमीनी ज्ञान और नीचे से प्रतिरोध ने अवसर खोले

एक बुनियादी कमी ने इस विषय को और बेहतर बनायाः क्वीर थ्योरी, जिसे कानूनी और अकादमिक तौर पर बहुत कमजोर कर दिया गया, को लगभग पूरी तरह से बाहर रखा गया। इस कमी ने जेंडर अध्ययनों को ऐसे परस्परछेदित विश्लेषण विकसित करने से रोक दिया जो जेंडर को कामुकता, कामना, नातेदारी और गैर–प्रतिमानात्मक अभिव्यक्ति से जोड़ सकें। इसके सामानांतर, अंग्रेजी भाषी उदारवादी नारीवाद – जिसे बिना किसी सामाजिक आधार के आयात किया गया था, के दबदबे ने इस क्षेत्र को व्यक्तिगत और माध्यम–वर्गीय चिंताओं तक सीमित कर दिया। अल्पसंख्यकों और अधीनस्थ महिलाओं की जिंदगी को बनाने वाले संरचनात्मक हालात को सम्बोधित करने के लिए जहाँ यह ढांचा अपर्याप्त था, लेकिन इसने मध्यम–वर्ग के सन्दर्भ में उन चुनौतियों को सामने ला दिया जो अभी भी अनसुलझी हैंः प्रजनन और देखभाल सम्बन्धी कार्य का निरंतर अवमूल्यन, विधिक जोखिम, और निर्धनता का स्त्रीलिंगीकरण। इन ताकतों ने मिलकर एक ऐसा विषय बनाया जो नाम के लिए तो है लेकिन सार में सीमित है; जिसे अब अपने नजरअंदाज निर्वाचन क्षेत्र और अपने परिकल्पित केंद्र के अंदर मौजूद असमानताओं से एक साथ जूझना होगा।

फिर भी, भले ही अकादमिक क्षेत्र संकीर्ण रहा, लेकिन सामाजिक तौर पर इसकी अहमियत थी। यद्यपि, विश्वविद्यालयों के अंदर महिला अध्ययन कभी भी पूरी तरह से समेकित नहीं हुए, लेकिन इक्कीसवीं सदी के प्रारम्भ से यह महिला सक्रियता के साथ गहराई से जुड़ गए। NGOs, परोपकारी संघों, साहित्यिक कृतियों, अभियानों और शांत विरोध के दैनिक कृत्यों के जरिए, महिलाओं ने विश्लेषण और विवेचना के अपने तरीके बनाए। ज्ञान के ये जमीनी स्तर के तरीके ऊपर से बनाए गए अकादमिक संरचना के साथ तनाव में मौजूद थे।

इस इतिहास ने दो परस्पर विरोधी ताकतों द्वारा आकारित एक विषय उत्पन्न कियाः ऊपर से नियमित और नीचे से प्रतिरोध। इस दुहरी गतिकी – राज्य नियंत्रण और नारीवादी नवाचार – ने ईरान में जेंडर अध्ययनों की दिशा तय की है और सामाजिक ज्ञान की सीमाओं पर फिर से सोचने के मौके खोल रहा है।

> नियमन से पुनः प्राप्ति तक : ईरान में जेंडर अध्ययन का पुनर्निर्माण

ईरान में जेंडर अध्ययन को लंबे समय से बनाए रखने वाली संस्थागत बाधाओं के खिलाफ, नारीवादी विद्वान, विद्यार्थी और कार्यकर्त्ताओं ने – अक्सर चुपचाप, अक्सर पर्सनल रिस्क पर – उसी बौद्धिक स्थान को वापस पाने के लिए जिससे उन्हें बाहर रखा गया था, लगातार काम किया है। मेरी अपनी कक्षा में, यह प्रतिरोध उन असाइनमेंट में दिखाई दिया जिन्हें स्टूडेंट्स ने लिखने के लिए चुनाः देखभाल कार्य के विवरण, अंतरंगता, गतिशीलता, और जेंडर आधारित जिंदगी को आकार देने वाले छोटे–छोटे नियमों के बारे में। ये सिर्फ अभ्यास नहीं थेय ये ज्ञान के ऐसे विद्रोही रूप थे जो इस क्षेत्र को घरेलू बनाने के खिलाफ थे।

विश्वविद्यालय के बाहर, महिला अधिकार कार्यकर्ताओं, NGO आयोजक, कुर्द, अरब और बलूची नारीवादी, प्रवासी महिलाओं और अनगिनत दूसरे लोगों ने सरकार के तय पाठ्यक्रम के बजाय, संघर्ष पर आधारित विश्लेषणात्मक फ्रेमवर्क बनाए। इस लंबे समय से चले आ रहे काम ने जीना विद्रोह के बाद आए बड़े बदलाव की नींव रखी।

ईरानी कुर्दिस्तान से शुरू हुए जीना क्षण ने एक नई नारीवादी सोच को आसान बनायाः परस्परच्छेदन, वि–औपनिवेशिक और पारदेशीय सोच का अभिमुखन। यह कुर्द, बलूची, अरब और प्रवासी महिलाओं के बीच दशकों के संगठन से आया, जिन्होंने लंबे समय से पितृसत्तात्मकता, सैन्यवाद, नृजातीय हाशियेकारण और आर्थिक वंचन के परस्पर कटाव की व्यवस्था का सामना किया था। उनके संघर्षों ने तेहरान–केंद्रित नारीवाद को प्रान्तीयकृत किया और यह दिखाया कि जेंडर नृजातीयता, वर्ग, हिंसा और औपनिवेशिकता से कैसे जुड़ा हुआ है।

यह उभरती हुई नारीवादी चेतना स्थानीयता में जड़ है, फिर भी हिंसा और एकजुटता के वैश्विक सर्किट पर ध्यान देती है। यह मानती है कि रोजहेलात और सिस्तान–बलूचिस्तान के संघर्ष फिलिस्तीन और अफगानिस्तान के संघर्षों से मिलते–जुलते हैं, और जिंदगी और इज्जत की मांग हमेशा ट्रांसनेशनल होती है। यह जेंडर अध्ययनों को चुनौती देती है कि वह अपनी राज्य–आकारित शुरुआत से हटकर, नीचे से एकजुटता के आस–पास, शरीर, समुदाय और रोजमर्रा के जीवन से निकलने वाले ज्ञान के आस–पास खुद को फिर से बनाए।

> एक ऐसे समाजशास्त्र को बनाने की आवश्यकता है जो जीते–जागते अनुभव पर आधारित हो और सामूहिक बदलाव के लिए समर्पित हो

इसके आलोक में, मेरी पदच्युति कोई एक अकेली घटना नहीं थी, बल्कि यह ज्ञान कौन बनाएगा और ज्ञान के किस रूप को रहने दिया जाएगा के ऊपर हो रहे व्यापक संघर्ष का एक लक्षण थी। यह हमें स्मरण कराती है कि जेंडर अध्ययनों को पुनः प्राप्त करने के लिए हमें आख्यानों, देखभाल, और जमीनी जांच के उन रूपों को केंद्र में लाना होगा जिन्हें लंबे समय से परिधीय माना जाता रहा है।

यहां से, नारीवादी व्यवहार जेंडर अध्ययनों के विकल्प के तौर पर नहीं, बल्कि उसके पुनर्भिमुखन के तौर पर सामने आते हैं। यह एकजुटता की एक क्षेत्रीय नैतिकता को आगे बढ़ाती है जो अल्पसंख्यक, अफगान और फिलिस्तीनी संघर्षों को बिना दुख की संस्तरण को पैदा किए एक साथ रखती है। इस परिदृश्य में, जेंडर अध्ययन सुनने, अनुवाद करने और हाशिए पर पड़े लोगों की जिंदगी को दिखाने के जुड़े हुए व्यवहार के तौर पर उभरते हैंः एक ज्ञान–मीमांसा जो मौजूद होने के बावजूद अलग–अलग है; जो संदर्भ में निहित है, फिर भी विषय, राष्ट्रीय और पहचान की सीमाओं को पार कर सकती है। इसका भविष्य संस्थागत पहचान पर नहीं, बल्कि लोगों के लिए एक समाजशास्त्र, जो जीते–जागते अनुभव पर आधारित हो और सामूहिक बदलाव के लिए समर्पित हो, को बनाने और लागू करने की इसकी क्षमता पर निर्भर करता है। ■

संपर्क करेंः
शिवा अलीनाकियान <sh_alinaghian@yahoo.com>

> दबाब के अंतर्गत: ईरान पर समाजशास्त्रीाय शोध

एक राउंड टेबल

श्रेयः हैंस–पीटर गॉस्टर, अनस्प्लैश के जरिए।

यह राउंडटेबल ईरान पर काम करने वाले छह समाजशास्त्रियों को एक साथ लाती है, जो अलग–अलग भू–राजनैतिक जगहों पर विशिष्ट अकादमिक क्षेत्रों और संस्थानात्मक सन्दर्भों में स्थित थे। जहाँ वे समाजशास्त्र विषय में अपने प्रशिक्षण के कारण एक दूसरे से जुड़े थे, योगदानकर्त्ता ईरान के भीतर और बाहर अपनी जगहों से आकारित विभिन्न आस्थापकता लेकर आते हैं और राष्ट्र, भाषा एवं सांस्थानिक सीमाओं के पार ज्ञान का सृजन करते हैं। राउंड टेबल ईरान में समाजशास्त्रीय शोध करने की चुनौतियों, नवाचार और नैतिक मुश्किलों की जांच करने के लिए तीन मुख्य पद्धतिया प्रश्नों पर विमर्श करता है। हालांकि उनका शोध शहरी जीवन, शिक्षण नीति, डिजिटल सक्रियता और पर्यावरणीय न्याय जैसे कई विषयों पर फैला हुआ है, फिर भी सभी योगदानकर्ता जमीनी, आलोचनात्मक और प्रतिवर्तनीय संलग्न जांच के लिए प्रतिबद्ध हैं। राजनीतिक पाबंदी, ज्ञान को मिटाने, संस्थागत रुकावटों और ज्ञान पैदा करने के वैश्विक संस्तरण के मध्य प्रत्येक ईरानी समाज पर शोध करने के मुश्किल रास्ते पर चलता है। योगदानकर्ताओं के बारे में संक्षेप में इस तरह बताया जा सकता है।

नफीसेह आजाद ईरान में रहने वाली एक सामाजिक शोधकर्ता

>>

हैं, जिनका काम गुणात्मक पद्धति द्वारा जेंडर और शहरी जीवन पर फोकस करता है। शहरी हाशिए पर रहने और सामाजिक दुख–तकलीफों पर शोध करने वाली ईरान में रहने वाली **माराल लतीफी**, तेहरान में नीचे की ओर गतिशीलता की जांच करती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनोइस (USA) में PhD अभ्यर्थी महबूबेह मोगादम, युवा सक्रियता, सौंदर्यशास्त्र, और राजनैतिक व्यक्तिपरकता का अध्ययन करने के लिए ट्रांसनेशनल नारीवादी सिद्धांतों का प्रयोग करती हैं। ईरान में रहने वाली शिक्षा और सामाजिक नीति की विद्वान फतेमेह मोगादसी, शिखा के निजीकरण, बाल श्रम और गरीबी हटाने की पहलों की जांच करती हैं। लादन रहबारी, यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टर्डम (नीदरलैंड्स) में समाजशास्त्र की सह–आचार्य हैं, (डिजिटल) विमर्श और जेंडर और प्रतिरोध की राजनीति की छानबीन करती हैं। रेजा सोहराबी, कार्लटन यूनिवर्सिटी, ओटावा (कनाडा) में PhD अभ्यर्थी हैं, जो पर्यावरणीय राजनीति और पानी की कमी की जांच करती हैं।

ये विद्वान मिलकर तीन मुख्य मुद्दों पर काम करते हैं: निगरानी और सीमित पहुँच के हालात में ईरान का अध्ययन करने के तरीकों की रुकावटों को कैसे पार करें, राजनैतिक संवेदनशीलता और जोखिम के मध्य कौन से नैतिक फ्रेमवर्क उनके काम को मार्गदर्शन देते हैं; और वैश्विक शक्ति गतिशीलता ज्ञान उत्पादन के हालात और संस्तरण को कैसे आकार देते हैं। ये प्रश्न रेहानेह जावदी और नाजनीन शाहरोकनी ने पूछे, जिन्होंने बातचीत को फ्रेम किया और संवाद को गाइड किया।

रेहानेह जावदी (RJ) और नाजनीन शाहरोकनी (NS): आइए उन चुनौतियों से शुरू करते हैं जो शोध की संभावनाओं को आकार देती हैं। ईरान पर शोध करने में आपको कौन सी खास पद्धतिगत रुकावट का सामना करना पड़ा, और आपने उससे कैसे निपटा या उसके हिसाब से खुद को ढाला? राजनीतिक रूप से सीमित या अस्पष्ट माहौल में समाजशास्त्र के अभ्यास के बारे में यह अनुभव क्या व्यापक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है?

नफीसेह आजाद: मेरा हालिया शोध महिलाओं और शहरी जीवन के मेल पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें महिलाओं के अनुभवों को जानने के लिए गुणात्मक पद्धति का इस्तेमाल किया गया है। इस काम को दो लगातार रुकावटों ने दिशा दी है; डेटा तक सीमित पहुंच और ईरान में महिलाओं के मुद्दों को लेकर बढ़ती राजनैतिक संवेदनशीलता।

सामाजिक शोध में, विशेषकर जेंडर से जुड़े क्षेत्रों में, भरोसेमंद डेटा तक पहुंच एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। खास आंकड़े – जैसे कि आत्मा–दाह या ऑनर किलिंग पर – अक्सर गोपनीय होते हैं या अप्राप्य। ईरान के सांख्यिकीय केंद्र से मिले आंकड़ों और अर्ध–सरकारी या निजी संगठनों के जारी किए गए आंकड़ों को ट्राईएंगुलेट करके, मैं इन दिक्कतों के बावजूद आंशिक जानकारी निकाल पाया हूँ।

दूसरी बाधा ईरान में आधिकारिक और सार्वजनिक संस्कृति के मध्य बढ़ते अंतराल से आती है, जिसने स्वतंत्र राष्ट्रीय–स्तर के शोध रिसर्च के लिए संभावना और अधोसंरचना दोनों को खत्म कर दिया है। संवेदनशील विषयों पर काम करने को तैयार स्वतंत्र संस्थाएं कम हैं, लेकिन वे विश्वविद्यालय व्यवस्था के बाहर जरूरी मौके देते हैं। महिलाओं की आर्थिक एजेंसी पर मेरी सबसे हालिया अध्ययन ऐसे ही एक संस्थान के जरिए की गई थी।

राजनैतिक संवेदनशीलता लगातार थीमैटिक सीमायें लगाती रहती हैं: कुछ विषय अभी भी निषिद्ध हैं। फिर भी, पहुँच योग्य आबादी और कार्यक्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके, और पद्धति में नवाचार करके, मैं व्यापक समाजशास्त्रीय निहितार्थ वाले गहन गुणात्मक आंकड़ों का सृजन कर पाया हूँ। जहाँ सार्वजनिक प्रसार सीमित रहता है, खासकर अकादमिक शोध पत्रिकाओं के बाहर, इस उपागम ने मुझे प्रतिबंधित परिस्थितियों में विवेचनात्मक जांच को बनाए रखने में मदद की है।

फतेमेह मोगादासी: महिलाओं के मुद्दों पर भरोसेमंद आंकड़े मिलने में मुश्किल पर नफीसेह के विचार, सामाजिक नीति बनाने पर शोध करने के मेरे अपने अनुभव से मेल खाते हैं। मेरे काम में, मुझे जो मुश्किलें आई हैं, वे सांस्कृतिक निषेधाज्ञाओं से कम और गहरी संस्थागत सीमाओं से ज्यादा जुड़ी हैं, जो इस क्षेत्र का निर्माण करती हैं।

सामाजिक नीतिनिर्माण शोधकर्त्ताओं और नीति निर्माताओं के मध्य लगातार बातचीत पर निर्भर करता है, फिर भी ईरान में यह रिश्ता काफी कमजोर है। नीति निर्माताओं द्वारा आनुभविक अध्ययन की न्यून मांग के साथ मिलकर अमूर्त दार्शनिक उपागमों के दबदबे ने शोधकर्त्ताओं को अलग–थलग कर दिया है और ज्ञान के उत्पादन और निति क्रियान्यन के मध्य का लिंक तोड़ दिया है। इस विसंबंधन ने शैक्षणिक असमानता और सार्वजनिक शिक्षा के निजीकरण पर मेरी शोध को आकार दिया है, जहाँ मुझे बार–बार पद्धतिशास्त्रीय रुकावटों का सामना करना पड़ा है।

पहला, सूक्ष्म–स्तरीय डेटा तक पहुंच का मुद्दा है। शैक्षणिक असमानता के प्रभावी विश्लेषण करने के लिए, ऐसे डेटा की जरूरत होती है जो विद्यार्थियों के व्यक्तिगत, पारिवारिक और पर्यावरणीय सन्दर्भ दर्शाते हों। ईरान में, ऐसा डेटा दुर्लभ है, असंगत रूप से रिपोर्ट किया जाता है, और आमतौर पर सिर्फ राष्टीय या प्रांतीय स्तर पर ही मिलता है। शिक्षा मंत्रालय जैसी संस्थाओं के द्वारा विस्तृत डेटा पाने के लिए औपचारिक तंत्र या तो अनुपस्थित हैं या बेअसर हैं। यह शोधकर्त्ताओं को अनौपचारिक चौनल या निजी नेटवर्क्स पर निर्भर रहने के लिए दबाब डालता है– ये तरीके न सिर्फ अरक्षणीय हैं बल्कि नैतिक रूप से भी कमजोर भी हैं।

दूसरा, सर्वे डेटा पर सरकारी नियंत्रण एक बड़ी रुकावट है। 1990 के दशक से, कई बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय और छोटे अभिवृत्तिक सर्वेक्षण किए गए हैं, जिनमें ज्यादातर सरकारी संस्थाओं द्वारा वित्तपोषित हुए हैं। फिर भी, परिणामी आंकड़े स्वतंत्र शोधकर्त्ताओं के लिए अनुपलब्ध रहते हैं। फील्ड डेटा पर इस तरह का एकाधिकार ईरानी सामाजिक विज्ञानों में भरोसेमंद स्त्रोतों की व्यापक कमी में योगदान देता है।

आखिर में, शोध के क्षेत्रों तक पहुंच भी लगातार कम होती जा रही है। मंत्रालयों से आधिकारिक स्वीकृति लेकर काम करने पर भी, स्कूल में अवलोकन, साक्षात्कार या आंकड़ा संग्रहण के अन्य तरीकों को करने की कोशिशें अक्सर अफसरशाही बाधाओं या संशय का सामना करती हैं। शैक्षणिक माहौल को राजनैतिक रूप से संवेदनशील जगह माना जाता है, जिससे बुनियादी आनुभविक कार्य करना भी मुश्किल हो जाता है। फलस्वरूप, शोधकर्त्ताओं को अक्सर दस्तावेजों या द्वितीयक विश्लेषण पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे गुणात्मक अन्वेषण का क्षेत्र और गहनता सीमित हो जाती हैं।

ये बाधाएं न सिर्फ यह तय करती हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बल्कि ईरान में आनुभविक–अध्ययन आधारित नीति शोध

>>

ईरान का राष्ट्रीय पुस्तकालय
श्रेयः विकिमीडिया कॉमन्स

करने की संभावना पर भी असर डालती हैं।

लादान रहबारीः फतेमेह की तरह, मुझे भी ऐसे डेटा से जूझना पड़ा है जो आसानी से नहीं मिलता या अधूरा है, लेकिन जिस फतेमेह की तरह, मुझे भी ऐसे अनूपलब्ध या अपूर्ण डाटा से जूझना पड़ा है, लेकिन जिस संस्थागत दूरी के बारे में वे बताती हैं, वह तब अलग रूप ले लेती है जब कोई बाहर से काम कर रहा हो और जिसे क्षेत्र तक आसान या सुरक्षित पहुंच न हो। ईरान के बाहर से शोध करने से जटिलता की एक अतिरिक्त परत और बढ़ जाती है। विरोध और असहमति के डिजिटल विमर्श पर अपने काम से मैं आपको इसका एक उदाहरण दे सकता हूं।

मेरे एक मौजूदा प्रोजेक्ट में, मैंने 2022 में "औरत, जिंदगी, आजादी" विद्रोह के दौरान और उसके बाद परिसंचरित फारसी भाषा के ट्विटर पोस्ट का विश्लेषण किया। मुझे विद्रोह को समाजशास्त्रीय अर्थ से समझने और इसे अध्ययन करने के लिए स्वयं को तैयार करने में समय लगा, खासकर एक शोधकर्ता, जो पेशेवर और निजी पर्सनल तौर पर इस विषय से करीब महसूस करता है, लेकिन वह घटनाओं के केंद्र से बहुत दूर, नीदरलैंड्स में रह रहा है।

इस विशिस्ट प्रोजेक्ट में मेरा ध्यान इस बात पर रहा है कि फारसी बोलने वाले लोग धर्म के बारे में अपनी भावनाएं कैसे जाहिर करते हैं। मेरे सामने एक लगातार पद्धतीय चुनौती रही है कि धर्म के तौर पर इस्लाम की आलोचनाओं को एक राजनैतिक व्यवस्था के तौर पर इस्लामिक गणतंत्र की आलोचनाओं से कैसे अलग किया जाये। यह एक विश्लेषणात्मक समस्या है जो ईरान और धर्म और धार्मिकता पर लोकप्रिय बहस पर काम करने वाले कई लोगों के लिए जानी–पहचानी हो सकती है। मैंने देखा है कि डेटा को स्पेक्ट्रम के दो पक्षों में से किसी एक के पक्ष में अति–व्याख्या करने की प्रवृति होती है।

यदि मेरे पास क्षेत्र तक सीधी पहुँच होती तो मैं प्रयोजन और विवेचना को और अधिक स्पष्ट करने के लिए संवाद विश्लेषण के साथ बड़े पैमाने पर गुणात्मक–संख्यात्मक सर्वेक्षण करता। मुझे पता है कि रिमोट सर्वेक्षण तकनिकी रूप से संभव हैं, लेकिन दूसरे देश से ऑनलाइन उपकरण का इस्तेमाल करके उन्हें करने में कई मुश्किलें और पूर्वाग्रह आते हैं। इसके अतिरिक्त, जैसा कि ईरान के विद्वान अच्छी तरह जानते हैं, व्यापक ईरानी आबादी के लिए प्रवासी एक भरोसेमंद प्रॉक्सी के तौर पर काम नहीं कर सकते। इसलिए, मेरे पास काम करने के लिए सिर्फ अधूरे उपकरण हैं।

बेशक, इन चुनौतियों से निपटने के तरीके हैं। उदाहरण के लिए, मुझे सह–पाठकों और सहयोगपूर्ण व्याख्या के साथ–साथ सदस्य–जांच तकनीक जैसे दूसरे तरीकों पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन फिर भी, मेरा मानना है कि ये रणनीतियां, चाहे कितनी भी मूल्यवान हों, ईरान में किए गए एक ठोस और प्रतिनिधी सर्वेक्षण की सख्ती और पहुंच की पूरी तरह से जगह नहीं ले सकतीं। एक लक्षित रिमोट सदस्य–जांच तरीका शायद कुछ हद तक मदद कर सकता है; लेकिन यह विवेचना से जुड़ी उलझनों को पूरी तरह से हल नहीं कर सकता। यह उन कई पद्धतियों सीमाओं और चुनौतियों का सिर्फ

> >

एक हालिया उदाहरण है जिन्हें मुझे अपने शोध में पहचानना और उन पर काम करना आवश्यक है।

महबूबेह मोगादमः फील्ड से दूरी और यात्रा पर लगी पाबंदियों से होने वाली दिक्कतों के बारे में लादान की चिंताओं को दोहराते हुए, मुझे 'फील्ड में होने' का क्या मतलब है को फिर से परिभाषित करना पड़ा। वुमन, लाइफ, फ्रीडम मूवमेंट में ळमद ि की भूमिका पर शोध करते समय मेरे सामने आई सबसे बड़ी पद्धतिया चुनौती में से एक यह रही है कि मैं ईरान जाकर खुद क्षेत्र–कार्य नहीं कर पाया। इस कमी ने रोजमर्रा की अंतर्क्रिया और अनौपचारिक बातचीत तक पहुंच को कम कर दिया है, जो नृवंशविज्ञानी शोध के लिए बहुत जरूरी हैं।

इस आंदोलन ने जेंडर पर आधारित हिंसा और तानाशाही शासन के खिलाफ पूरे ईरान में युवाओं के विरोध को बढ़ावा दिया। इस विषय को त्यागने के बजाय, मैंने डिजिटल एथनोग्राफी की ओर रुख किया। मैं खुद को इस तरीके में प्रक्षिक्षित कर रहा हूं और मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, न्यूज कवरेज और डिजिटल अभिलेखागार से व्यवस्थित तरीके से डेटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। इस डिजिटल तरीके को बेहतर बनाने के लिए, मैं स्नोबॉल निदर्शन के जरिए एक ट्रस्ट नेटवर्क बना रहा हूं – ईरान में अभी मौजूद लोगों के साथ–साथ हाल ही में देश छोड़ने वालों के साथ ऑनलाइन साक्षात्कार और अनौपचारिक बातचीत कर रहा हूं। मैं ईरान और अमेरिका के मध्य यात्रा करने वाले लोगों से भी नियमित बात करता हूं, उनसे खास सवाल पूछता हूं और उनके विचारों को इकट्ठा करता हूं। ईरान में मित्र मुझे हालिया शोध और अकादमिक थीसिस तक पहुंचने में मदद करते हैं।

यद्यपि, यह प्रोजेक्ट अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन इस अनुकूली, बहु–स्त्रोत वाली रणनीति ने मुझे उन स्थानीय कर्त्ताओं की रोजमर्रा की जिंदगी और नजरिए के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में मदद की है जिनका मैं अध्ययन करता हूँ, जिससे शारीरिक गैर–मौजूदगी के बावजूद इस क्षेत्र की ज्यादा गहरी और बारीक समझ मिलती है।

रेजा सोहराबीः महबूबेह का डिजिटल एथनोग्राफी और उपाख्यानों लेखों की ओर रुख मुझे याद दिलाता है कि आज पहुँच सिर्फ प्रतिभागियों के साथ संबंधों पर ही नहीं, बल्कि खुद तरीकों पर भी निर्भर करता है। मेरे मामले में, भरोसा बनाना सिर्फ शोध के लिए जरूरी नहीं था, बल्कि यह स्वयं में एक तरीका बन गया।

मेरा PhD शोध ईरान में पानी की कमी और सामाजिक आंदोलनों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह इस्फहान और खुजेस्तान प्रांतों का एक तुलनात्मक अध्ययन है, जहाँ मैं पानी की राजनीति के बारे में विद्व ानों, कार्यकर्त्ताओं और किसानों का साक्षात्कार करता हूँ। शेत्राकार्य में बढ़ाएं काफी अधिक रही हैं, विशेष रूप से जब प्रतिभागियों के चयन की बात आती है।

महबूबेह की तरह, विदेश से पढ़ाई करने की वजह से साक्षात्कार करने के लिए भरोसा बनाना बहुत जरूरी हो गया है। इससे निपटने के लिए, मैंने स्नोबॉल निदर्शन पर बहुत ज्यादा भरोसा कियाः पहचान को छुपाने के लिए यह बताये बिना कि मैं आगे कार्यवाही करूँगा या नहीं, सुझाव और अनुशंसा माँगना। मुझे समुदाय के साथ संलग्नता भी एक खास प्रभावी रणनीति लगी। साक्षात्कार से पहले प्रतिभागियों के साथ खुला संवाद करने से मेरे प्रोजेक्ट की अकादमिक प्रकृति और मकसद को बताने में मदद मिली। एक बार जब उन्हें अपने योगदान की अहमियत समझ में आ गई, तो कई लोग हिस्सा लेने के लिए उत्सुक हो गए।

राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों में, शोध के लिए स्थानीय तौर तरीकों की जरूरत होती है; वे जो शोधकर्त्ता में प्रतिभागियों के भरोसे पर और प्रोजेक्ट की उपयोगिता में उनके विश्वास पर निर्भर होते हैं। मेरे लिए, सम्प्रेषण और सामुदायिक संलग्नता सिर्फ पहुँच के उपकरण के तौर पर नहीं, बल्कि दबाव में नैतिक और असरदार तरीके से शोध करने के मुख्य हिस्से के तौर पर उभरे हैं।

मराल लतीफीः संवेदनशील शोध स्थितियों में भरोसे की नाजुकता के बारे में जो रेजा उजागर करती हैं, वो अत्यंत आवश्यक है। मेरे डॉक्टोरल शोध निबंध में तेहरान में मध्यम–आय समूहों की नीचे की ओर गतिशीलता को बॉर्डियूसियन फ्रेमवर्क के जरिए जांचा गया, जिसमें ईरान के हाल के आर्थिक संकटों के तहत सामाजिक दुख और स्थानीय विस्थापन के बीच की उलझन पर ध्यान केंद्रित किया गया। आनुभविक रूप से, शोध कार्य में इस रास्ते पर चल रहे 32 लोगों के साक्षात्कार लिए गए, जिनमें से 25 विश्लेषणात्मक कोर थे। दो मुख्य पद्धतीय चुनौतियों के लिए एक प्रतिवर्तनीय, सम्बन्ध् ाात्मक बॉर्डियूसियन उपागम की जरूरत थी। पहला, प्रतिभागियों से सामाजिक दुख के पुराने और जमे हुए रूपों को बताने के लिए कहा गया – जिसे बॉर्डियू ने मिजरे डू मोंडे कहा था – जो कई सालों में सामने आए। दूसरा, ये अनुभव निर्धनीकरण की प्रक्रिया से बहुत करीब से जुड़े थे, जो मध्यम वर्ग के लिए एक विशिष्ट एक कलंक है।

इस द्विबंधन से साक्षात्कार के सिर्फ फॉर्मूला वाली बातचीत में बदलने का जोखिम था, या, ज्यादा विवेचनात्मक रूप से, शोध समागम स्वयं में संरचनात्मक हिंसा का पुनरुत्पादन हो सकता थ। नुकसान और विस्थापन की इन आख्यानों से नैतिक रूप से जुड़ने के लिए एक सावधान, भरोसे पर आधारित पद्धति आवश्यक थी।

आरजे और एनएसः आपके विचारों से यह बात सामने आती है कि पद्धति कभी भी सिर्फ तकनीक का मामला नहीं होती, यह शोध के खुलासा होने की स्थितियों से आकारित होती है; जहाँ पहुँच अनिश्चित होती है, जानकारी रोकी जाती है, और क्षेत्र स्वयं भी अस्थिर रहता है। इन हालातों को देखते हुए, ईरान पर आपके कार्य में, आपने जोखिम से जुड़े नैतिक तनावों को कैसे संभाला है, चाहे वे आपके लिए, आपके संभाषी के लिए, या आपके डेटा के लिए हो? किन नैतिक सिद्धांतों ने आपके फैसलों का मार्गदर्शन किया है, और वे किन तरीकों से शोध नैतिकता के मुख्य ढाँचों को जटिल बना सकते हैं या चुनौती दे सकते हैं ?

लादन रहबरीः ईरान पर काम करने वाले कई समाजशास्त्रियों की तरह, मैं भी अपने सम्भाषियों के, और स्वयं के लिए और मेरे साथ या मेरे लिए काम करने वाले दूसरे शोधकर्त्ताओं के लिए भी सुरक्षा ओर गोपनीयता के जटिल प्रश्नों से लगातार जूझता रहता हूँ। लेकिन हाल ही में मेरे सामने आई सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक, अध्ययन के क्षेत्र या ईरानी सरकार से नहीं, बल्कि मेरे अपने विश्वविद्यालय के नैतिकता समीक्षा प्रक्रिया से आई है।

जिस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने अपने पूर्व कमेंट में बताया था, उसके लिए फंडिंग के लिए आवेदन करने और उसे पाने के बाद, मेरे विश्वविद्यालय के एथिक्स बोर्ड ने इसे उच्च–जोखिम वाला बताया। उन्होंने यह इस आधार पर कहा कि ईरानी लोगों के साथ कोई भी संपर्क ईरानी सरकार के (रिमोट) निगरानी व्यवस्था को मुझे, मेरे संस्था, और उन ऑनलाइन सोशल मीडिया उपयोगकर्त्ताओं को टारगेट करने के लिए ट्रिगर कर सकता है जिनका मैं अध्ययन करता हूँ। मैं मानता हूँ कि ये चिंताएँ पूरी तरह से बेबुनियाद नहीं थीं, और मैं भी निश्चित रूप से उनमें से कुछ को साझा करता हूँ।

>>

लेकिन इन सुरक्षा मुद्दों को कम करने के लिए जो प्रोटोकॉल सुझाए गए थे, वे अच्छी तरह से जानकारी वाले नहीं थे और उनसे शोध बहुत मुश्किल या लगभग नामुमकिन हो जाती।

एक सुझाव यह था कि जिस बड़े डेटासेट के साथ मैं काम करना चाहता था, उसमें सभी सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं से सूचित सहमति ली जाए। यह एक नामुमकिन काम होता और यह अनुत्पादक भी सकता था क्योंकि इससे उन उपयोगकर्ताओं को मेरे सीधे संपर्क में आने से और खतरा हो सकता था। दूसरा सुझाव यह था कि सारा विश्लेषण एक अति–सुरक्षित डिजिटल वातावरण में किया जाए और डेटा को तुरंत नष्ट कर दिया जाए, जो मुझे उस सामग्री को दुबारा देखने से या परिणामों का परीक्षण करने से रोक सकता था।

महीनों की बातचीत के बाद, आखिरकार मुझे काम करने की मंजूरी मिल गई। यह एक लम्बी प्रक्रिया थी जिसने प्रोजेक्ट की शुरुआत को महीनों से पीछे कर दिया। इस प्रक्रया से गुजरने के बाद, मैं सच में निराश हो गया और मैंने नया डेटा इकट्ठा न करने का फैसला किया। इसके बजाय, मैंने नीदरलैंड्स की एक अन्य विश्वविद्यालय में एक सहयोगी का बनाया हुआ एक मौजूदा डेटासेट इस्तेमाल किया, जिसे पहले ही अपनी यूनिवर्सिटी से एथिकल स्वीकृति मिल चुकी थी। मैं बहुत खुशकिस्मत था कि ऐसा डेटासेट पहले से मौजूद था।

इस कहानी को मैं यह दिखाने के लिए साझा कर रहा हूँ कि कैसे (पश्चिमी) संस्थागत एथिक्स फ्रेमवर्क खुद ही सुरक्षाकरण के उपकरण की तरह काम कर सकते हैं, खासकर तब जब शोध तथाकथित गैर–पश्चिमी सन्दर्भ पर केंद्रित हो, जिन्हें 'संवेदनशील' और 'उच्च–जोखिम' क्षेत्र माना जाता है। ऐसी प्रक्रियाएं, भले ही नेकनीयत हों, अकादमिक स्वतंत्रता को कम करने का जोखिम उठाती हैं, खासकर मेरे जैसे माइग्रेंट और प्रवासी विद्वानों के लिए, जिससे सेल्फ–सेंसरशिप होती है या विद्वान इस हद तक निरूत्साह होते हैं कि वे शोध विषय या रणनीति को पूरी तरह से बदल देते हैं।

महबूबेह मोघदम: लादान जिस संस्थागत सुरक्षाकरण के बारे में बताते हैं, वह उस नैतिक बंधन से जुड़ा है जिसका सामना मैं अक्सर अपने काम में करता हूँ। ईरान में Gen Z की डिजिटल सक्रियता पर मेरे शोध में, दृश्यता और जोखिम को लेकर अक्सर नैतिक तनाव पैदा होते हैं।

वुमन, लाइफ, फ्रीडम आंदोलन के दौरान एक खास मामला एक किशोरी का था, जिसकी सार्वजनिक इंस्टाग्राम सामग्री प्रतीकात्मक बन गई थी। हालांकि उसके पोस्ट व्यापक रूप से साझा किए गए, लेकिन मैंने उन्हें सीधे तौर पर उद्धृत नहीं किया। इसके बजाय, मैंने उसकी सामग्री को नाम छुपा कर ओर अन्य तरह से व्याख्या कर सम्मिश्रित आख्यानों में शामिल करके पुनःपहचान को रोका। मैंने हमेशा डेटा की तथाकथित 'पूर्णता' के बजाय प्रतिभागियों की सुरक्षा और सहमति को प्राथमिकता दी है। जबकि कुछ एथिक्स फ्रेमवर्क सार्वजनिक डेटा को तटस्थ मानते हैं, मैं ऐसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील सन्दर्भों में अति–दर्शनीयता के खतरों को नजरअंदाज नहीं कर सकता।

आंदोलन पर कार्रवाई के बाद, लड़की ने अपने कई पोस्ट और कहानियों को हटा दिया। उसकी प्रोफाइल का स्वर काफी बदल गयाय उसके इंस्टाग्राम हाइलाइट्स और टेलीग्राम पोस्ट सामाजिक–राजनैतिक टिप्पणियों से हटकर हास्य ओर आम बातों में बदल गए। इस बदलाव ने खुलासे के असली जोखिम को रेखांकित किया।

ईरान के अंदर प्रतिभागियों के साथ ऑनलाइन साक्षात्कार के दौरान और भी नैतिक चिंताएँ सामने आईं। मैंने सिग्नल जैसे एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया, ओर स्पष्ट अनुमति के बिना बातचीत रिकॉर्ड करने से बचा, और पूरी तरह से गुमनामी बनाए रखी। ये व्यवहार सिर्फ तकनिकी चयन नहीं हैं, बल्कि नैतिक प्रतिबद्धताएं हैं जो उन मुश्किल हालातों से आकारित होती हैं जिनमें शोधकर्त्ता और प्रतिभागी दोनों काम करते हैं।

रेजा सोहराबी: महबूबेह का दृश्यता पर ध्यान एक व्यापक तनाव की याद दिलाता है जिसका सामना हममें से कई लोग करते हैंः प्रतिभागियों के आख्यानों की भेद्यता को बिना बढ़ाये, सत्यनिष्ठा को कैसे बनाए रखें। अपने शोध में, मैंने इस नैतिक चुनौती को एक लचीले, प्रतिभागी–केंद्रित उपागम के जरिए सम्बोधित किया, जिससे लोगों को साक्षात्कार प्रक्रिया को समझने और उसे आकर देने में मदद मिली।

बिना नाम बताए साक्षात्कार करना जरूरी साबित हुआ। इससे प्रतिभागी बिना किसी प्रतिभाव के डर से ज्यादा खुलकर अपनी बात रख पाए। गोपनीय साक्षात्कार होने से कई लोगों को अपनी बात रखने के दौरान होने वाला तनाव काफी कम हो गया। एक मामले में, एक कार्यकर्ता ने सरकारी जल–प्रबंधन नीति की विस्तृत आलोचना की। हालांकि बातचीत खुली थी, लेकिन बाद में प्रतिभागी ने इस पर चिंता व्यक्त की कि उनकी टिप्पणियों का क्या पता लगाया जा सकता है। जोखिमों के बारे में बात करने के बाद, उन्हें भरोसा हुआ कि उनकी राय पहचानी नहीं जा सकती है, और उन्होंने इसे शामिल करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी।

फिर भी, मैंने गुमनामी को बेहतर बनाने के लिए और कदम उठाए, और खुलासा होने के जोखिम को कम करने के लिए खास समय औरभौगोलिक सन्दर्भों को हटा दिया। इससे मुझे प्रतिभागियों की पहचान की रक्षा करते हुए कहानी के सार को बनाए रखने में मदद मिली।

इस अनुभव ने मुझे यह समझाया कि नीतिगत शोध में, खासकर राजनैतिक रूप से संवेदनशील जगहों पर, न सिर्फ दृश्यता की नैतिकता पर ध्यान देने की जरूरत है, बल्कि कार्य के आवश्यक भाग के रूप में प्रतिभागियों की सुरक्षा के लिए भी प्रतिबद्धता आवश्यक है। प्रतिभागियों की चिंताओं के प्रति लचीलापन ओर उत्तरदायित्व भरोसे की जगह बनाने और अंततः, शोध को मुमकिन बनाने के लिए जरूरी थे।

मराल लतीफी: रेजा की तरह, मैं एथिक्स को एक चेकलिस्ट के तौर पर नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाले सम्बन्ध के रूप में समझने लगा हूँ। मेरे लिए, इसके लिए न सिर्फ गुमनामी बल्कि प्रतिभागियों के साथ जुड़ाव के ग्रामर पर भी पुनः सोचने की जरूरत थी। नैतिक रूप से प्रतिभागियों के वस्तुकरण से बचने का अर्थ एक बाहरी 'आप' से एक सामूहिक, समानुभूति 'हम' की ओर जाना था।

'द वेट ऑफ द वर्ल्ड' में बॉर्डियू के उपागम को अपनाते हुए, मैंने भरोसेमंद सोशल नेटवर्क के जरिए प्रतिभागियों को शामिल किया – या तो सीधे जान–पहचान वालों के मध्यम से या रेफरल से। इस रणनीति ने प्रतीकात्मक दूरी कम की और कलंकित अनुभवों को साझा करने के लिए हालात बनाए। यह मेरी अपनी जीवनसंबंधी नजदीकी से और मजबूत हुआ, क्योंकि मैंने खुद भी कई तरह के स्थानिक पदावनति का अनुभव किया था। इन जुड़ावों ने आपसी समझ को बढ़ाने में मदद की और ज्यादा सूक्ष्म व्याख्या करने में मदद की।

>>

फिर भी, वहीं परिस्थितियां जो भरोसे ओर पहुँच को आसान बनती हैं, उन्होंने गुमनामी को भी जटिल बना दिया और पद्धतीय अनुकूलन की मांग की। उदाहरण के लिए, मैंने जीवनसंबंधी छवि – जो शायद प्रतिभागियों के दुख के संबंधपरक गहराई को बेहतर ढंग से दिखा सकता था – को थीमैटिक एनालिसिस के पक्ष में छोड़ने का फैसला किया, जो पहचान की ज्यादा सुरक्षा देता था, भले ही कहानी में तालमेल की कीमत पर।

फतेमेह मोगादासीः नजदीकी और जोखिम के बारे में माराल की बात एक ऐसी मुश्किल को उजागर करती है जिसका मैं अक्सर सामना करता हूँ: भरोसा और अंतरंगता जो नैतिक शोध का आधार है, वह उन सरकारी संस्थाओं के साथ टकराव में आ सकता है जो आलोचनात्मक जांच को एक राजनैतिक खतरा मानती हैं। जहाँ अकादमिक जगत शोध करने वालों को विषय ओर पद्धति के चयन में कुछ हद तक आजादी देता है, लेकिन जब शोध अकादमिक सीमाओं से आगे बढ़ जाती है – चाहे वह सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर हो या निष्कर्षों के सार्वजनिक प्रसार के द्वारा हो – तो वह आजादी तेजी से कम हो जाती है। ये सीमाएं सिर्फ तकनीकी या नौकरशाही नहीं हैं; वे बहुत ज्यादा नैतिक ओर वैचारिक/विचाध ारायी हैं।

शैक्षिक नीति बनाने के क्षेत्र में, जब प्रबन्धकीय कमियों या कार्यकारी दोषों के प्रति आलोचना निर्देशित की जाती है, तो उसे आम तौर पर बर्दाश्त कर लिया जाता है। लेकिन जब यह गहरे मुद्दों को चुनौती देती है – जैसे कि शिक्षा व्यवस्था की वैचारिक हामीदारी, विद्यालयों में सन्नहित प्रतिमानात्मक मूल्य, या भाषा, संस्कृति और राजनैतिक न्याय के प्रश्न। यह अक्सर ऐसे प्रत्युत्तर को उत्पन्न करता है जो विद्वता से जुड़े नहीं होते, बल्कि वैचारिक निगरानी या राजनैतिक नियंत्रण से जुड़े होते हैं।

ऐसे माहौल में, संरचनात्मक आलोचना का शायद ही कभी स्वागत किया जाता है। इसे अक्सर "राजनैतिक पैंतरेबाजी" कहकर खारिज कर दिया जाता है या इस पर "राष्ट्रीय संस्थाओं को कमजोर करने" का आरोप लगाया जाता है। ये हालात शोधकर्ता को एक मुश्किल नैतिक स्थिति में डाल देते हैं, जिसमें वैज्ञानिक ईमानदारी, क्षेत्र तक पहुँच, और निजी या पेशेवर सुरक्षा के बीच लगातार मोल–भाव करना पड़ता है, खासकर न्याय–अभिमुखित शोध में, जिसमें अपने विशिष्ट जोखिम और जटिलताएँ हैं।

नफीसेह आजादः शोध की आजादी के राजनैतिकीकरण पर फतेमेह की सोच महिला अध्ययनों पर मेरे काम से मिलती–जुलती है, जहाँ सुरक्षा और सहमति की चिंताएँ प्रक्रिया के हर चरण को तय करती हैं। नृवंशीय पद्धतियों और सोद्देश्य निदर्शन पर मेरे भरोसे को देखते हुए, गुमनामी जरूरी है; खासकर महिलाओं पर शोध में। मैं प्रतिभागियों को सुरक्षित रखने के लिए कई तरह के तरीकों का इस्तेमाल करती हूँ, जिसमें गुमनाम डेटा संग्रहण, पहचान के विवरणों को हटाना और शोध कार्य पूरा होने के बाद साक्षात्कार नष्ट करना शामिल है। प्रतिभागी किसी भी समय – पूर्ण या आंशिक रूप से – अपने साक्षात्कार वापस ले सकते हैं और मुझसे किसी भी समय रिकॉर्डिंग बंद करने का अनुरोध कर सकते हैं। मैं उनकी सुरक्षा पक्का करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाती हूँ। मैं मैसेजिंग ऐप या ईमेल के जरिए साक्षात्कार साझा करने से बचती हूँ और उन्हें शोध दल के अन्य सदस्यों के साथ तभी साझा करती हूँ जब प्रतिभागी स्पष्ट सहमति देते हैं।

कुछ मामलों में, जब प्रतिभागी मूल साक्षात्कार को साझा करने के लिए राजी नहीं हुए, तो मैंने कमीशनिंग बॉडीज को शोध जमा रने से मना कर दिया। दूसरों में, मैंने प्रतिभागी महिलाओं के नाम या लोकेशन बताने से बचने के लिए अपने लिखे हुए विश्लेषण की पूरी जिम्मेदारी ली। विश्वविद्यालय व्यवस्था के बाहर, जहाँ संस्थागत सुरक्षा और संसाधन सीमित हैं, ये सावधानियां और अधिक चुनौतीपूर्ण हैं।

शायद इस काम का सबसे दर्दनाक और अपरिहार्य पहलू यह है कि मैं कभी–कभी पूरे शोध क्षेत्र को पहले ही छोड़ देता हूं – जब मुझे लगता है कि मैं डेटा की सुरक्षा, प्रतिभागियों की सुरक्षा, या निष्कर्षों को प्रसारित करने में अपनी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता।

आरजे और एनएसः और फिर भी ये नैतिक और पद्धतिगत तनाव सिर्फ स्थानीय नहीं हैं, ये वैश्विक शक्ति संरचना में शामिल हैं और ज्ञान की राजनीति से आकारित होते हैं। कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं से लेकर किसके आख्यान भरोसेमंद माने जाते हैं, शक्ति तय करती है कि किसे शोध माना जायेगा। वैश्विक गतिशीलता, जैसे कि प्रतिबन्ध, प्रवासियों की स्थिति, या पश्चिमी अकादमिक अपेक्षाएं, ईरान पर समाजशास्त्रीय ज्ञान के उत्पादन, परिसंचरण और स्वागत को कैसे आकार देती हैं?

मराल लतीफीः ईरान में समाजशास्त्रीय ज्ञान उत्पादन में एक और कम दर्शनीय रुकावट समाजशास्त्रीय विद्वता, तुरंत होने वाले राजनैतिक घटनाक्रमों पर ध्यान दे या सामूहिक प्रतिरोधों के अंतिम नतीजों की भविष्यवाणी करें, की चलती मांग है। यह अनिवार्यता, जो "समाज–में–रूपांतरण" की सोच में छिपी है, सामाजिक स्थानों की गतिशीलता पर बुनियादी शोध को धीरे–धीरे हतोत्साहित करती है। मजे की बात यह है कि ऐसे दबाव एक ऐसे ईरानी समाजशास्त्र के उभरने में रुकावट डालते हैं जो आज की बारीक व्याख्या कर सके और संभावित सामाजिक भविष्य की कल्पना कर सके।

फतेमेह मोगादासीः मारल की बात को आगे बढ़ाते हुए, मैंने पाया है कि लंबे समय तक चलने वाले या बुनियादी शोध को आगे बढ़ाने की कोशिशें भी अक्सर संरचनात्मक फंडिंग की कमी की वजह से रुक जाती हैं। ईरान में समाजशास्त्रीय शोध में एक बड़ी रुकावट विश्वविद्यालयों ओर शोध केंद्रों का कमीशन वाले प्रोजेक्ट पर निर्भर रहना है, जिन्हें आमतौर पर सरकारी या अर्ध–सरकारी संस्थाएं फंड करती हैं। ये प्रोजेक्ट "आवेदन और अनुक्रिया" मॉडल का अनुकरण करते हैं, जिससे स्वतंत्र या दीर्घ–कालिक जांच के लिए बहुत कम जगह बचती है।

मेरे अनुभव में, मैंने जरूरी सामाजिक मुद्दों पर ऐसे प्रस्ताव तैयार किए हैं जो फंडिंग की कमी के कारण कभी पूरे नहीं हुए। इससे न सिर्फ शोध की क्षमता बर्बाद होती है, बल्कि अभिप्रेरणा भी कम होती है और ज्ञान उत्पादन की गुणवत्ता भी कमतर होती है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ईरान को सामाजिक नीति में केस स्टडी के रूप में शायद ही कभी प्राथमिकता दी जाती है। डम्छ।–केंद्रित संस्थाओं में शोध एजेंडा अनतर्राष्ट्रीय निकायों की रूचि के साथ संरेखित होते हैं या उन मामलों का पक्ष लेते हैं जिनका डेटा तक पहुँच आसान होती है। इस वजह से, ईरानी मुद्दों को अक्सर दरकिनार कर दिया जाता है या उन्हें भू–राजनैतिक और सुरखा के फ्रेम तक ही सीमित कर दिया जाता है।

शिक्षा के निजीकरण पर साहित्य में यह अंतराल साफ दिखाई देता है। मुश्किलों का सामना करने के बावजूद–अफगानिस्तान और इराक जैसे देशों का अक्सर विश्लेषण किया जाता है, जबकि

>>

ईरान, बड़े पॉलिसी बदलावों से गुजरने के बावजूद, काफी हद तक अनुपस्थित रहता है। यह कुछ हद तक पारदर्शी डेटा व्यवस्था की कमी और लगातार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अभाव के कारण है, जिससे ईरान को अंतर्राष्ट्रीय शोध फ्रेमवर्क के अंदर एक "विश्लेषण योग्य" विषय के तौर पर जगह बनाना मुश्किल हो जाता है।

रेजा सोहराबी: संरचनात्मक बहिष्करण के बारे में फतेमेह की बात को आगे बढ़ाते हुए, मैं यह उजागर करना चाहता हूँ कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबन्ध अकादमिक शोध के सबसे बुनियादी प्रचालन तंत्र को भी बदल देते हैं, खासकर प्रवासी विद्वानों के लिए। ईरान पर अमेरिका के आर्थिक प्रतिबन्ध शोधकर्ताओं पर कई तरह से असर डालते हैं। क्षेत्रीय कार्य के दौरान, मैं प्रतिभागियों को वित्तीय मदद प्रदान करने या उपहार नहीं दे पाया, क्योंकि गिफ्ट कार्ड सहित सभी अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन ब्लॉक थे।

मैंने एक बाह्य शोध ग्रांट के लिए भी आवेदन किया था, लेकिन मेरे आवेदन को कभी देखा नहीं किया गया क्योंकि मेरा क्षेत्रीय कार्य ईरान में आधारित था। इसका औचित्य "युद्ध क्षेत्र" में शोध पर रोक बताया गया – यह एक ऐसी हिदायत थी जिसमें हालिया वर्षों में सक्रिय संघर्ष की अनुपस्थिति के बावजूद ईरान भी शामिल था। यह दिखाता है कि मध्य–पूर्व और वैश्विक दक्षिण की व्यापक सैन्य कल्पनाएँ जमीनी हकीकत को गलत तरीके से दिखा कर और प्रवासी विद्वानों को जरूरी स्त्रोतों से बाहर रख कर कैसे पश्चिमी वर्गीकरण को आकर देती हैं।

ऐसे अनुभव प्रवास से काम करने वाले शोधकर्त्ताओं के सामने आने वाली खास कमियों को दिखाते हैं, जिसमें प्रतिबंधित गतिशीलता, फंडिंग तक पहुँच का अभाव, और संरचनात्मक अकादमिक रुकावटें शामिल हैं, जिनका सामना कम राजनीतिकरण के सन्दर्भों में काम करने वालों को नहीं करना पड़ता।

नफीसेह आजाद: रेजा जिस पृथक्करण की बात कर रहे हैं, वह सिर्फ शारीरिक ही नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा बौद्धिक भी है। ईरान के अंदर से बोलते हुए, मुझे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और घरेलू पाबंदियों, दोनों की वजह से घुटन भरा पृथक्करण महसूस हो रहा है। प्रतिबंधों ने अकादमिक संसाधनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, और आवश्यक शोध यंत्रों तक पहुँच सीमित कर दी है। वीजा मना होने की वजह से अक्सर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में भाग लेना रुक जाता है, और हाल के सालों में, यह लगभग नामुमकिन हो गया है। ईरानी सरकार की खुद की अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में शामिल होने पर लगी पाबंदियों से ये रुकावटें और बढ़ जाती हैं, जिससे ईरानी विद्वानों का पूरी तरह से पृथक्करण हो गया है; एक ऐसा पृथक्करण जो उभर नहीं रहा है, बल्कि पहले से ही जमा हुआ है।

लेकिन, इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात पश्चिमी अकादमिक संस्थानों की उम्मीदें और पूर्वाग्रह हैं, जो अक्सर ईरानी समाज की जटिलताओं और विविधता को छिपा देते हैं, खासकर महिलाओं के मामले में। मध्य–पूर्व की मुस्लिम महिलाओं के बारे में पुरानी सोच जर्नल की समीक्षा करने वालों और सम्पादकों की सोच को बनाती रहती है। मेरे हाल के एक आलेख को एक जाने–माने जेंडर अध्ययन की शोध पत्रिका ने अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसके नतीजों को समझ से बाहर या नामंजूर माना गया। मेरा मानना है कि यह मेरी शोध और मुस्लिम महिलाओं के बारे में हावी पश्चिमी बातों के बीच तालमेल न होने की वजह से हुआ। परिवार और मातृत्व के प्रति एजेंसी के भाव, प्रतिरोध या वैकल्पिक तरीकों पर अक्सर बुनियादी स्तर पर सवाल उठाए जाते हैं।

समूची समीक्षा प्रक्रिया के दौरान, मुझे लगा कि मेरे साथ एक शोधकर्त्ता की तरह नहीं बल्कि एक डेटा संग्रहक की तरह बर्ताव किया जा रहा है। एक और आलेख में – जो आखिरकार काफी बदलावों के बाद प्रकाशित हुआ – मुझे यह स्पष्ट लगा कि ईरान कभी न जाने के बावजूद समीक्षकों को लगा कि वे ईरानी महिलाओं को मुझसे बेहतर समझते हैं। महिलाओं को उनकी पूरी विविधता और बदलाव के साथ दिखाने की कोशिशों को अक्सर वैश्विक अकादमिक जगहों पर गंभीर विरोध का सामना करना पड़ता है। यह मुद्दा कॉन्फ्रेंस में और भी ज्यादा मुखर होता है, जहाँ इसी तरह की गतिकी सामने आती है। बदकिस्मती से, पश्चिमी संस्थाओं में कुछ ईरानी विद्वान इन गतिकी को और मजबूत करते हैं, और अपने साथियों के काम को उसी अनोखे नजरिए से देखते हैं। फिर भी, गहन क्षेत्रीय कार्य से जो सामने आती हैं, वे ऐसी महिलाएँ हैं जिनकी जिंदगी और पसंद इन कटौतीत्मक वृतांतों को चुनौती देती हैं।

लादान रहबारी: मैं प्रवासी स्थानों में, खासकर पश्चिमी शैक्षणिक जगत में, आवाज और भरोसे की राजनीति पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। एक एकेडमिक, जो बड़े ईरानी प्रवासियों का हिस्सा है और कुछ हद तक संस्थागत संसाधनों से मजबूत है, होने के नाते मैं ईरानी सरकार के जुल्म से बचा हुआ हूँ और मुझे कुछ हद तक सहारा भी मिलता है जो हर किसी को नहीं मिलता। हालाँकि मैं दूरस्थ निगरानी या उत्पीड़न से सुरक्षित नहीं हूँ, मुझे अकादमिक संस्थाओं के अंदर और दुख की बात है कि प्रवासी ईरानी सर्कल में भी, गेटकीपिंग के दूसरे तरीकों का सामना करना पड़ता है।

मैंने यह भी देखा है कि कुछ खास तरह की आवाजें, खासकर जिन्हें पश्चिम की तरफ झुकाव रखने वाले धर्मनिरपेक्ष (कभी–कभी स्व–घोषित विशेषज्ञ) माना जाता है, उन्हें पश्चिमी माहौल में ज्यादा आसानी से अपना लिया जाता है। वे वही लोग हैं जो पश्चिमी उद्धार के उपनिवेशी या प्राच्यविद आख्यानों को दोहराते हैं। ऐसे माहौल में, जब कुछ और कभी–कभी हावी प्रवासी आख्यानों ने पहले ही उन फ्रेमवर्क को आकारित किया हो या जिन्हें पसंद किया जाता है, तो उन्हें सुनना मुश्किल होता है।

इससे जमीनी और आनुभविक विद्वता तैयार करना और भी जरूरी हो जाता है। फिर भी, जैसा कि मैंने अपने पहली टिप्पणी में बताया था, अति–सुरक्षित शोध प्रोटोकॉल न सिर्फ डेटा संग्रहण और उसे सँभालने में बल्कि ज्ञान उत्पादन की व्यापक प्रक्रिया में भी ये गंभीर रुकावटें डालते हैं। मैं नफीसेह की इस बात से भी सहमत हूँ कि कैसे संस्थाएं पहले से बने ज्ञानमीमांसीय पैराडाइम के अंदर काम करती हैं और जब वैकल्पिक ज्ञान या ज्ञान बनाने के तरीकों की बात आती है तो वे इतनी लचीली नहीं होती। मुझे लगता है कि हमें उस नजरिए को खारिज कर देना चाहिए जो हमें पहले से स्थापित पश्चिमी सिद्धांतों को साबित करने के लिए डेटा माइन की तरह देखता है; ईरानी संदर्भ की अपनी खासियतें हैं और इसे स्थानीय, प्रादेशिक, और हाँ, कभी–कभी पारदेशीय ज्ञान के मेल से सबसे अच्छे से जाना जा सकता है। हमें अब सबसे ज्यादा जरूरत सख्त, सूक्ष्म शोध की है जो निगमित, आयातित, दोहराई जाने वाली और अक्सर थकी हुई बातों का विरोध करे।

मैं यह सब कह रहा हूँ, लेकिन मुझे यह भी पता है कि यह आसान नहीं है। ईरान में राजनैतिक और सामाजिक यथार्थ को आसान बनाने के लिए संस्थागत और नव–उदारवादी दबाव हैं। और इसका सारा दोष संरचना पर नहीं डाला जा सकता। बाकी सब की तरह, एकेडेमिक्स, लाभ–संचालित पूंजीवादी बाजार का हिस्सा हैं, और कभी–कभी मुश्किल 'चयन' महंगा पड़ता है। पद्धति और

>>

नैतिक बाध्यताएं, विषयगत प्रतिमान, प्रवासी राजनीति, और लगातार गेटकीपिंग के साथ इन चुनौतियों से निपटना सच में बहुत थका देने वाला है। बहुत से (खासकर शुरुआती करियर वाले) शिक्षाविदों के लिए, जो मुश्किल जॉब मार्केट में टिके रहने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ज्ञानमीमांसीय फैसले स्वयं के निजी जीवन से जुड़े होते हैं। जैसा कि हम समाजशास्त्री कहना पसंद करते हैं: यह जटिल है।

महबूबेह मोगदम: थकावट पर लादान की सोच मुझसे बहुत मिलती–जुलती है। अपने काम में, मैंने देखा है कि कैसे हावी ज्ञानमीमांसा कीमती ज्ञान को कम कर देती हैं। वैश्विक शक्ति गतिकी को बाहरी बाध्यताओं के तौर पर नहीं, बल्कि ईरान के बारे में ज्ञान कैसे बनता है, फैलता है और मिलता है, इसके लिए केंद्रीय मानते हुए मैं अपने शोध को पारदेशीय नारीवादी और औपनिवेश–विरोधी नजरिए पर आधारित करती हूँ।

एक प्रवासी विद्वान के तौर पर, मुझे दृश्यता के तरीकों – प्लेटफॉर्मस, भाषा तक पहुँच, और प्रकाशन अवसरों – से फायदा होता है, जो अक्सर उन लोगों को नहीं मिलते जिनकी जिंदगी और विरोध के बारे में मैं अध्ययन करती हूँ। फिर भी, प्रतिबंधों, अमेरिका–ईरान तनाव, सेंसरशिप, और निगरानी की वजह से ईरान में अभिलेखागार, क्षेत्रीय कार्य, और विद्वानों के साथ सहयोग तक मेरी पहुँच कम होती जा रही है।

उसी समय, पश्चिमी शैक्षणिक जगत ज्ञान के उदारवादी और संस्थागत तरीकों को खास अहमियत देता है – जो कानूनी, नीति या सुधार पर आधारित होते हैं – जबकि वे असर, याद, सौंदर्य और रोजमर्रा के विरोध की राजनैतिक अहमियत को नजरअंदाज कर देते हैं। मेरा काम इस बात पर जोर देता है कि ये कम समझ में आने वाले व्यवहार राजनैतिक रूप से जरूरी हैं। यह सिर्फ एक सैद्धांतिक नजरिया नहीं है, बल्कि ईरान के खास हालात और उनमें पैदा होने वाली संघर्ष की सृजनत्मक रणनीति की झलक है।

यह एक नैतिक प्रतिबद्धता भी है कि हम निष्कर्षी ढांचे का विरोध करें और अनुभव पर आधारित जानने के तरीकों को केंद्र में रखें। यह शोध को सिर्फ वैश्विक उत्तर द्वारा तय शर्तों पर पढ़ने लायक बनाने से नारीवादी इंकार है। ■

> राजनैतिक और सामाजिक अर्थव्यवस्था

में श्रम प्रवासन

कैरन शायर, यूनिवर्सिटी ऑफ ड्यूइसबर्ग–एसेन, जर्मनी, **हेइडी गॉटफ्राइड**, वेन स्टेट यूनिवर्सिटी और रसेल सेज फाउंडेशन, USA, और **रीना अग्रवाल**, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, USA

कला प्रदर्शन से डाक टिकिट
श्रेयः करेन शायर

सदियों से, प्रवासन को कुछ लोगों के लिए मौका और दूसरों के लिए श्राप के तौर पर देखा जाता रहा है। पंद्रहवीं से उन्नीसवीं सदी तक, यूरोप से दक्षिण और दक्षिण–पूर्व एशिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका, और अफ्रीका में प्रवासन ने यूरोपियन प्रवासियों को नए संसाधन, जमीन और मौके दिए। लेकिन इन्हीं प्रवासन बहावों का अर्थ था, प्राप्तकर्ता देशों में मूल आबादी के लिए जीत, भूमि अधिग्रहण, बीमारी, हिंसा, और (कुछ मामलों में) पूरी तरह से सांस्कृतिक तबाही। अठारहवीं और उन्नीसवीं सदी में, अफ्रीका और साउथ एशिया से अफ्रीका, एशिया और खासकर अमेरिका के दूसरे हिस्सों में जबरदस्ती प्रवासन से बसने वाले देशों में बसने वालों को दौलत तो मिली, लेकिन प्रवासियों को खुद अमानवीय हिंसा और बेइज्जती झेलनी पड़ी, उन प्रवासियों के वंशजों की पीढ़ियों की तो बात ही छोड़िए। आज, हम इसी उलझन का एक और रूप देख रहे हैं। अरबों लोगों के लिए, प्रवासन ही आर्थिक रूप से जिंदा रहने औरध्या शारीरिक सुरक्षा का एकमात्र मौका देता है। फिर भी, यही प्रवासन का बहाव अरबों मूल निवासियों के लिए गहरी असुरक्षा और उनमें गुस्सा पैदा कर रहा है। एक के बाद एक देश को ये तनाव नफरत से भरे दक्षिण–पंथी गठबंधनों में बदल रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम प्रवासन के सवाल की जांच करने के लिए नए विश्लेषणात्मक लेंस का एक सेट पेश करें, और समाजशास्त्री इस चुनौती को लेने के लिए अच्छी तरह तैयार हैं।

यह विशिष्ट खंड श्रम प्रवासन की राजनैतिक और सामाजिक आर्थिकी का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करता है। इसमें राज्यों,

>>

नीतियों, कर्ताओं और उन लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों पर फोकस किया गया है जो राष्टीय सीमाओं के भीतर और पार, दोनों ही रूप से, गतिशीलता के जरिए अपनी आजीविका को बेहतर बनाना चाहते हैं। आगे दिए गए आलेख उन योगदानों पर आधारित हैं जो मूल रूप से 2024 की गर्मियों में ड्युइसबर्ग–एसेन यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्र संघ की अर्थव्यवस्था एवं समाज पर शोध समिति (RC02) और वर्ल्ड सोसाइटी फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित कॉन्फ्रेंस "इंटरनेशनल पोलिटिकल इकॉनमी ऑफ माइग्रेंट लेबर" में पेश किए गए थे। वे भेजने वाले राज्यों और आउट–माइग्रेशन की नीतियां, विदेशी निवेश के लिए पूंजीय गांव से शहर और क्रॉस–बॉर्डर प्रवासन के जटिल कटाव, खासकर वैश्विक दक्षिण से और वैश्विक दक्षिण की ओरय भेजने वाले और प्राप्त–कर्ता राज्यों की तुलनाय पढ़े–लिखे और कम सैलरी वाले प्रवासनय और ये सभी प्रवासियों की उम्मीदों और जिंदगी के रास्तों को कैसे आकार देते हैं, इस पर बात करते हैं। इसमें शामिल देश एक बड़े सामाजिक–राजनैतिक भूभाग में फैले हुए हैं, जो दुनिया भर में मुश्किल अन्तः प्रादेशिक और पारदेशीय प्रवासन बहाव को दिखाते हैं।

> प्रवासन–विकास व्यवस्था का विश्लेषण

प्रवासन के समाजशास्त्रीय विश्लेषण में एक जरूरी नवाचार यह है कि भेजने वाले देशों के लिए श्रम प्रवासन की भूमिका और नतीजों की संकल्पना में बदलाव किया गया है, जहाँ आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक बदलाव प्रवासन से जुड़ जाते हैं, जिसे अग्रवाल "प्रवासन–विकास व्यवस्था" कहते हैं। और राजनीतिक बदलाव प्रवासन से जुड़ जाते हैं, जिसे अग्रवाल "प्रवासन–विकास व्यवस्था" कहते हैं। जैसा कि अग्रवाल के मुख्य आलेख में बताया गया है, भारत, जहाँ अग्रवाल ने मूल रूप से यह कॉन्सेप्ट डेवलप किया था और डेवलपिंग दुनिया के दूसरे संदर्भों में, में प्रवासन–विकास व्यवस्था के अध्ययन में तीन प्रश्न शामिल हैंः पहला, प्रवासन से किसे लाभ होता है; दूसरा, प्रवासन के क्या परिणाम होते हैं; और तीसरा, प्रवासन और विकास के मध्य का सांठ–गाँठ कैसे लगातार बदल रही है।

यह खुलासा करने से कि प्रवासन से किसे लाभ होता है, प्रवासन के बारे में लोगों की राय और समर्थन को सकारात्मक बनाने में मदद मिल सकती है। प्रवासन के नतीजों की जांच करने से, खासकर सामाजिक वर्ग संस्तरण और कुलीन साझेदारी के संबंध में, वृद्धि के मॉडल के तौर पर प्रवासन और सामाजिक सुरक्षा पर इसके असर के बारे में अंतर्दृष्टि मिल सकती है। आखिर में, यह अध्ययन करने से कि समय के साथ प्रवासन–विकास व्यवस्था कैसे बदलती है, यह प्रवासन कैसे सामाजिक विकास से लाभ प् सकता है के बारे में वैकल्पिक कल्पनाएं मिल सकती है।

भारत से विदेशों में कम वेतन वाले क्षेत्रों में आउट–माइग्रेशन का अध्ययन करते हुए, कुमार ने जांच की कि क्या भेजने वाले और पाने वाले देशों के मध्य द्वि–पक्षीय अनुबंध थे। यह एक ऐसा तरीका है जो चाहे नाम के लिए ही, सुरक्षित और व्यवस्थित प्रवासन का वादा करता है। कुमार ने पाया कि ये अनुबंध भारतीय आउट–माइग्रेंट्स के स्वास्थय और सुरक्षा पर ठीक से ध्यान नहीं देते हैं, कुछ हद तक इसलिए क्योंकि वे प्रवासी संगठनों और श्रम संघों से सलाह लेने और सुरक्षा प्रदान करने में उनकी भागीदारी को मुमकिन बनाने की अनदेखी करते हैं। भारतीय राज्य के लिए, आउट–माइग्रेशन कई मकसद पूरे करता है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ ही देश और विदेश दोनों जगह राजनीतिक मान्यता हासिल करता है, और एक नए नव–उदारवादी हैबिटस के लिए सहमति हासिल करता है।

> घरेलू और देखभाल श्रमिक प्रवासन

प्रवासी गतिशीलता पर समाजशास्त्रीय कार्य ने लंबे समय से देखभाल प्रवासन के परिणामों का पता लगाया है, दोनों ही मामलों में, दोनों ही उन मूल समुदायों के लिए जिनके पास देखभाल की कमी है, और उन जगहों पर सामाजिक असमानताओं के लिए जहाँ काम करने की शोषणकारी स्थितियाँ वैश्विक और नृवंशीय संस्तरण में निहित हैं। घरेलू और देखभाल प्रवासन पर लेखों की श्रृंखला वैश्विक दक्षिण के अंतर्गत गतिशीलता की पारदेशीय तुलना और गांव से शहर और क्रॉस–बॉर्डर प्रवासन के बीच तुलना करती है।

गा–सालाजार, मोरेनो, कैस्टिब्लैंको–मोरेनो और पिनेडा दिखाते हैं कि लैटिन अमेरिका में महिलाओं की दक्षिण–से दक्षिण गतिशीलता, दक्षिण–से–उत्तर बहाव, जिसने देखभाल प्रवासन पर शोध में दबदबा बनाया है, व्यवस्थागत रूप से कैसे अलग है, वैश्विक देखभाल चेन प्रजनन श्रम का साधारण हस्तांतरण व्यवस्था नहीं हैं। कोलंबिया प्रवास करने वाली वेनेजुएला की महिलाओं की बड़ी आबादी अपने बच्चों और दूसरे आश्रित व्यस्क के साथ माइग्रेट करते समय घर पर अपनी देखभाल की जिम्मेदारियाँ भी साथ ले जाती है। हालाँकि, देखभाल कार्य क्षेत्र में, विस्थापित कोलंबियाई महिलाएँ भी काफी मौजूद हैं, जबकि इस क्षेत्र में आम तौर पर अनियमित प्रवासन और अनौपचारिकता वेनेजुएला की प्रवासी महिलाओं के काम करने के हालात और रोजी–रोटी की सुरक्षा पर असर डालती है।

Ng और Ye, पूर्व और दक्षिण–पूर्व एशिया के पैटर्न की तुलना करते हैं, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में गांव से शहर की ओर देखभाल प्रवासन और कम आय वाले देशों से सिंगापुर में घरेलू मजदूरों के पारदेशीय प्रवासन के बीच। "गतिशील विकासवाद" की सोच दोनों मामलों में बहुत एक जैसी काम करती है, जो गतिशील और प्रवासी घरेलू मजदूरों को कम आधुनिक दिखाती है, और इस तरह उन आधुनिक शहरी परिवारों से अच्छे काम और सही बर्ताव के कम लायक हैं जिनके लिए वे काम करते हैं।

> शिक्षित और कुशल प्रवासियों के बारे में सोच पर सवाल

दो आलेख शिक्षित और कुशल प्रवासियों के विश्लेषण पर फोकस करते हैं, जिन्हें अभी भी प्रवासी विद्वता में काफी हद तक नजरअंदाज किया जाता है। यह खासकर खाड़ी देशों में प्रवासन पर शोध के लिए सच है। पॉल, यावास और पार्क मध्य–पूर्व और उत्तरी अफ्रीका (MENA) और दक्षिण एशिया से दुबईः आम ग्लोबल नॉर्थ लेबर मार्केट से ज्यादा पसंद की जाने वाली जगह, आने वाले निर्वासित प्रवासियों, पर अपने शोध के नतीजों पर चर्चा करते हैं। जहाँ दुबई में करियर विकास और जीवन स्तर वैश्विक उत्तर के सन्दर्भ से अलग नहीं हैं, MENA क्षेत्र और दक्षिण एशिया से निर्वासित लोग भौगोलिक नजदीकी को देखते है। वैश्विक उत्तर से अधिक दुबई को पसंदीदा गंतव्य स्थल बनाने के पीछे परिवार से आसानी से मिलना और धार्मिक और नृवंशीय पहचान के लिए सहिष्णुता होती है। हालांकि, यह बात सब–सहारा अफ्रीका के प्रवासियों पर लागू नहीं होती है, जिन्हें दुबई में वैसा ही भेदभाव झेलना पड़ता है जैसा वैश्विक उत्तर में होता है। दुबई जैसे वैश्विक शहर बड़ी संख्या में कम वेतन वाले अप्रवासियों के शामिल होने की जगह हैं जो कुलीन प्रवासियों की सेवा करते हैं, जिससे प्रजनन सेवाओं की एक अनिश्चित फेमिनाइज्ड अर्थव्यवस्था बनती है।

शू चीन से आने वाले प्रवासियों की अभिप्रेरणा की तुलना करते हैं, जो पढ़ाई के लिए देश के अंदर और देश के बाहर कनाडा आते–जाते रहते हैं। शोध में यह माना गया है कि कनाडा में नागरिकता और चीन में शहरी "हुकोऊ" पंजीकरण स्थिति, देश के

>>

अंदर और देश के अंदर शैक्षिक प्रवास के लिए मुख्य अभिप्रेरणा हैं। इसके उलट, शू पाते हैं कि ग्रामीण शिक्षा प्रवासी स्नातक के बाद शहरी चीनी श्रम बाजार में बेहतर नौकरी की संभावनाओं में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, न कि अलग पंजीकरण स्थिति (हुकोऊ) में। कनाडा आने वाले चीनी शैक्षणिक प्रवासी नागरिकता के बजाय स्थायी रहवास पसंद करते हैं, जैसा कि चीन के ग्रामीण इलाकों से कनाडा आए चीनी लोग करते हैं, क्योंकि विदेशी नागरिकता उनके चीन वापस आने और देश के बाहर रहने की उनकी क्षमता को रोक सकती है।

> कंबोडिया में चीनी प्रभाव का मामला

लाई और सियू का आखिरी लेख खास तौर पर इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि कैसे कंबोडिया में चीनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कपडा उद्योग का 90% और सभी विदेशी फैक्ट्रियों का 55% है, कंबोडिया में एक तानाशाही पूंजीवाद के मॉडल को मजबूत करता है, जहां विदेशी निवेश पर निर्भर आर्थिक विकास को श्रम अधिकारों और लोकतान्त्रिक भागीदारी से ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। जहाँ कंबोडिया के कपडा कारीगर शोषण के खिलाफ संघर्ष करना जारी रखते हैं, हड़ताल की घटनाएं तेजी से कम हो गई हैं क्योंकि देश चीनी निवेशकों को आकर्षित करने और खुश करने के लिए सस्ता श्रम देने का लक्ष्य रखता है। जो प्रवासी विकास व्यवस्था सामने आई है, वह लैटिन अमेरिका और दूसरे दक्षिण–पूर्व एशियाई मामलों में आश्रित विकास पर पहले की शोध जैसा है।

विचारधारा और नीतियां इस बात को प्रभावित करती हैं कि प्रवासन सामाजिक गतिशीलता प्रदान कर्ता है या सिर्फ मौजूदा संस्तरण को मजबूत करता है।

इन आलेखों में प्रवासन पर भावी समाजशास्त्रीय शोध के लिए सुझाए गए नए रास्ते, देशों – भेजने और पाने वाले – और उनके विकास और निवेश मॉडल के महत्व की ओर इशारा करते हैं, ताकि यह तय हो सके कि प्रवासन सामाजिक गतिशीलता और आजीविका की सुरक्षा के मौके खोलता है, या पहले से ही कमजोर प्रवासियों को खतरनाक आजीविका में फंसा देता है। सामाजिक वर्ग, साथ ही जेंडर और नृवंशीयता, खासकर जब ये मूल देश और गंतव्य के आय स्तर के अंतर के साथ ओवरलैप होते हैं, तो वे प्रवासन के इन संभावित नतीजों को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। हालांकि पढ़े–लिखे प्रवासियों को लाभ मिलने की सबसे ज्यादा संभावना होती है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे अपने गंतव्य देश के श्रम बाजार में शामिल होते हैं या नहीं।

विकास की विचारधारा और नीति इस बात के लिए मायने रखती हैं कि प्रवासन सामाजिक गतिशीलता का मौका देता है या जेंडर, वर्ग, और नृवंशीय संस्तरणों को मजबूत करता है। हालांकि, सुरक्षित और व्यवस्थित प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय शासन प्रणाली ने अभी तक कम मजदूरी वाले काम में प्रवासियों के लिए बराबरी और सुरक्षा नहीं दी है। साथ ही, गंतव्य देशों की नीतियां अभी तक कुशल प्रवासियों को वह सामाजिक और राजनैतिक सुरक्षा नहीं देती हैं जो वे चाहते हैं। सीमा से जुड़े प्रवासन के नतीजे और समवसजन और बहिष्करण के प्रश्न आतंरिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन के लिए बहुत समान हैं, जो घरेलू और देखभाल श्रम और कम–कुशल विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में एक–दूसरे से जुड़े होते हैं। दक्षिण–से–दक्षिण प्रवासन और बढ़ती संख्या में आउट–माइग्रेशन और आप्रवासन दोनों का मेल, दुनिया भर में प्रवासियों के अनुभवों को आकार देने वाले संस्थानों और तरीकों पर अधिक शोध की जरूरत को रेखांकित करता है। ■

संपर्क करें:
करेन शायर <karen.shire@uni-due.de>
हेइडी गॉटफ्राइड <ag0921@wayne.edu>
रीना अग्रवाल <agarwala@jhu.edu>

> प्रवासन चुनौती में

समाजशास्त्रीय योगदान

रीना अग्रवाल, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, USA द्वारा

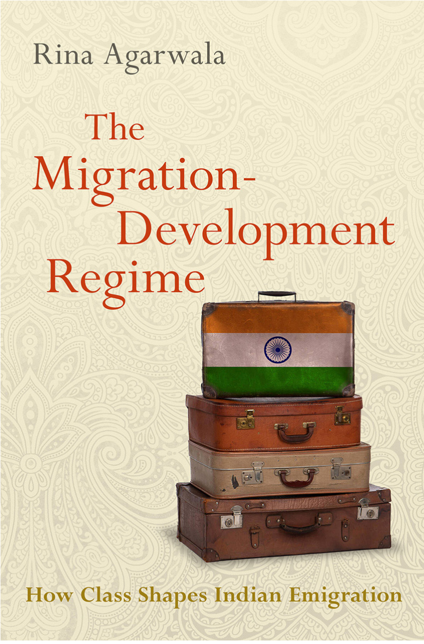

रीना अग्रवाल की पुस्तक द माइग्रेशन–डेवेलपमेंट रेजिमे का बुक कवर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस

वैश्विक प्रवासन हमारी सदी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। यह विषय स्वयं ही चुनाव के नतीजे तय कर रहा है, और इस मुद्दे पर लोगों के विचार देशों, समुदायों और यहाँ तक कि परिवारों को भी बाँट रहे हैं। समाजशास्त्र इस चुनौती से निपटने में कैसे मदद कर सकता है?

दशकों से, समाजशास्त्रियों ने हमारी नजर को सिर्फ अकेले प्रवासियों पर ध्यान देने के बजाय, उन बड़ी आर्थिक और सामाजिक ताकतों को समझने में पुनःनिर्देशित करने में मदद की है जो सबसे पहले आतंरिक और वैश्विक प्रवासन के बहाव को बढ़ावा देती हैं। इन संरचनात्मक कारकों को समझने से यह समझने में मदद मिली है कि कौन प्रवास करता है, कैसे और कहाँ प्रवास करता है, और इसमें शामिल लागतों और जोखिमों के बावजूद वे प्रवास क्यों करते हैं। उदाहरण के लिए, समाजशास्त्रियों ने विभिन्न "पुश कारकों" – जैसे आर्थिक गरीबी, बीमारियों का फैलना, भूमि अधिग्रहण, और हिंसा – का विश्लेषण किया है, जो कुछ लोगों को अपने घरों और प्रियजनों को उन इलाकों में छोड़ने का मुश्किल और अक्सर खतरनाक फैसला लेने के लिए उकसाते हैं जहाँ वे रहते हैं। समाजशास्त्रियों ने अलग–अलग "पुल कारकों" – जैसे कानूनी और संस्थागत ढांचा और श्रम मांग – पर भी जोर दिया है, जो लोगों को दूसरों के बजाय कुछ खास प्राप्त–कर्त्ता क्षेत्रों की ओर खींचते हैं। यह जानते हुए कि लोग सिर्फ तार्किक कर्त्ता नहीं होते, समाजशास्त्रियों ने मध्यस्थता–प्रक्रिया – जैसे नृवंशीय नेटवर्क, सांस्कृतिक बंधुत्व, और पारिवारिक/घरेलू निर्णय पोर्टफोलियो – का भी अध्ययन किया है, जो कुछ प्रवासन बहाव को बढ़ावा देते हैं, भले ही वे सबसे ज्यादा किफायती या जोखिम–मुक्त न हों।

लेकिन समाजशास्त्रियों के रूप में, हमें अपनी जांच यहीं नहीं रोकनी चाहिए। अपनी हालिया पुस्तक, *द माइग्रेशन–डेवलपमेंट रिजीमः हाउ क्लास शेप्स इंडियन एमिग्रेशन* में, मैं एक नया विश्लेषणात्मक ढांचा प्रदान करता हूं जिसे मैं प्रवासन–विकास शासन, या MDR कहता हूं, जो तीन जरूरी तरीकों से जांच को बढ़ाने के लिए हमारे समाजशास्त्रीय उपकरणों का इस्तेमाल करता है। 33

> प्रवासन शासन से किसे लाभ होता है?

सबसे पहले, हमें शक्ति की अपनी समाजशास्त्रीय समझ का इस्तेमाल करके उन गैर–प्रवासी कर्त्ताओं को सामने लाना होगा जिन्हें प्रवासन से न सिर्फ नुकसान होता है बल्कि लाभ भी होता है। प्रवासन के इर्दगिर्द सार्वजनिक और राजनैतिक विवादों ने दिखाया है कि प्रवासन स्पष्ट तौर पर प्रवास करने वाली आबादी से कहीं अधिक प्रभाव डालता है, लेकिन आजकल की बहसें होने वाले खर्चों पर ही ध्यान केंद्रित करती हैं। लेकिन यह उजागर करना कि गैर–प्रवासी आबादी में से किसे लाभ हो रहा है और उन्हें कैसे लाभ हो रहा है, इससे यह बेहतर ढंग से समझाया जा सकता है कि खर्चों और जोखिमों के बावजूद प्रवासन का बहाव क्यों जारी है। इन लाभार्थियों और लाभों को सामने लाने से प्रवासन के लिए सार्वजनिक समर्थन बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है। आखिर में, इन लाभार्थियों और लाभों को सामने लाने से यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि किन क्षेत्रों को सुरक्षा की आवश्यकता है।

तो कौन से गैर–प्रवासी कर्त्ताओं को प्रवासन से लाभ होता है और कैसे? वैश्विक प्रवासन के मामले में, हम जानते हैं कि मूल नियोक्ता अक्सर वैतनिक उत्पादक क्षेत्र में सस्ते प्रवासी श्रम के जरिए ज्यादा आर्थिक लाभ और प्रजाति–और जेंडर–आधारित प्रस्थिति गतिशीलता हासिल करते हैं। समाजशास्त्रियों ने यह भी सामने लाने में मदद की है कि कैसे मूल परिवार अपने बुजुर्गों, अपने बच्चों और यहाँ तक कि खुद की देखभाल के लिए प्रवासी पर निर्भर होकर वैतनिक और अवैतनिक प्रजनन क्षेत्र में बढ़ी हुई प्रजाति–और जेंडर–आधारित शक्ति हासिल करते हैं।

>>

MDR फ्रेमवर्क एक और लाभकारी बात को उजागर करता है जिसे प्रवासन पर समाजशास्त्रीय अध्ययनों में अक्सर छिपा दिया जाता है; राज्य। 1900 के दशक की शुरुआत से, प्राप्त–कर्त्ता और भेजने वाले देशों के "प्रवासन प्रस्थिति" ने यह नियंत्रित किया है कि खास राष्ट्रीय सीमा में आने या जाने का अधिकार किसे है। और "अंतर्राष्ट्रीयवाद" में दिलचस्पी बढ़ने के बावजूद, राष्ट्र–राज्य अभी भी लोगों के सीमा–पार चलन को विनियमित करने, रोकने और नियंत्रित करने के कानूनी अधिकार वाले अकेले कर्त्ता के तौर पर काम करते हैं। लेकिन ऐसा शासन महंगा होता है। तो राज्य क्यों परेशान होंगे? 1833 से लेकर आज तक भारत को एक भेजने वाले देश के तौर पर देखते हुए, मैं दिखाता हूँ कि कैसे भारत सरकार ने लगातार बाहर जाने को एक जरिया बनाया है, जिससे वह अपने देश में आर्थिक विकास कर सके, (घरेलू और वैश्विक स्तर पर) राजनीतिक मान्यता हासिल कर सके, और नए नियमों, आदतों और तरीकों के लिए मंजूरी पा सके। उदाहरण के लिए, भारतीय प्रवासियों ने 1900 के दशक की शुरुआत में साम्राज्यवाद–विरोधी और नस्लवाद–विरोधी आंदोलन और 1970 के दशक में लोकतंत्र–समर्थक आंदोलन को फैलाने में मदद की। और हाल ही में, भारत और खाड़ी देशों के बीच आने–जाने वाले गरीब प्रवासी मजदूर उद्यमशीलता और आत्मनिर्भरता के आदर्शों को आगे बढ़ाते हैं और वैश्विक महानगरवाद की पहचान बनाते हैं।

लेकिन भावी शोध में जरूरी प्रश्नों के जवाब मिलने बाकी हैं। तेजी से, राज्य एक ही समय में भेजने वाले और पाने वाले राज्य के तौर पर काम कर रहे हैं। वे इन प्रतिस्पर्धी भूमिकाओं को कैसे सँभालते हैं? राष्ट्रीय स्तर के राज्य शासन, उप–राष्ट्रीय राज्य शासनों से कैसे अलग होते हैं और उनसे संभावित रूप से कैसे टकरा सकते हैं? इसी तरह, क्या MDR फ्रेमवर्क हमसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रवासन विश्लेषण को अलग करने वाली मौजूदा रुकावटों को खत्म करने के लिए कहता है?

> प्रवासन व्यवस्था के असल परिणाम क्या हैं?

दूसरा, प्रवासन से पक्का लाभ उठाने वालों को उजागर कर, हम प्रवासन के सही परिणामों (नियत या अनियत) को भी ज्यादा सही तरीके से बता सकते हैं; जिससे जिन समस्याओं का हमें समाधान ढूंढना है, उनकी सही प्रकृति का बेहतर तरीके से पता चल सकता है।

भारत के मामले में, मैं MDR फ्रेमवर्क का इस्तेमाल यह तर्क देने के लिए करता हूँ कि 1830 के दशक से लेकर आज तक भारतीय सरकार की आप्रवासन नीति और तरीकों का एक मुख्य परिणाम यह रहा है कि भारतीय नागरिकों के बीच वर्ग के आधार पर भेदभाव लगातार बढ़ा है और उन्होंने उसे पक्का किया है। उदाहरण के लिए, 1833 में गुलामी खत्म करने के बाद, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने गरीब भारतीय मजदूरों को नस्लीय कुली (बंधुआ मजदूरी, अनौपचारिक रोजगार और मध्यम–वर्गीय पेशों में) के तौर पर काम करने के लिए प्रवासगमन को बढ़ावा दिया। लेकिन 1900 के दशक से लेकर आज तक, भारत सरकार ने गरीब नागरिकों को विदेश जाने से कानूनी तौर पर रोक दिया है, जबकि अमीर नागरिकों को आजादी से आने–जाने की अनुमति दी है। यद्यपि, आने–जाने पर ये रोक सुरक्षा और राष्ट्रवाद के नाम पर लगाई गई थीं, लेकिन उन्होंने वह दिया जिसे मैं "पितृसुलभ सुरक्षा" कहता हूँ, जिससे भारत और दुनिया भर में वर्ग असमानता और गहरी हो गई है।

इस बीच, 1980 के दशक से, भारतीय सरकार ने अपने कुलीन प्रवासियों को भारत में व्यापर और सरकारी नेताओं के साथ एक "कुलीन गठबंधन" बनाने में मदद की है जिसने 1800 के दशक के बाद पहली बार वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था में भारत की जगह बदल दी है। भारतीय सरकार की आप्रवासन नीतियों और तरीकों की वजह से, खास तौर पर भारतीय–अमेरिकी, निजीकरण, आत्मा–निर्भरता, और स्वेच्छावाद जैसे नव–उदारवादी आदर्शों और तरीकों को अभिजात्य US जगहों से भारत में अभिजात्य लोगों तक पहुँचाने के लिए एक मुख्य पारदेशीय वेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। इसने भारतीय व्यापर, नागरिक समाज संगठन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, टैक्स कोड और रियल एस्टेट बाजार को नया रूप दिया है, जिससे भारत एक नए तरह का वैश्विक आर्थिक कर्त्ता बन गया है। UK के भारतीय मूल के, हिंदू पूर्व प्रधानमंत्री ने उदाहरण दिया कि कैसे ऐसे पारदेशीय वेक्टर निजी दायरे में भी आते हैं; उन्होंने एक भारतीय नागरिक और भारत की सबसे सफल IT फर्मों में से एक के संस्थापक की बेटी से शादी की है।

लेकिन, फिर भी, जरूरी प्रश्नों के उत्तर मिलने बाकी हैं। अगर MDR फ्रेमवर्क वर्ग–आधारित असमानताओं को सामने लाता है, तो क्या इसे प्रवासन व्यवस्था के जाति– और जेंडर–आधारित परिणामों का भी खुलासा करना चाहिए? प्रवासन वाले राज्यों ने समय के साथ इन संस्तरणों को कैसे पक्का किया है?

> प्रवासन शासन कैसे बदल सकते हैं और बदलते हैं?

आखिर में, समाजशास्त्रियों के तौर पर हम संरचना और एजेंसी के बीच के जटिल और बदलते संबंधों के बारे में अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं, और हम जानते हैं कि शक्ति ऊपर और नीचे से इस्तेमाल की जा सकती है। इसलिए, MDR फ्रेमवर्क प्रवासन राज्य को एक स्थिर इकाई के तौर पर नहीं, बल्कि संघर्ष की जगह के रूप में देखता है। इसलिए, हमारी प्रवासन के शोध में, हमें न सिर्फ यह दिखाना होगा कि कैसे राजनैतिक और आर्थिक संरचनाएं ऊपर से प्रवासन को आकार देते हैं, बल्कि यह भी दिखाना होगा कि कैसे प्रवासी कभी–कभी नीचे से राज्यों और आर्थिक संरचना को नया आकार देते हैं। राज्यों और प्रवासियों के मध्य इन द्वंद्वात्मक संबंधों के परिणामों में, MDR समय के साथ बदलते हैं। भारत के मामले में, मेरी पुस्तक 1830 के दशक से लेकर आज तक तीन अलग–अलग MDR के उतार–चढ़ाव का पता लगाती है। भावी शोध को विभिन्न देशों और उप–राष्ट्रीय इलाकों के MDR में हुए ऐतिहासिक बदलावों का पता लगाना चाहिए, और इस इतिहास का इस्तेमाल वैकल्पिक भविष्य की कल्पना करने के लिए करना चाहिए।

समाजशास्त्री दशकों से वैश्विक प्रवासन को समझने में अहम योगदान दे रहे हैं। लेकिन समकालीन चुनौतियाँ नए मोड़ ले रही हैं, और हमारे शोध को ताजी हवा की जरूरत है। MDR फ्रेमवर्क हमारे भावी शोध को बढ़ाने में मदद करने के लिए एक नया टूल देता है। ■

संपर्क करें :
रीना अग्रवाल <agarwala@jhu.edu>

> भारतीय राज्य सुरक्षित और व्यवस्थित माइग्रेशन की कल्पना कैसे करता है और उसे कैसे लागू करता है

इल अश्विन कुमार, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, USA द्वारा

भारतीय झंडा लहराते हुए. श्रेयः रघु राजा, पिक्सेल्स द्वारा

पिछले कुछ दशकों में, अलग–अलग राजनीतिक और विकास के लक्ष्यों को पाने के लिए माइग्रेशन को मैनेज करने में सरकार, खासकर भेजने वाले राज्य की भूमिका पर काफी जानकारी सामने आई है। सुरक्षित और सही तरीके से माइग्रेशन की मांग इस चर्चा के साथ–साथ उठती है, प्रवसन और विकास कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। 2015 के यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और 2018 में अपनाया गया ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन, "सुरक्षित, व्यवस्थित और जिम्मेदार" माइग्रेशन के लिए एक पैटर्न बताते हैं।

यह लेख जमीनी स्तर पर इस फ्रेमवर्क की असलियत को देखता है, और यह भी कि कैसे राष्ट्रीय और अप–राष्ट्रीय सरकारें इन मकसदों के लिए प्रोग्राम सोचती हैं और उन्हें लागू करती हैं। खास तौर पर, मैं यह देखता हूँ कि भारत, जो दुनिया में सबसे ज्यादा प्रवासी श्रमिक भेजता है, भावी प्रवासी कामगारों के लिए मार्केटेबल स्किल्स को फैलाकर सुरक्षित और नैतिक प्रवसन की कल्पना कैसे करता है। ऐसा करने के लिए, मैं दिल्ली, केरल और तेलंगाना जैसे माइग्रेंट भेजने वाले बड़े इलाकों में वर्कर ऑर्गनाइजेशन के साथ–साथ फेडरल और स्टेट स्किल और रिक्रूटमेंट एजेंसियों के इंटरव्यू लेता हूँ।

> सुरक्षित और व्यवस्थित माइग्रेशन के लिए "स्किल–माइग्रेशन इकोसिस्टम" की संभावनाएँ और सीमाएँ

रीना अग्रवाल का कहना है कि कॉलोनियल और पोस्ट–कॉलोनियल भारतीय सरकार ने हमेशा अपने विकास के मकसद को पूरा करने के लिए अपनी माइग्रेंट आबादी में दखल दिया है और उनसे जुड़ी है। यह दखल जिस मुख्य तरीके से हुआ है, वह है अपने प्रवासी कामगारों की सुरक्षा पक्का करना।

हाल ही में, भारत सरकार ने प्रवासी कामगारों को मार्केटेबल स्किल्स देकर और उन्हें रिसीव करने वाले देशों के साथ बाइलेटरल लेबर एग्रीमेंट्स (BLAs) में तय ऑफिशियल चैनल्स के जरिए भेजकर नैतिक भर्तियों को बढ़ावा देने की कोशिश की है। हालांकि ये समझौते लागू करने में सीमित हैं, लेकिन इनका मकसद गंतव्य देशों में सुरक्षित और नैतिक भर्तियां प्रैक्टिस, साथ ही सैलरी और काम की सुरक्षा के बारे में आपसी सहमति से तय किए गए नॉर्म्स को पक्का करना है। फरवरी 2025 तक, भारत की केंद्र सरकार के साथ–साथ कुछ राज्य सरकारों ने जर्मनी, इजराइल और जापान जैसे देशों के साथ स्किल–बेस्ड BLAs साइन किए हैं। कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल और टेक्निकल काम, और हेल्थकेयर समेत कई तरह के कामों और सेक्टर के लिए। इन एग्रीमेंट के जरिए, भारत सरकार ने तर्क दिया कि वे मॉनिटरिंग और कभी–कभी सहयोग के जरिए प्राइवेट एजेंसियों के काम को भी बेहतर तरीके से कंट्रोल कर

>>

सकते हैं, जो अभी भी रिक्रूटमेंट मार्केट पर हावी हैं। नए एक्टर (यानी फेडरल और स्टेट) एजेंसियां, निजी कौशल विकास एजेंसियों के अतिरिक्त) अब "कौशल–प्रवास" पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश कर चुकी हैं।

लेकिन, इन प्रोग्राम को अलग–अलग फेडरलिस्ट इंडियन माइग्रेशन मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में लागू करना मुश्किल रहा है। फेडरल और स्टेट एक्टर अलग–अलग लक्ष्य और स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, लेकिन उनके अलग–अलग पॉलिटिकल रुख भी होते हैं, जिससे लागू करने की प्रक्रिया के दौरान कॉम्पिटिशन और कन्फ्यूजन होता है। फेडरल और स्टेट स्किलिंग एजेंसियों के साथ मेरे इंटरव्यू से पता चला कि उनके बीच बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है, क्योंकि वे कॉन्ट्रैक्ट और इंस्टीट्यूशनल पहचान के लिए एक–दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, साथ ही कई मौजूदा प्राइवेट रिक्रूटमेंट और स्किलिंग एजेंसियों के साथ भी मुकाबला करते हैं। इससे सहयोग की कमी हुई है और माइग्रेंट्स को स्किल देने के स्टैंडर्ड को लेकर कन्फ्यूजन पैदा हुआ है। उदाहरण के लिए, जबकि हाल ही में हुए इंडिया–जर्मनी एग्रीमेंट के तहत रिक्रूटमेंट से पहले कड़े स्किल और भाषा ट्रेनिंग स्टैंडर्ड को पूरा करना जरूरी था, कंस्ट्रक्शन के काम के लिए लंबे समय से चले आ रहे इंडिया–इजराइल एग्रीमेंट में सिर्फ एक ऊपरी तौर पर टास्क–बेस्ड टेस्ट की जरूरत थी।

> डेंजर जोन में "सुरक्षित" माइग्रेशन की प्रैक्टिकैलिटी और एथिक्स

असल में, इंडिया–इजराइल एग्रीमेंट से इस बात पर बहुत बड़ा विवाद हुआ कि सेफ और एथिकल लेबर माइग्रेशन क्या होता है। जब मैंने अधिकारियों से इंडियन वर्कर्स को एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जोन में भेजने की सेफ्टी के बारे में पूछा, तो फेडरल और तेलंगाना स्टेट एजेंसियों ने सख्त सरकारी निगरानी का भरोसा देकर अपने फैसले को सही ठहराया। वर्कर्स को उनके काम के लिए अच्छी सैलरी मिलेगी, एग्रीमेंट में उनके खाने और रहने का भी इंतजाम होगा। अगर वर्कर्स खुद को किसी खतरनाक सिचुएशन में पाते हैं, तो इंडियन कॉन्सुलेट उनकी जरूरतों का ध्यान रखेंगे, जिसमें जरूरत पड़ने पर उन्हें निकालना भी शामिल है।

दूसरी तरफ, केरल राज्य की एजेंसियों ने इस बाइलेटरल एग्रीमेंट की सेफ्टी और एथिक्स पर सवाल उठाए। इस लड़ाई को लेकर केंद्र सरकार के ज्यादा गोलमोल रवैये के उलट, केरल के मुख्यमंत्री ने दिसंबर 2023 में गाजा में इजराइल के हमलों की ऑफिशियली निंदा की। केरल सरकार की रिक्रूटमेंट एजेंसियों ने कन्फर्म किया कि मुख्यमंत्री के बयान के बाद, उन्होंने इस एग्रीमेंट के तहत इजराइल में वर्कर्स भेजने से मना कर दिया। जैसा कि केरल राज्य के एक रिक्रूटमेंट एजेंट ने कहा:

"हमें (सरकारी एजेंसियों को) अलग–अलग जगहों पर कर्मचारियों की सही भर्ती पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें एक्टिव वॉर जोन में भेजना किसी भी तरह की नैतिकता के खिलाफ है!"

भारत सरकार वर्कर्स को बचाने में कितनी नाकाम है, यह हायरिंग और नौकरी से निकालने के तरीकों में भी साफ दिख रहा था। इजराइल में वर्कर्स के पहले बैच के आने के कुछ महीनों बाद, एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आई। पाया गया कि लगभग 2,000 भारतीय वर्कर्स को लोकल इजराइली कॉन्ट्रैक्टर्स ने उनके काम की जगहों से निकाल दिया, जिसके कारण कई लोगों को इजराइल से पूरी तरह से डिपोर्ट कर दिया गया। एम्प्लॉयर्स ने नौकरी से निकालने का कारण "स्किल्स की कमी" बताया। और सरकार इस स्थिति को ठीक करने के लिए कुछ खास नहीं कर सकी। इस घटना ने "सुरक्षित, व्यवस्थित और जिम्मेदार" माइग्रेशन को आसान बनाने के इस प्रोग्राम के विजन में कई कमियों को सामने लाया।

> श्रमिकों की आवाज को शामिल करना

आखिर में, केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा, सिविल सोसाइटी भी मायने रखती है। पारंपरिक रूप से, मजदूर संगठन, नागरिक समूह और ट्रांसनेशनल लेबर नेटवर्क माइग्रेंट अधिकारों की रक्षा करने में अहम भूमिका निभाते रहे हैं। मेरे इंटरव्यू से पता चलता है कि जैसे–जैसे माइग्रेंट लेबर का सरकारी मैनेजमेंट बढ़ रहा है, माइग्रेंट वर्कर ऑर्गनाइजर की आवाज कम होती जा रही है। उदाहरण के लिए, भारतीय ट्रेड यूनियनों ने इजराइल के साथ भारत के सौदे का विरोध किया, यह तर्क देते हुए कि फिलिस्तीनियों पर चल रहे जुल्म को बढ़ावा बिल्कुल भी नैतिक नहीं है। फिर भी, यूनियनों और दूसरे माइग्रेंट संगठनों ने पुष्टि की कि उन समझौतों को बनाते समय उनसे सलाह नहीं ली गई थी।

आयोजकों ने कहा कि माइग्रेंट वर्कर की सुरक्षित और सही भर्ती की दिशा में कोई भी कदम उठाने से पहले जमीनी स्तर पर माइग्रेंट वर्कर के अधिकारों की रक्षा करने वालों की सोच को ध्यान में रखना जरूरी है। ग्लोबल बॉर्डर को सख्त करने के मामले में, उनका शामिल होना और भी जरूरी हो जाता है, खासकर ट्रांसनेशनल लेवल पर। माइग्रेंट वर्कर को ट्रेनिंग देने और उन्हें तैयार एम्प्लॉयर से मिलाने के अलावा, सुरक्षित और सही तरीके से माइग्रेशन की किसी भी उम्मीद के लिए माइग्रेंट वर्कर के अधिकारों को पक्का करने के लिए एक ज्यादा सबको साथ लेकर चलने वाले नजरिए की जरूरत होगी। ■

संपर्क करें:
अश्विन कुमार <ak2398@cornell.edu>

> वैश्विक देखभाल श्रृंखलाओं पर पुनर्विचार: वैश्विक दक्षिण की प्रवासी महिलाएँ

मारिया कैमिला वेगा–सालाजार, यूनिवर्सिदाद दे लॉस आन्देस, कोलंबिया, **कैरोलीना मोरेनो**, यूनिवर्सिदाद दे लॉस आन्देस, कोलंबिया, **सूएलन कैस्तिब्लांको–मोरेनो**, यूनिवर्सिदाद दे ला साये, कोलंबिया, **हावियर ए. पिनेडा डी.**, यूनिवर्सिदाद दे लॉस आन्देस, कोलंबिया

जंगल में बस्ती के टेंट और फुटपाथ पर कपड़े लटके हुए हैं।
श्रेय: लूना एंड्राडे अरांगो, पिक्सेल्स द्वारा

इक्कीसवीं सदी की शुरुआत में, समाजशास्त्री अर्ली होशचाइल्ड ने ग्लोबल केयर चेन का विचार पेश किया – यह महिलाओं का पारदेशीय नेटवर्क है जो देखभाल की जिम्मेदारियों को सीमा पार, आम तौर पर गरीब देशों से अमीर देशों में हस्तांतरण करता है। इस संकल्पना ने एक मजबूत अकादमिक क्षेत्र को जन्म दिया, जो यह विश्लेषण करता है कि जेंडर, वर्ग और प्रवासन देखभाल के साथ कैसे जुड़े हैं। ज्यादातर साहित्य दक्षिण–उत्तर प्रवासन पर केंद्रित रहा है: देखभाल की बढ़ती मांग बढ़ती को पूरा करने हेतु वैश्विक दक्षिण की महिलाओं का संपन्न देशों की ओर प्रवास। लेकिन तब क्या होता है जब देखभाल शृंखलाएँ वैश्विक दक्षिण के अंदर संचालित होती हैं? लैटिन अमेरिकी विद्वान इसी की जांच कर रहे हैं, जिससे चिली, ब्राजील, अर्जेंटीना और हाल ही में कोलंबिया जैसे देशों में प्रवासन और देखभाल–कार्य के जटिल पैटर्न का पता चला है।

यह आलेख दक्षिण–दक्षिण प्रवासन पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें वेनेजुएला की उन महिलाओं के मामले को इस्तेमाल किया गया है जो बड़ी संख्या में 2015 से कोलंबिया प्रवास कर गई हैं। 2023 के आखिर तक, लगभग 2.9 मिलियन वेनेजुएला निवासी कोलंबिया चले गए थे, जिसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से थोड़ी ज्यादा थी। इनमें से अनेक महिलाएँ न केवल अस्थिर आव्रजन नीतियों और विरोधी श्रम–बाजार परिस्थितियों से जूझ रही हैं, बल्कि भुगतानयुक्त तथा अवैतनिक देखभाल–कार्य की जिम्मेदारियाँ भी वहन कर रही हैं।

> कोलंबिया में देखभाल–कार्य: एक जटिल परिदृश्य

लंबे समय से कोलंबिया सशस्त्र संघर्ष के कारण उत्पन्न आंतरिक विस्थापन से प्रभावित रहा है, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में महिलाएँ अनौपचारिक देखभाल और घरेलू कार्य क्षेत्रों में कार्यरत हैं। अब, यह देश अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों, विशेष रूप से वेनेजुएलाई

>>

महिलाओं, के लिए एक प्रमुख गंतव्य भी बन गया है।

प्रारंभिक चरण में, वेनेजुएला से आए प्रवासियों की बढ़ती संख्या के प्रति कोलंबियाई सरकार ने मानवीय सहायता के साथ प्रतिक्रिया दी। बाद में, सरकार ने कानूनी नियमितीकरण के उपाय पेश किए, जिनमें सबसे उल्लेखनीय था अस्थायी संरक्षण परमिट (च्च्ज), जिसने प्रवासियों को कार्य के अवसरों और बुनियादी सेवाओं तक पहुँच प्रदान की। हालाँकि, प्रशासनिक विलंब, बदलती राजनीतिक इच्छाशक्ति, और सीमित कार्यान्वयन क्षमता के कारण अनेक प्रवासी अब भी बिना दस्तावेजों के रह गए हैं, जिससे वे श्रम शोषण और असुरक्षा के प्रति और अधिक संवेदनशील हो गए हैं।

यह स्थिति विशेष रूप से देखभाल अर्थव्यवस्था में स्पष्ट दिखाई देती है। कोलंबिया के आधिकारिक घरेलू सर्वेक्षण (GEIH) के आंकड़ों का उपयोग करते हुए, यह सामने आता है कि अपेक्षाकृत उच्च शिक्षा होने के बावजूद, वेनेजुएलाई महिलाएँ कम वेतन, अनौपचारिक क्षेत्रोंकृजैसे आतिथ्य सेवाएँ, खाद्य सेवा, और खुदराकृमें अनुपात से अधिक संख्या में केंद्रित हैं। आश्चर्यजनक रूप से, घरेलू कार्य इन महिलाओं का प्रमुख क्षेत्र नहीं है। यह क्षेत्र मुख्यतः आंतरिक रूप से विस्थापित कोलंबियाई महिलाओं द्वारा भरा जाता है, जो यह दर्शाता है कि कोलंबिया के आंतरिक संघर्षों ने उसके स्वयं के देखभाल श्रम–बाजार को किस प्रकार आकार दिया है।

जो वेनेजुएलाई महिलाएँ घरेलू कार्य में संलग्न हैं, वे आमतौर पर अपने कोलंबियाई समकक्षों की तुलना में अधिक युवा और अधिक शिक्षित होती हैं, फिर भी वे अधिक अनौपचारिकता, और सामाजिक सुरक्षा से बहिष्करण की उच्च दरों का सामना करती हैं। उदाहरण के लिए, 2023 में 40% वेनेजुएलाई घरेलू श्रमिकों के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं था, और केवल 7% ही सेवानिवृत्ति बचत प्रणालियों से जुड़ी हुई थींकृजबकि वे पूर्णकालिक कार्य कर रही थीं। अधिकांश के पास केवल मौखिक श्रम अनुबंध होते हैं, जिससे उनकी अस्थिरता और भी बढ़ जाती है।

> संख्याओं से परेः एक नारीवादी आलोचना

हमारा अध्ययन देखभाल–कार्य के विश्लेषण के लिए एक अधिक अंतर्विभाजित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल देता है। यहाँ केवल लिंग ही निर्णायक कारक नहीं हैं; बल्कि राष्ट्रीय मूल, कानूनी स्थिति, जाति, आयु, और शिक्षाकृये सभी मिलकर यह निध् ाारित करते हैं कि देखभाल की जिम्मेदारियाँ किस प्रकार वितरित होती हैं, और किन्हें इस प्रक्रिया से बाहर रखा जाता है।

वेनेजुएला के संदर्भ से वर्तमान प्रवासन और श्रम नीतियों की टिकाऊपन पर भी गंभीर प्रश्न उठते हैं। कोलंबिया का मानवीय सहायता से तथाकथित "सामाजिक–आर्थिक एकीकरण" की ओर झुकाव अभी तक प्रवासी महिलाओं के लिए वास्तविक सुरक्षा या अवसरों में परिणत नहीं हुआ है। हाल ही के राजनीतिक परिवर्तनों ने तो वेनेजुएला में जारी अस्थिरता के बावजूद स्वैच्छिक वापसी के आह्वान भी शुरू कर दिए हैं।

हमारा तर्क है कि अस्थायी परमिटों और राजनीतिक विवेकाधि ाकार पर निर्भर रहने के बजाय, कोलंबिया जैसे देशों को मजबूत और स्थायी प्रवासन नीतियों की आवश्यकता हैकृऐसी नीतियाँ जो देखभाल–कार्य के मूल्य को मान्यता दें और दस्तावेजी स्थिति चाहे जो हो, देखभाल प्रदान करने वाली महिलाओं के अधिकारों की गारंटी सुनिश्चित करें।

> वैश्विक दक्षिण में देखभाल शृंखलाओं पर पुनर्विचार

यह शोध लैटिन अमेरिकी विद्वत्ता के उस विस्तृत होते साहित्य में योगदान देता है जो देखभाल प्रवासन के यूरोकेन्द्रित मॉडलों को चुनौती देता है। दक्षिण से उत्तर की ओर श्रम के एक–तरफा प्रवाह को मान लेने के बजाय, हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि क्षेत्रीय संदर्भों में देखभाल की वास्तविकताएँ गतिशील, बहुस्तरीय और जटिल होती हैं। कोलंबिया में देखभाल निर्यात भी होती है और आयात भीः अनेक कोलंबियाई लोग प्रवासी के रूप में देश छोड़ चुके हैं, वहीं यह देश स्वयं भी विदेश से आए बड़ी संख्या में देखभाल–कार्यकर्ताओं को आश्रय दे रहा है।

इसके अतिरिक्त, वैश्विक दक्षिण में देखभाल अक्सर विस्थापन, असमानता, और राज्य की उपेक्षा द्वारा आकार ग्रहण करती है। यह केवल रोजगार का विषय नहीं, बल्कि महिलाओं के बीच जीवित रहने और आपसी एकजुटता का प्रश्न भी है। यहाँ देखभाल का वितरण प्रायः अनौपचारिक नेटवर्क, पारिवारिक व्यवस्थाओं और सामुदायिक रणनीतियों के माध्यम से होता है, प्रायः राज्यीय समर्थन के अभाव में।

कोलंबिया में वेनेजुएलाई महिलाएँ, प्रवासी होने और देखभालकर्ता होने के अर्थ को नये सिरे से परिभाषित कर रही हैं। उनके अनुभव वैश्विक देखभाल शृंखलाओं के सरल मॉडलों को प्रश्नांकित करते हैं और हमें यह समझने के लिए प्रेरित करते हैं कि देखभाल केवल श्रम नहीं, बल्कि राजनीतिक संघर्ष और सामाजिक परिवर्तन का भी एक स्थल है। इन वास्तविकताओं का दस्तावेजीकरण करके, यह अध्ययन प्रवासन और देखभाल की एक ऐसी अधिक जमीनी, समावेशी समाजशास्त्र की आवश्यकता पर बल देता है जो जीवन की निरंतर गतिशीलता में मार्ग खोजती महिलाओं की आवाज और एजेंसी को केंद्र में रखे। ■

संपर्क करें:
मारिया कैमिला वेगा–सालाजार <mc.vega611@uniandes.edu.co>
कैरोलीना मोरेनो <camoreno@uniandes.edu.co>
सूएलन कैस्तिब्लांको–मोरेनो <secastiblanco@unisalle.edu.co>
हावियर ए. पिनेडा डी. <jpineda@uniandes.edu.co>

> चीन और सिंगापुर में देखभाल श्रम प्रवासन का "मोबाइल डेवलपमेंटलिज्म"

लिन यू लिंग, यॉर्क विश्वविद्यालय, कनाडा और **यूनहुई ये**, यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया, कनाडा द्वारा

घरेलू सहायकों का छुट्टी का दिन
श्रेय: रेक्स पे, क्रिएटिव कॉमन्स CC BY 2.0 द्वारा

कोविड–19 महामारी ने देखभाल–कार्य और प्रवासी घरेलू श्रमिकों पर वैश्विक निर्भरता की ओर पुनः ध्यान आकर्षित किया। फिर भी, समान प्रकार के संघर्षों के बावजूद, इन श्रमिकों के अनुभवों का विभिन्न राष्ट्रीय संदर्भों में तुलनात्मक विश्लेषण बहुत कम किया गया है। पूर्वी एशिया, यूरोप, तथा चीन और भारत जैसे बड़े देशों के भीतर इस विषय पर विकसित हो रही सशक्त विद्वत्ता ने हाल के वर्षों में गति अवश्य प्राप्त की है, किंतु यह अब भी मुख्यधारा के शोध संदर्भों में अपेक्षाकृत हाशिये पर बनी हुई है। हम इस महत्वपूर्ण विमर्श में योगदान देते हुए चीन में घरेलू देखभाल श्रमिकों (DCWsw) और सिंगापुर में विदेशी घरेलू श्रमिकों (FDWsw) के मामलों को एक साथ प्रस्तुत करते हैं। इसके माध्यम से हम यह दिखाते हैं कि किस प्रकार समान प्रकार की आर्थिक विकास रणनीतियाँ समानांतर रूप से शोषण के रूपों को जन्म देती हैं।

> पुराने विकास मॉडल: ग्रामीण/पारंपरिक को "पिछड़ा" और शहरी/आधुनिक को "श्रेष्ठ" मानना

हमारे लेख "सेम बट डिफरेंट: चीन और सिंगापुर में देखभाल श्रम प्रवासन", जो वर्क आर्गेनाईजेशन लेबर एंड ग्लोबलीसाशन पत्रिका के आगामी विशेषांक "स्पेशलिटीज ऑफ डोमेस्टिसिटी" में प्रकाशित होने वाला है, में हम नारीवादी राजनीतिक अर्थव्यवस्था के अध्ययन तथा ऑनलाइन नृवंशविज्ञानात्मक अनुसंधान के आधार पर विभिन्न राष्ट्रीय संदर्भों में घरेलू श्रमिकों के अनुभवों की तुलना करते हैं। यह विश्लेषण विकासवादी विचारधाराओं में निहित शोषण के साझा पैटर्न को उजागर करता है। हम उस परिस्थिति को स्पष्ट करते हैं जिसे हम "मोबाइल डेवलपमेंटलिज्म" कहते हैंकृअर्थात् रैखिक और चरणबद्ध विकास की ऐसी विचारधाराएँ जो लोकप्रिय आधुनिकीकरण सिद्धांत के प्रभाव में ग्रामीणध्पारंपरिक समाजों को "निम्न" और शहरी/आधुनिक समाजों को "श्रेष्ठ" के रूप में वर्गीकृत करती हैं।

प्रवासन की गतिशीलता इन सामाजिक पदानुक्रमों से गहराई से प्रभावित होती है। चीन में ग्रामीण घरेलू श्रमिकों के साथ उनके अपेक्षाकृत निम्न suzhi (मानवीय गुणवत्ता) के आधार पर भेदभाव किया जाता है। वहीं सिंगापुर में विदेशी घरेलू श्रमिकों को अक्सर एशिया के "कम विकसित" क्षेत्रों से आने वाला माना जाता है। इस प्रकार दोनों ही समूहों की प्रवासी महिलाएँ उस "मोबाइल डेवलपमेंटलिज्म" के अधीन होती हैं, जो उपनिवेशकालीन सभ्यतागत श्रेणीकरण की परंपरा से जुड़ा है, जहाँ कुछ लोगों को स्वभावतः अधिक "आधुनिक" या "विकसित" माना जाता है।

यह श्रेणीकरण कोई संयोग नहीं है। इसका स्रोत द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद विकसित आधुनिकीकरण सिद्धांत में निहित है, जो तथाकथित "पिछड़े" ग्रामीणध्पारंपरिक समाजों से "उन्नत" शहरी/आधुनिक समाजों की ओर रैखिक प्रगति की धारणा को महिमामंडित करता है। चाहे श्रमिक अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार प्रवास करें (जैसे सिंगापुर के मामले में) या देश के भीतर ग्रामीणदृशहरी विभाजन को पार करें (जैसे चीन में), उन्हें अपने मानवीय अस्तित्व और श्रम दोनों के अवमूल्यन का सामना करना पड़ता है।

> देखभाल संकट को समझना

राज्य प्रायः विकास–रणनीतियों का उपयोग महिलाओं तथा उनके द्वारा किए जाने वाले देखभाल–कार्य के अवमूल्यन को उचित ठहराने के लिए करते हैं। आर्थिक आधुनिकीकरण और देश को "उन्नत" बनाने के राष्ट्रीय लक्ष्य इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण, किंतु एकमात्र, हिस्सा नहीं हैं। नारीवादी राजनीतिक अर्थव्यवस्था के अध्ययन में इस बात पर व्यापक शोध उपलब्ध है कि किस प्रकार देखभाल–कार्य का व्यवस्थित रूप से अवमूल्यन किया जाता है।

चाहे यह श्रम ग्रामीण चीनी महिलाओं द्वारा किया जाए या एशियाई प्रवासी महिलाओं द्वारा, इसे अक्सर अदृश्य और शोषण के लिए उपलब्ध बना दिया जाता है। यह स्थिति उन लैंगिक विचारध ाराओं से निर्मित होती है जो रंगभेद से प्रभावित महिलाओं को स्वाभाविक रूप से दूसरों की सेवा के लिए उपयुक्त मानती हैं। >>

यह परिस्थिति वैश्विक स्तर पर देखभाल–कार्य के मूल्यांकन में व्यापक विफलताओं को भी दर्शाती है। देखभाल को प्रायः महिलाओं का "स्वाभाविक कर्तव्य" समझा जाता हैकृएक ऐसी असीम और मुक्त प्रवाहित होने वाली संसाधन के रूप में, जो "प्रेम" से प्रेरित है, न कि ऐसा श्रम जिसके लिए उचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए।

>suzhi (मानवीय गुणवत्ता) और "कम विकसित" एशिया की धारणा

चीन की हुकौ (घरेलू पंजीकरण) प्रणाली, जो 1950 के दशक में स्थापित की गई थी, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच एक संस्थागत विभाजन उत्पन्न करती है। ग्रामीण प्रवासी शहरों में काम तो कर सकते हैं, लेकिन वे शहरी नागरिकों को मिलने वाले लाभ – जैसे स्वास्थ्य सेवाएँ, अपने बच्चों के लिए शिक्षा, या सामाजिक सुरक्षा – प्राप्त नहीं कर पाते। "सुजी" (मानवीय गुणवत्ता) की धारणा इस स्थिति को और मजबूत करती है, क्योंकि इसके माध्यम से ग्रामीण लोगों को "निम्न गुणवत्ता" वाला बताया जाता है – ऐसे लोग जिन्हें असभ्य माना जाता है और जो चीन के आधुनिकीकरण में बाधा उत्पन्न करते हैं।

एक घरेलू देखभाल श्रमिक ने इस धारणा को साहसपूर्वक चुनौती दी, जब उसके नियोक्ता ने उसे नववर्ष के दिन अवकाश देने से इनकार कर दिया और कहाः "एक बाओमु (घरेलू श्रमिक के लिए प्रयुक्त अपमानजनक शब्द) होने के नाते तुम्हें सरकारी अवकाश माँगने का क्या अधिकार है?" उसने उत्तर दियाः "क्या बाओमु चीनी नागरिक नहीं हैं? यदि हैं, तो उन्हें वैधानिक अवकाश का अधिकार होना चाहिए।" उसके इस प्रतिरोध का परिणाम यह हुआ कि उसे अपनी नौकरी खोनी पड़ी।

सिंगापुर में विदेशी घरेलू श्रमिकों को अक्सर "कम विकसित" एशियाई देशों से आई महिलाओं के रूप में देखा जाता है और उनके साथ नस्ली भेदभाव किया जाता है। भर्ती वेबसाइटों पर उनके फोटो, व्यक्तिगत विवरण और "कौशल" इस प्रकार प्रदर्शित किए जाते हैं मानो वे तुलना के लिए प्रस्तुत किए गए उत्पाद हों। इसके अतिरिक्त, राज्य की अनिवार्य साथ–रहने (लिव इन) नीति और नियोक्ता–प्रायोजन प्रणालीकृजो कफाला प्रणाली से मिलती–जुलती हैकृऐसी निर्भरता–आधारित स्थितियाँ उत्पन्न करती है, जहाँ श्रमिकों के लिए नियोक्ता बदलना आसान नहीं होता, भले ही वे शोषण या दुर्व्यवहार का सामना कर रहे हों।

>समान चुनौतियाँ, भिन्न संदर्भ

चीनी घरेलू श्रमिक अपने ही देश के भीतर स्थानांतरित होने वाले सह–जातीय नागरिक होते हैं, जबकि सिंगापुर में उनके समकक्ष श्रमिक विदेशी नागरिक होते हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को पार करते हैं। फिर भी दोनों समूह कई समान प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हैं।

कानूनी असुरक्षा : चीन में 90% से अधिक घरेलू श्रमिकों के पास औपचारिक रोजगार अनुबंध नहीं होते, क्योंकि कानून के अनुसार केवल कंपनियों को ही नियोक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त है, न कि निजी परिवारों को। इसी प्रकार, सिंगापुर में विदेशी घरेलू श्रमिकों के पास अनुबंध तो होते हैं, पर उन्हें निम्नतम वीजा श्रेणी के अस्थायी "अतिथि श्रमिकों" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिन्हें हर दो वर्ष में नवीनीकृत करना पड़ता है।

लिव इन की व्यवस्था और शोषण : दोनों ही समूह प्रायः अपने नियोक्ता के घर में रहते हैं, जिससे उनसे चौबीसों घंटे उपलब्ध रहने की अपेक्षा की जाती है। सिंगापुर की एक विदेशी घरेलू श्रमिक ने बतायाः "मैं सुबह 4 बजे उठकर नाश्ता बनाती हूँ [...] मेरा आराम का समय रात 11 बजे से 12 बजे के बीच शुरू होता है, यह इस पर निर्भर करता है कि वे काम से कब घर लौटते हैं।" इसी तरह, एक चीनी घरेलू देखभाल श्रमिक की कविता में लिखा है; "जब तक मेरा सिर तकिए को छूता है, तब तक ग्यारह बज चुके होते हैं। थकी हुई, पसीने से भीगी, मैं बिस्तर पर लेटती हूँ और घर के बारे में सोचती हूँ।"

अमानवीय व्यवहार : दोनों समूह विकास–आधारित विचारधाराओं से प्रभावित उपेक्षापूर्ण और अपमानजनक व्यवहार का सामना करते हैं। चीन में नियोक्ता घरेलू श्रमिकों की "गैर–मानक मंदारिन" की आलोचना करते हैं और उन्हें "सही ढंग से" बोलने का अभ्यास करने के लिए बाध्य करते हैं। वहीं सिंगापुर में नियोक्ता विदेशी घरेलू श्रमिकों को ऐसे लोगों के रूप में देखते हैं जिन्हें शहरी जीवन के अनुरूप बनाने के लिए "अनुशासन" की आवश्यकता है। वे उनकी स्वच्छता, आधुनिक उपकरणों के उपयोग की जानकारी, और कथित रूप से "आरामप्रिय" ग्रामीण जीवनशैली की आलोचना करते हैं।

>निजी स्थानों में शोषण और विकासवादी विचारधाराएँ

हमारा तुलनात्मक दृष्टिकोण राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रवासन – दोनों पर ध्यान केंद्रित करता है। चीन में आंतरिक प्रवासन और सिंगापुर में अंतरराष्ट्रीय प्रवासन, दोनों ही विभिन्न स्तरों और संदर्भों में विकासवादी विचारधाराओं की उपस्थिति को उजागर करते हैं। ये दोनों परिस्थितियाँ उस स्थिति को जन्म देती हैं जिसे "घरेलूपन की स्थानिकताएँ" कहा जा सकता हैकृऐसे निजी स्थान जहाँ सार्वजनिक निगरानी और श्रम विनियमन से परे शोषण पनपता है।

वैश्विक विकास रणनीतियाँ स्थानीय स्तर पर ऐसे पदानुक्रम निर्मित करती हैं जो कुछ जनसमूहों को उपभोज्य श्रम के रूप में देखने को उचित ठहराती हैं। चाहे इसे ग्रामीणदृशहरी विकास अंतर के आधार पर समझाया जाए या अंतरराष्ट्रीय विकास असमानताओं के माध्यम से, परिणाम समान होता है; महिलाओं का देखभाल–कार्य एक ऐसी वस्तु में बदल जाता है जिसे अन्य परिवारों के सामाजिक पुनरुत्पादन को बनाए रखने के लिए निकाला जाता है।

"मोबाइल डेवलपमेंटलिज्म" की अवधारणा को समझना हमें अलग–अलग प्रतीत होने वाली परिस्थितियों के बीच संबंधों को देखने में सहायता करता है। चीन की घरेलू देखभाल श्रमिकाएँ, जो बुनियादी श्रम अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं, और सिंगापुर की विदेशी घरेलू श्रमिकाएँ, जो न्यायपूर्ण व्यवहार के लिए संगठित हो रही हैंकृदोनों ही ऐसी विकासवादी विचारधाराओं से उत्पन्न समान चुनौतियों का सामना करती हैं, जो उन्हें स्वाभाविक रूप से कम सम्मान और कम संरक्षण के योग्य मानती हैं।

अंततः, इन समानताओं की सामूहिक पहचान विभिन्न संदर्भों के बीच अंतरराष्ट्रीय और संबंधपरक एकजुटता तथा सीखने की संभावनाएँ खोलती है। दोनों समूहों की महिलाएँ उल्लेखनीय दृढ़ता और सहनशीलता का परिचय देती हैं। वे ऑनलाइन मंचों का उपयोग अपने अनुभव साझा करने, पारस्परिक समर्थन प्रदान करने और अन्यायों को दर्ज करने के लिए करती हैं। उनकी आवाजें देखभाल–कार्य के मुख्यधारा में प्रचलित अवमूल्यन और श्रम–शोषण को चुनौती देती हैं तथा उनकी पूर्ण मानवीय गरिमा की मान्यता की मांग करती हैं। ■

संपर्क करें:
लिन यू लिंग <lynnngyl@yorku.ca>
यूनहुई ये <yunhuiye@uvic.ca>

> गैर–पश्चिमी प्रवासियों के लिए दुबई का विशिष्ट आकर्षण

अंजू मैरी पॉल, मुस्तफा यावाश, और **सेजिन पार्क**, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी अबू धाबी, यूएई द्वारा

सास्किया सैसन के उस क्लासिक कार्य के बाद, जिसमें न्यूयॉर्क, लंदन और टोक्यो को वैश्विक नगरों के रूप में वर्णित किया गया था, अन्य नगरों को भी पहचाना और रैंक किया गया – मुख्यतः आर्थिक मानदंडों के आधार पर। कॉर्पोरेट वैश्वीकरण के केंद्रों के रूप में, वैश्विक शहर, जिनका संचालन उच्च–कौशल प्रवासियों द्वारा किया जाता है, प्रमुख बहुराष्ट्रीय निगमों के कार्यालयों का केंद्र होते हैं। जैसे–जैसे ये शहर ऐसे प्रतिभाशाली श्रमिकों को आकर्षित करने की प्रतिस्पर्धा करते हैं, विश्लेषकक्रृजो इन शहरों का मूल्यांकन और रैंकिंग करते हैं – तथा नीति–निर्माताकृजो उन्हें बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं – अक्सर सार्वभौमिक मानदंडों का उपयोग करते हैं, मानो सभी प्रवासी केवल उच्च आय, आरामदायक जीवनशैली और बेहतर सुरक्षा जैसी एक ही प्राथमिकताओं द्वारा संचालित हों। यहाँ तक कि वैश्विक शहरों के सांस्कृतिक महत्व का आकलन भी संग्रहालयों और प्रमुख स्थलों की संख्या के आधार पर किया जाता है।

हम यह पूछते हैं कि क्या वैश्विक शहरों के कुछ अतिरिक्त, विशिष्ट आयाम हो सकते हैं, जो उच्च–कौशल प्रवासियों के विशेष उपसमूहों के लिए उनकी आकर्षकता बढ़ाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए, हम दुबई का अध्ययन करते हैं – एक ऐसा शहर जो वैश्विक नगर रैंकिंग में तेजी से ऊपर उठा है। दुबई में गैर–पश्चिमी प्रवासी पेशेवरों के साथ किए गए सर्वेक्षणों और विस्तृत साक्षात्कारों के आधार पर, हमें पता चलता है कि दुबई दक्षिण एशिया तथा मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका (MENA) क्षेत्रों से आए प्रवासियों के लिए एक वैश्विक और साथ ही एक स्थानीय शहरकृदोनों रूपों मेंकृविशेष आकर्षण रखता है।

एक सामान्य वैश्विक शहर के रूप में, दुबई (1) अधिक आर्थिक लाभ, (2) उच्च जीवन–स्तर, और (3) अधिक सुरक्षा – जिन्हें प्रवासी अक्सर "वैश्विक उत्तर" की निर्मित छवि से जोड़ते हैं– प्रदान करता है। लेकिन दुबई इन प्रवासियों को "स्थानीय" लाभ भी देता है; (4) उनके मूल देशों के भौगोलिक निकटता, (5) सांस्कृतिक परिचय – क्योंकि इन क्षेत्रों से आने वाले प्रवासियों की बड़ी और दीर्घकालिक आबादी यहाँ रहती है, और अंततः (6) उनकी विशिष्ट धार्मिक और नस्लीय पहचानों के प्रति अधिक सहिष्णुता।

> दुबई का पृष्ठभूमि संदर्भ

3.5 मिलियन आबादी वाला शहर दुबई, संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा शहर है। पिछले दो दशकों में, दुबई ने तीव्र विकास करते हुए डम्छ। क्षेत्र में कार्यरत बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए पसंदीदा क्षेत्रीय मुख्यालय के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया है। यह शहर स्वयं को मध्य पूर्व का सबसे व्यवसाय–हितैषी और उदार केंद्र होने पर गर्व करता है। साथ ही, सार्वजनिक सुरक्षा, सरकार पर विश्वास, और जीवन–योग्यता जैसे मानकों पर दुबई लगातार उच्च अंक प्राप्त करता हैकृजो किसी शहर की प्रवासी–अनुकूलता को मापने के लिए प्रयुक्त प्रमुख मानदंडों में शामिल हैं।

इसके साथ ही, दुबई (और संपूर्ण यूएई) अपनी आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने के लिए प्रवासियों पर अत्यधिक निर्भर है। वर्ष 2023 में दुबई की 92% आबादी गैर–एमिराती थी। जबकि लोकप्रिय कल्पना में दुबई के प्रवासियों को अक्सर पश्चिमी नागरिकों के रूप में देखा जाता है, वास्तविकता यह है कि प्रवासियों का बहुत बड़ा हिस्सा दक्षिण एशिया और डम्छ। क्षेत्र से आता है।

> एक भिन्न प्रकार के प्रवासी

दुबई के तुलनात्मक आकर्षण का मूल्यांकन करने के लिए, हमने उच्च–कौशल प्रवासियों का सर्वेक्षण और साक्षात्कार किया, जो यूएई से सीधे सटे तीन विश्व–क्षेत्रोंकृदक्षिण एशिया, MENA, और उप–सहारा अफ्रीकाकृसे आते हैं। हमने उत्तरी अफ्रीकी देशों को डम्छ। क्षेत्र का हिस्सा माना, और शेष अफ्रीका से अलग, क्योंकि इन देशों के लोग अरबी बोलते हैं और जातीय रूप से स्वयं को अरब मानते हैं।

हमारे सर्वेक्षण डेटा से पता चला कि प्रवासन से पहले तीनों समूहों में यूएई आने की प्रबल इच्छा थी (1 से 5 की स्केल पर औसत 3.68)। लेकिन, दक्षिण एशियाई और MENA प्रतिभागियों ने यूएई में लंबे समय तक रहने की इच्छा उप–सहारा अफ्रीकी प्रवासियों की तुलना में कहीं अधिक व्यक्त की (3.35 बनाम 2.71)। यह अंतर इस तथ्य से संबंधित था कि इन तीनों समूहों ने यूएई के जीवन और अपने पूर्व देश के जीवन की तुलना करते हुए संतुष्टि के भिन्न स्तरों को व्यक्त किया।

दक्षिण एशियाई और डम्छ। उत्तरदाताओं ने यूएई पहुँचने पर तीन प्रमुख क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार महसूस कियाकृकरियर के अवसर, जीवन–स्तर, और सांस्कृतिक परिचितता। इसके विपरीत, उप–सहारा अफ्रीकी उत्तरदाताओं ने केवल कार्य और जीवन–स्तर के क्षेत्रों में ही उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया। सांस्कृतिक परिचितता के संदर्भ में उन्हें लाभ नहीं मिला, क्योंकि यूएई में उप–सहारा अफ्रीकी समुदाय अपेक्षाकृत छोटे और बिखरे हुए हैं। परिणामस्वरूप, उप–सहारा अफ्रीकी उत्तरदाता यूएई से आगे किसी तीसरे देश में प्रवास करने में अधिक रुचि रखते थे, जबकि अन्य दो समूहों में यह प्रवृत्ति कम थी।

> दुबई के आर्थिक, जीवनशैली और सुरक्षा संबंधी लाभ

इन 46 वैश्विक रूप से गतिशील पेशेवरों– जो दुबई आने से पहले अपने मूल देशों के बाहर रह चुके थे– के साथ किए गए हमारे गहन साक्षात्कार ने इन अलग–अलग दृष्टिकोणों को स्पष्ट करने में सहायता की। तीनों समूहों ने दुबई में प्राप्त आर्थिक लाभ, आरामदायक जीवनशैली, और अधिक सुरक्षा को प्रमुख विशेषताओं के रूप में रेखांकित किया। ये लाभ यूएई में प्रवासी के रूप में कार्यरत सभी कुशल प्रवासी–श्रमिकों पर लागू होते हैं, चाहे वे किसी भी देश से आए हों। दुबई द्वारा पेश किए जाने वाले वित्तीय लाभ कभी–कभी पश्चिमी देशों में समान पदों पर प्राप्त आय से भी अधिक हो सकते हैंकृआंशिक रूप से यूएई में कम मूल्य वर्धित कर (वैट) और व्यक्तिगत आयकर के अभाव के कारण।

साक्षात्कारदाताओं ने दुबई के उच्च जीवन–स्तर पर विशेष जोर

>>

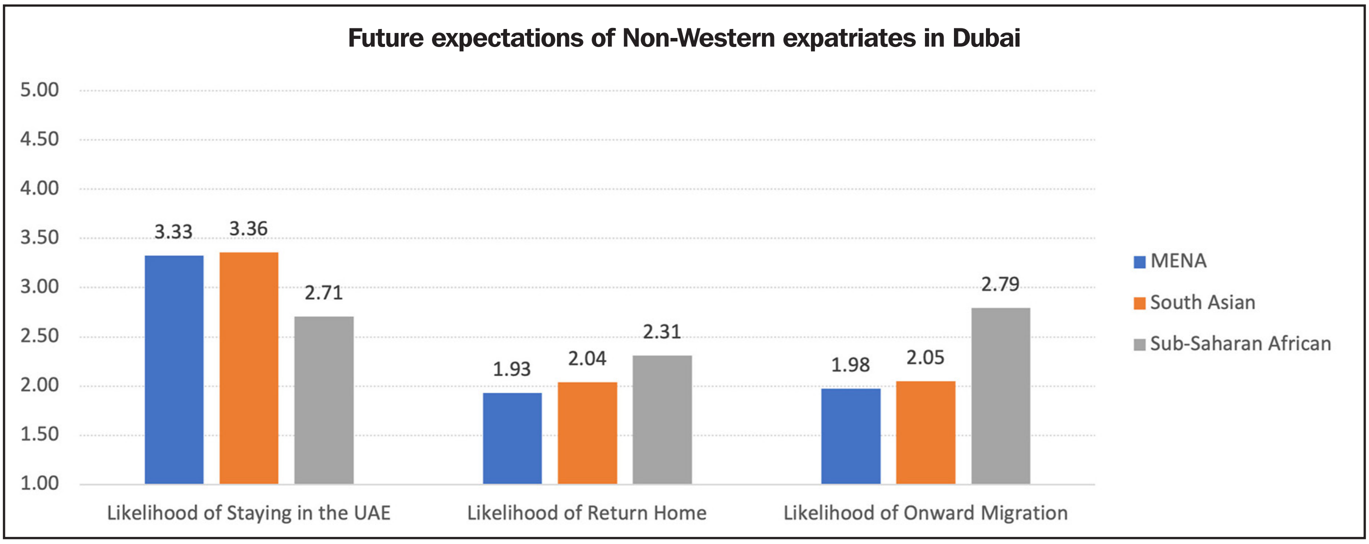

स्त्रोतः अंजू मैरी पॉल, मुस्तफा यावस, और सेजिन पार्क

दिया – जिसमें सुव्यवस्थित सार्वजनिक अवसंरचना और सुरक्षा की उच्च अनुभूति शामिल है। इसके अलावा, उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि दुबई में सुलभ और किफायती घरेलू श्रम आसानी से उपलब्ध है, क्योंकि एशिया और अफ्रीका से बड़ी संख्या में कम–वेतन प्रवासी यूएई में देखभाल और सेवा–क्षेत्र के कार्य के लिए आते हैं।

ये सभी विशेषताएँ मिलकर दुबई के एक प्रामाणिक "वैश्विक नगर" होने की पुष्टि करती हैं – ऐसा शहर जिसमें श्रम बाजार के उच्च और निम्न दोनों स्तरों पर बड़ी संख्या में प्रवासी आबादी निवास करती है।

> दुबईः दोनों दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप

दक्षिण एशियाई और MENA क्षेत्र के साक्षात्कारदाताओं ने दुबई की भौगोलिक निकटता पर भी विस्तार से चर्चा की, जो उन्हें अपने मूल देशों में परिवार से मिलने या परिवारजनों के दुबई आने के लिएकृयूएई के अपेक्षाकृत सहज पर्यटक वीजों के कारण – अधिक बार और किफायती यात्राएँ करने में सक्षम बनाती है। इन दोनों क्षेत्रों से मध्यम वर्ग के प्रवासी समुदायों की यूएई में लम्बे समय से मौजूदगी, तथा उनके साथ विकसित हुए सांस्कृतिक और सामाजिक संस्थानोंकृजैसे मस्जिदें, सुपरमार्केट और रेस्तराँ जहाँ हलाल एवं क्षेत्रीय खाद्य विकल्प उपलब्ध हैं, से लेकर ऐसे विद्यालय जहाँ उनके राष्ट्रीय पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं – के कारण दक्षिण एशियाई और डम्छ। प्रवासी अक्सर दुबई को "घर जैसा" अनुभव करने की बात करते हैं।

अंततः, इन साक्षात्कारदाताओं ने अपनी धार्मिक और नस्ली पहचानों की बेहतर स्वीकृति की भी चर्चा की – एक ऐसा अनुभव जो उन्हें वैश्विक उत्तर के शहरों में अक्सर नहीं मिलता था। इसके विपरीत, उप–सहारा अफ्रीकी साक्षात्कारदाता यूएई में नस्ली भेदभाव या समान सामाजिक–आर्थिक स्तर वाले बड़े सह–जातीय समुदायों की अनुपस्थिति के कारण उत्पन्न अकेलेपन की बात अधिक करते थे।

समग्र रूप से, हमारे निष्कर्ष इस बात पर जोर देते हैं कि वैश्विक/विश्व–नगरों पर आधारित विद्वत्ता को प्रवासी पेशेवरों की विविधता को ध्यान में रखना चाहिए—न कि एक सार्वभौमिक प्रवासी के आध ाार पर विश्लेषण करना चाहिए। कुछ विशिष्ट प्रवासी समूहों को विदेश में "घर जैसा" अनुभव कराने में शहरों की सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं की भूमिका को – सतही बहुसांस्कृतिकता की धारणाओं से परेकृऔर अधिक मान्यता दी जानी चाहिए।■

संपर्क करेंः
अंजू मैरी पॉल <anju.paul@nyu.edu>
मुस्तफा यावाश <anju.paul@nyu.edu>
सेजिन पार्क <sejin.park@nyu.edu>

> चीन के शिक्षा–प्रवासी :

देश में, विदेश में और वापसी के बाद

फेंग श्यू, यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया, कनाडा द्वारा

गाओकाओ. स्त्रोतः हुबेई डेली, यहाँ उपलब्ध हैः http://m.cnhubei.com/content/2019-06/08/content_10844871.html.

कई युवा चीनी प्रवासी बेहतर शिक्षा के माध्यम से सामाजिक उन्नति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यह अध्ययन आंतरिक और अंतरराष्ट्रीय शिक्षा–प्रवासियों के साथ–साथ "वापसी करने वालों" पर भी विचार करता है। शोध विशेष रूप से उनके जीवनानुभवों पर केंद्रित है, जो स्थानीय निवास–स्थिति प्राप्त करने की प्रक्रिया से जुड़े हैंकृजैसे शंघाई या बीजिंग का हुकौ (घरेलू निवास पंजीकरण), तथा कनाडा में स्थायी निवास (PR)। यद्यपि कार्यात्मक दृष्टि से कनाडाई नागरिकता हुकौ के अधिक निकट मानी जा सकती है, जबकि च्च उससे कम निकट है, फिर भी मेरे साक्षात्कारदाताओं के बीच नागरिकता का महत्व बहुत कम दिखाई दियाय मतदान–अधिकार का कहीं उल्लेख नहीं हुआ, और अन्यथा भी कनाडाई नागरिकता केवल चीन की यात्राओं या भविष्य में वहाँ वापसी की प्रक्रिया को अधिक जटिल बना देती है।

2024 से 2025 के बीच, मैंने कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में बारह चीनी शिक्षा–प्रवासियों तथा चीन के बीजिंग और शंघाई में पंद्रह शिक्षा–प्रवासियों का साक्षात्कार किया। इनमें से अधिकांश का

>>

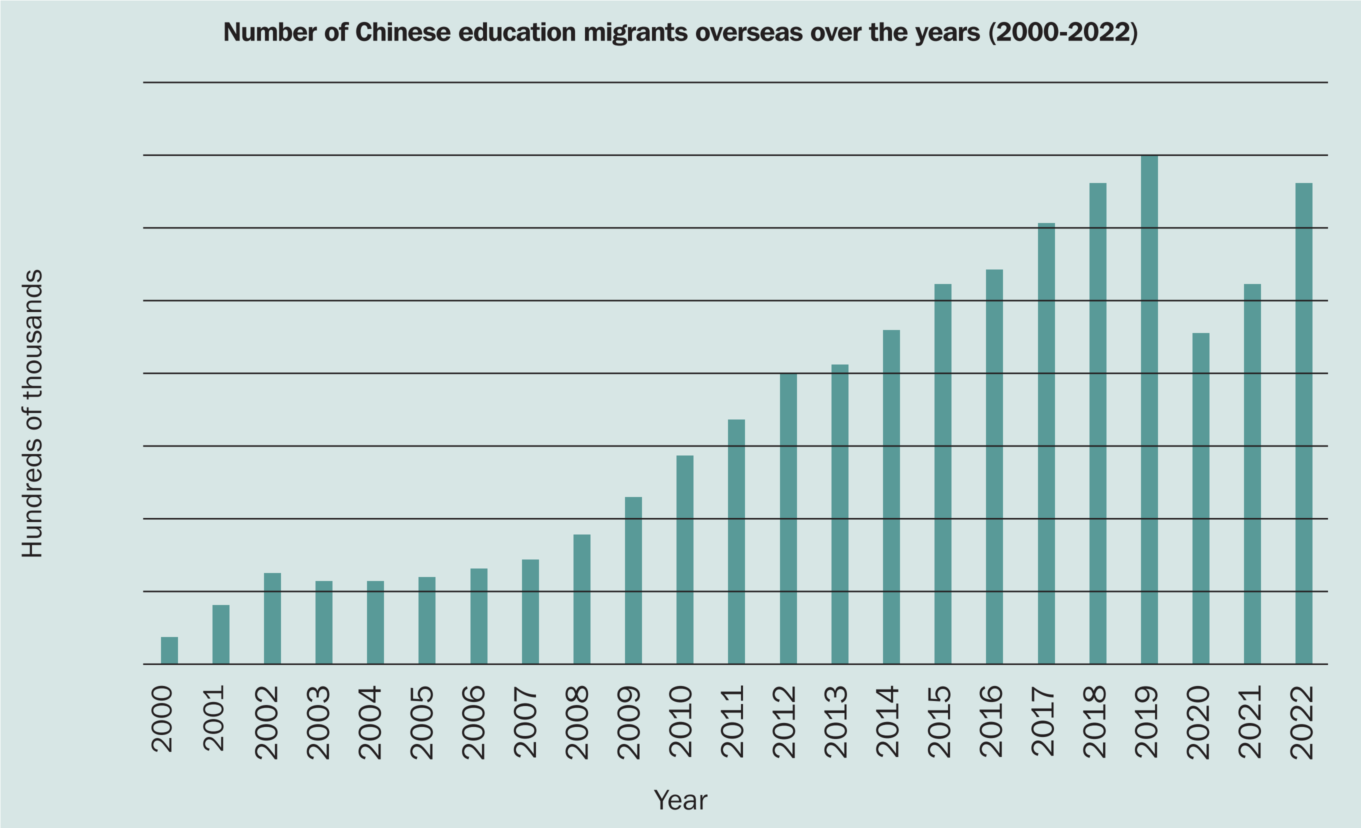

सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन से डाटा, द डेवेलोपमेंट ऑफ चाइनीज स्टूडेंट्स अब्रॉड (2023–2024) से रूपांतरित। यहाँ उपलब्ध है: https://web.archive.org/web/20240514045418/http://www.ccg.org.cn/archives/84327.

जन्म 1990 के दशक में हुआ थाय बहुत कम विवाहित थेय अधिकांश महिलाएँ थींय और प्रत्येक या तो कार्यरत था या रोजगार की तलाश में था।

इन सभी समूहों को एक ही अध्ययन में क्यों शामिल किया गया? पहला, समावेशन और बहिष्करण की "सीमांकन प्रक्रियाएँ" (bordering practices) केवल राष्ट्रीय सीमाओं पर ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय क्षेत्रों के भीतर भी घटित होती हैं। दूसरा, आंतरिक और अंतरराष्ट्रीय प्रवासन के अनुभव अक्सर एक–दूसरे से अंतर्संबद्ध और आच्छादित होते हैं। और अंततः, शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता के बीच संबंध हमेशा सरल या रैखिक नहीं होता।

> तरल और परस्पर आच्छादित प्रवासी अनुभव

मेरे साक्षात्कारों ने "देश के भीतर" और "विदेश में" रहने वाले प्रवासियों के बीच स्थापित सरल विरोधों को चुनौती दी। तथाकथित "आंतरिक प्रवासियों" में से केवल तीन को छोड़कर सभी ने विदेश में अध्ययन करने के बाद "वापसी" की थी, किंतु उनमें से कोई भी अपने मूल नगर नहीं लौटा था। दूसरी ओर, बीजिंग या शंघाई में रहने वाले कई "वापसी प्रवासी" भी इन स्थानों को अस्थायी मानते थे, यद्यपि सभी इन शहरों को महानगरीय, विकसित और आकर्षक अवसर–स्थलों के रूप में देखते थे।

कनाडा में रहने वाले अधिकांश साक्षात्कारदाता वहीं रहना चाहते थे, परंतु स्थायी निवास प्राप्त कर चुके लोग भी चीन में रहने वाले अपने परिजनों और मित्रों से मिलने के लिए नियमित रूप से लौटते थे, और कुछ अपने माता–पिता के वृद्ध होने पर स्थायी रूप से वापस जाने की योजना भी बना रहे थे। (एक हालिया अध्ययन के अनुसार, विश्वभर में शिक्षा–प्रवासियों में से 80% से अधिक अंततः अपने देश लौट आते हैं।) समग्र रूप से देखा जाए तो शिक्षा–प्रवासियों के अनुभव अस्थायी, तरल, परस्पर आच्छादित और जटिल प्रकृति के पाए गए।

> स्थानिक असमानताएँ और शैक्षिक गतिशीलता

मेरे उत्तरदाता सुधार–युग के एक अत्यंत गतिशील चीन में पले–बढ़े। उनकी आकांक्षाओं को सहारा देने वाली यह स्थानिक गतिशीलता गहरी भौगोलिक असमानताओं को भी प्रतिबिंबित करती है। यह आंशिक रूप से चीन में अपेक्षाकृत उदार हुकौ और पासपोर्ट नीतियों, मेजबान देशों की प्रतिभा–आकर्षण नीतियों, तथा परिवहन और संचार के उन्नत एवं सस्ते साधनों (जैसे बुलेट ट्रेनें, हवाई यात्रा और सोशल मीडिया) पर निर्भर करती है।

जैसे–जैसे ये शिक्षा–प्रवासी आगे बढ़े, व्यापक प्रवासन दबावों ने उनके मूल नगरों को भी बदल दिया। चीन के उत्तर–पूर्व में उद्योगहीनता के कारण कारखाने बंद हुए और लोगों को बाहर प्रवास करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बाजार और राज्य–प्रेरित नगरीकरण ने अन्य क्षेत्रों की सामाजिक संरचना को भी मूल रूप से बदल दिया। श्रमिक प्रवासी अक्सर अपने गृह–नगरों में परिजनों के लिए नए घर बनाते हैं। गृह–नगरों को अधिक घनिष्ठ सामाजिक संबंधों के स्थान के रूप में याद किया जाता है, किंतु साथ ही उन्हें पीछे छूट चुके स्थानों के रूप में भी देखा जाता है।

बीजिंग और शंघाई के प्रति प्राथमिकताएँ संभवतः इस अध्ययन की चयन–प्रक्रिया से प्रभावित रही हों, किंतु वे आश्चर्यजनक नहीं हैं। शंघाई या बीजिंग के हुकौ धारकों को देश के भीतर ही शीर्ष चीनी विश्वविद्यालयों तक अधिक सहज पहुँच प्राप्त होती है। इसके विपरीत, ग्रामीण या छोटे कस्बों से आने वाले उत्कृष्ट छात्र –जैसे मेरे कई उत्तरदाता – को कम से कम जूनियर हाई स्कूल के स्तर से ही अध्ययन हेतु स्थान परिवर्तन करना पड़ता है और प्रायः छात्रावासों

>>

में रहना पड़ता है।

गाओकाओ (राष्ट्रीय कॉलेज प्रवेश परीक्षा) की तैयारी अत्यंत व्यापक और सर्वग्राही होती है। इसके लिए अनेक अदृश्य और कम मूल्यांकित सहयोगों की आवश्यकता पड़ती है – जैसे आवासीय विद्यालयों में कार्यरत भुगतानित कर्मचारी, अथवा माता–पिता, विशेषकर माताएँ। जो विद्यार्थी छात्रावास में नहीं रहते, वे प्रायः विद्यालय के निकट किराए पर आवास लेते हैं, जहाँ माता–पिता या भुगतानित सहयोग के माध्यम से उनकी देखभाल की व्यवस्था होती है; फिर भी वे अपने अधिकांश जागृत समय विद्यालय में ही बिताते हैं। इस प्रकार अध्ययन के लिए स्थान परिवर्तन करने वाले माध्यमिक स्तर के छात्र अपनी पढ़ाई के वर्षों के दौरान अपेक्षाकृत कम गतिशील रहते हैं। इसलिए बीजिंग या शंघाई के किसी शीर्ष विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करना स्वयं में ही एक महत्वपूर्ण सफलता की कहानी माना जाता है।

कनाडा में रहने वाले कई साक्षात्कारदाताओं ने भी अपनी शैक्षिक प्रवासन यात्रा माध्यमिक विद्यालय से ही आरंभ की, जो चीन के आंतरिक प्रवासियों की शैक्षिक यात्राओं से काफी हद तक मिलती–जुलती है। किंतु बीजिंग या शंघाई के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रवेश के साथ जुड़ी प्रतिष्ठा के विपरीत, किसी कनाडाई विश्वविद्यालय में दाखिला लेना सफलता का उतना स्पष्ट संकेतक नहीं माना जाता। कई चार–वर्षीय स्नातक छात्र या तो गाओकाओ में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, या वे इस परीक्षा से बचना चाहते थे। ब्रिटिश कोलंबिया (कनाडा) में पूर्ण शिक्षा–व्यय केवल मध्यवर्गीय या संपन्न परिवार ही वहन कर सकते हैं। परिणामस्वरूप अपेक्षाकृत कम संपन्न पृष्ठभूमि से आने वाले कई स्नातकोत्तर छात्र पढ़ाई के साथ–साथ काम भी करते हैं। शिक्षा की लागत और संभावित आप्रवासन अवसरों ने भी मेरे उत्तरदाताओं को कनाडा चुनने के लिए प्रेरित किया। अतः केवल वर्गीय उन्नति ही नहीं, बल्कि अनेक उत्तरदाताओं ने व्यक्तिगत विकास को भी कनाडा जाने का एक प्रमुख कारण बताया।

> सीमांकन प्रक्रियाएँ और स्थायी स्थानीय स्थिति प्राप्त करने की रणनीतियाँ

चीन में कम–कौशल वाले श्रम–प्रवासियों के पास उतनी सामाजिक उन्नति की आशाएँ नहीं होतीं जितनी शिक्षा–प्रवासियों के पास होती हैं। चीन की स्थानीय मेजबान सरकारें सस्ते प्रवासी श्रम का स्वागत तो करती हैं, किंतु उन्हें स्थायी हुकौ धारकों के रूप में स्वीकार करने की इच्छुक नहीं होतीं। यद्यपि आज इसका महत्व कुछ कम हो गया है, फिर भी हुकौ कुछ महत्वपूर्ण जीवनपर्यंत अधिकार प्रदान करता है, जिनमें भविष्य में बच्चों के लिए शिक्षा–संबंधी अधिकार भी शामिल हैं।

इसके विपरीत, सफल शिक्षा–प्रवासियों को स्थानीय हुकौ प्राप्त करने का अपेक्षाकृत विशेषाधिकारयुक्त मार्ग मिलता है। फिर भी उन्हें चीन के शीर्ष विश्वविद्यालयों और महानगरों में कई प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि सफलता प्राप्त करने के बाद भी बड़े शहरों के हुकौ धारक उन प्रवासियों के कौशल और अत्यंत उच्च परीक्षा–अंकों का मजाक उड़ाते हैं जिन्होंने कठिन प्रतिस्पर्धा के बाद यह स्थान हासिल किया है।

कनाडा में शिक्षा–प्रवासियों के विपरीत, चीनी शिक्षा–प्रवासी स्नातक होने के बाद बिना स्थानीय हुकौ के भी बीजिंग या शंघाई में कानूनी रूप से रह सकते हैं। इसके लिए उन्हें केवल रोजगार और आवास सुनिश्चित करना होता है। रोचक बात यह है कि क्योंकि बीजिंग हुकौ मुख्यतः राज्य–क्षेत्र के कर्मचारियों को ही विशेषाधिकार देता है, इसलिए निजी क्षेत्र में रोजगार पाने की आकांक्षा रखने वालों के लिए यह प्राथमिकता नहीं होता। कम–कौशल प्रवासियों के विपरीत, वे जानते हैं कि अच्छे निजी क्षेत्र के रोजगार – न कि हुकौ – उन्हें निजी स्वास्थ्य बीमा और पेंशन जैसी सुविधाएँ प्रदान कर सकते हैं। स्थानीय हुकौ का महत्व मुख्यतः उन प्रवासी स्नातकों के लिए अधिक होता है जिनके बच्चे होते हैं, जबकि मेरे कई साक्षात्कारदाताओं की भविष्य–योजनाएँ इससे भिन्न थीं।

इसके विपरीत, कनाडा में रहने वाले चीनी शिक्षा–प्रवासियों के लिए स्थायी निवास (च्मतउंदमदज त्मेपकमदबम) दीर्घकालिक रूप से वहाँ रहने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैकृचाहे वह बेहतर रोजगार अवसरों के लिए हो, व्यक्तिगत या वैवाहिक संबंधों के कारण हो, अथवा यौनिक हिंसा से बचने के उद्देश्य से। औपचारिक रूप से "अंतरराष्ट्रीय छात्रों" को कनाडा के अंतरराष्ट्रीय गतिशीलता कार्यक्रम के अंतर्गत स्थायी निवास प्राप्त करने का एक विशिष्ट मार्ग उपलब्ध होता है। किन्तु व्यवहारिक अनुभवों में यह मार्ग काफी जटिल सिद्ध होता है। कनाडा की अंक–आधारित प्रणाली में बार–बार होने वाले परिवर्तन और हाल के वर्षों में प्रवासन–स्वीकृति में की गई कटौतियाँ स्थायी निवास की सुविचारित योजनाओं को भी संकट में डाल सकती हैं। इसके अतिरिक्त, स्थायी निवास के लिए आवेदन का निमंत्रण प्राप्त करने हेतु अतिरिक्त अंक अर्जित करने के लिए साक्षात्कारकर्ताओं को अक्सर स्थानीय, कम–कौशल और अस्थिर प्रकार के रोजगार करने पड़ते थे। स्नातक होने और स्थायी निवास आवेदन के निमंत्रण के बीच की अवधि में प्रारंभिक कनाडाई कार्य–अनुभव भी बाद में अधिक स्थायी नौकरियाँ प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। एक साक्षात्कारकर्ता को छोड़कर सभी ने अपनी पहली स्थानीय नौकरी चीनी स्वामित्व वाले व्यवसायों में प्राप्त की, जिनमें से अधिकांश कनाडाई कार्य–अनुभव की अनिवार्यता नहीं रखते थे। इनमें से कई नियोक्ता स्वयं भी हाल ही में प्रवासी बने थे। ऐसे रोजगार प्रायः स्थानीय चीनी समुदाय को लक्षित सेवाओं से जुड़े होते हैंकृजैसे छात्रों के लिए शैक्षिक और आव्रजन सेवाएँ, अथवा रेस्तराँ में कार्य।

> निष्कर्ष

अंतरराष्ट्रीय और आंतरिक प्रवासनकृदोनों पर होने वाला शोध शिक्षा–प्रवासियों के इन अनुभवों को समझने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। जब इन अध्ययनों को संयुक्त रूप से देखा जाता है, तो यह स्पष्ट होता है कि प्रवासियों के सामने आने वाली बाधाओंकृविशेषकर शक्ति–असमानताओं—में केवल राष्ट्रीय सीमाएँ ही निर्णायक नहीं होतीं। चीन की हुकौ व्यवस्था ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच, तथा विभिन्न दर्जे वाले नगरों और महानगरों के बीच विभाजन उत्पन्न करती है; साथ ही यह कम–कौशल और शिक्षित श्रमिकों के बीच भी भेद पैदा करती है। दूसरी ओर, कनाडा में नागरिकता के बजाय स्थायी निवास ही शिक्षा–प्रवासियों को अक्सर अस्थिर रोजगार की ओर ले जाता है, जो प्रायः सामुदायिक व्यवसायों में केंद्रित होता है। इसके अतिरिक्त, नीतियों और नियमों में लगातार परिवर्तन उनकी स्थिर स्थानीय स्थिति प्राप्त करने की प्रक्रिया को और अधिक जटिल बना देते हैं। ■

संपर्क करेंरू
फेंग श्यू <fengxu@uvic.ca>

> कंबोडियाई परिधान प्रवासी श्रमिक : अनिश्चितता और प्रतिरोध

ट्ज चूंग लाई एवं **कैक्सटन सियू**, हांगकांग बैपटिस्ट विश्वविद्यालय, हांगकांग

कम्बोडियाई ग्रामीण प्रवासी श्रमिक श्रम अधिकार प्रशिक्षण सत्र में भाग लेते हुए। कैक्सटन सियु द्वारा फोटो

9 मार्च 2024 को चीन–स्वामित्व वाली Y &W गारमेंट कंपनी के लगभग 600 कंबोडियाई ग्रामीण प्रवासी श्रमिकों ने श्रम एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण मंत्रालय तक पदयात्रा कर एक औपचारिक याचिका प्रस्तुत की। इस याचिका में उन्होंने कंपनी के स्वामी द्वारा अचानक दिवालियापन घोषित किए जाने के पश्चात अवितरित वेतन और लंबित लाभों के भुगतान की मांग कीकृक्योंकि कंपनी प्रबंधन अंतिम माह का वेतन दिए बिना ही परिचालन से हट गया था। उसी दिन दोपहर में मंत्रालय ने एक आधिकारिक वक्तव्य जारी कर श्रमिकों, उनके कानूनी प्रतिनिधियों, स्थानीय श्रमिक संगठनों तथा अन्य संबद्ध हितधारकों से तत्काल विरोध प्रदर्शन समाप्त करने का आह्वान किया। मंत्रालय ने आरोप लगाया कि यह प्रदर्शन यातायात अवरोध तथा नगरीय भीड़भाड़ का कारण बन रहा है। साथ ही, मंत्रालय ने श्रमिकों को कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से निवारण प्राप्त करने की सलाह देते हुए "सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने तथा व्यापक समुदाय के हितों की रक्षा" के महत्व पर बल दिया।

वाई ऐंड डब्ल्यू गारमेंट कंपनी लिमिटेड की अचानक दिवालियापन घोषणा और इसके परिणामस्वरूप मजदूरों को वेतन न मिल पाना, विदेशी निवेश के बदलते परिदृश्य में कंबोडियाई ग्रामीण प्रवासी परिधान श्रमिकों द्वारा झेली जा रही अत्यंत अस्थिर और असुरक्षित परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। साथ ही, श्रमिकों का सामूहिक विरोध न केवल उनकी संवेदनशील स्थिति को प्रकट करता है, बल्कि बढ़ते शोषण और असुरक्षा के बीच संगठित होने, प्रतिरोध दर्ज कराने और अपने एजेंसी–बोध को स्थापित करने की उनकी क्षमता को भी दर्शाता है। चीनी स्वामित्व वाले कारखानों के तीव्र विस्तार और श्रमिक प्रतिरोध की इन घटनाओं के सम्मिलित रूप से श्रम एवं औद्योगिक समाजशास्त्रियों के सामने कई तात्कालिक और गंभीर प्रश्न उपस्थित होते हैं: चीनी पूँजी की व्यापक उपस्थिति के बीच कंबोडियाई ग्रामीण प्रवासी परिधान श्रमिकों की वर्तमान स्थिति क्या है? दयनीय कामकाजी परिस्थितियों एवं आर्थिक अनिश्चितता से उत्पन्न चुनौतियों और कठिनाइयों का श्रमिक किस प्रकार सामना कर रहे हैं? इस समूची परिस्थिति पर कंबोडियाई सरकार की आधिकारिक भूमिका और रुख क्या है?

> श्रमिकों की बहुआयामी अस्थिरता

कंबोडियाई ग्रामीण प्रवासी परिधान श्रमिकों की वर्तमान परिस्थितियों का परीक्षण करने पर उनकी अस्थिरता के अनेक और परस्पर जुड़े रूप स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। 2023–2024 में 28 परिधान कारखानों के 86 श्रमिकों पर आधारित हमारे सर्वेक्षण से यह प्रत्यक्ष होता है कि ये श्रमिक तीव्र नौकरी–असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। इसके प्रमुख कारण हैं – जीविकोपार्जन स्तर के वेतन (204

> >

अमेरिकी डॉलर प्रति माह), व्यापक रूप से प्रचलित अल्पकालिक अनुबंध (जिनमें 66% श्रमिक छह महीने या उससे कम अवधि के अनुबंध पर कार्यरत हैं), और आयु–आधारित भेदभाव – विशेषकर 40 वर्ष से अधिक आयु वाले श्रमिक, जिन्हें छँटनी और बहिष्करण का अधिक जोखिम रहता है।

कारखाने नियमित रूप से रोटेशनल निलंबन लागू करते हैं, जिसके दौरान आदेशों की कमी होने पर श्रमिकों को मात्र 40 अमेरिकी डॉलर प्रति माह तक भुगतान किया जाता है। यह प्रथा आर्थिक अस्थिरता और दीर्घकालिक अनिश्चितता के चक्र को और गहरा करती है। उद्योग का खरीदार–प्रधान वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में गहरा एकीकरण अंतरराष्ट्रीय ब्रांडों को यह सुविधा देता है कि वे मांग और उत्पादन के उतारदृचढ़ाव से जुड़े जोखिमों को सबसे अधिक कमजोर वर्गकृअर्थात स्वयं श्रमिकोंकृपर स्थानांतरित कर दें। श्रमिकों की अस्थिरता केवल कारखाने की दीवारों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि प्रवासन के पैटर्न, परिवार–जीवन की रणनीतियों, और जीवित रहने की सामाजिक–आर्थिक संरचनाओं को भी गहराई से प्रभावित करती है। श्रमिकों में से 77% ग्रामीण प्रवासी हैं, और परिवारों के अस्तित्व के लिए द्वि–आय अत्यावश्यक है। यद्यपि 75% विवाहित दंपत्तियाँ एक साथ फ्नोम पेन्ह में निवास करती हैं, परंतु दो व्यक्तियों के लिए मूलभूत जीवन–यापन की लागत (300 अमेरिकी डॉलरध्माह) सामान्य वेतन से अधिक है। इन परिस्थितियों से निपटने हेतु कई परिवार अपने बच्चों को गृह–ग्राम में छोड़ देते हैं (37%), जहाँ दादा–दादी उनकी देखभाल करते हैं। संकट की स्थितियों में ये परिवार "रिवर्स रेमिटेंस" पर निर्भर होने को विवश होते हैं – 31% श्रमिक अपने ग्रामीण परिवारों से आर्थिक सहायता प्राप्त करते हैं। ऋणग्रस्तता व्यापक है और श्रमिकों पर गंभीर प्रभाव डालती है (मध्य राशिः 4,250 अमेरिकी डॉलर), जो प्रायः भूमि को गिरवी रखकर लिया जाता है। इससे श्रमिकों की दीर्घकालिक सुरक्षा कमजोर होती है तथा कुपोषण, अंतःपीढ़ीगत गरीबी, और आर्थिक अस्थिरता का चक्र और गहरा होता जाता है, क्योंकि वेतन उनके सबसे बुनियादी उपभोग–स्तर को भी निरंतर पूरा नहीं कर पाता। ये ऋण मुख्यतः कोविड काल में कम रोजगार के कारण उत्पन्न हुए, जब श्रमिक फ्नोम पेन्ह के उच्च–व्यय वाले आर्थिक वातावरण में जीवन–यापन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसके अतिरिक्त, कुछ ग्रामीण प्रवासी श्रमिक मोटरसाइकिल खरीदने और ईंधन की लागत वहन करने हेतु भी ऋण लेते हैं ताकि वे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच आवागमन कर सकेंकृविशेष रूप से वे जो अपने बच्चों और बुजुर्ग परिजनों को गाँव में ही छोड़कर आते हैं।

> सत्तावादी पूँजीवाद और कंबोडियाई राज्य की प्रतिक्रिया

वाई ऐंड डब्ल्यू गारमेंट कंपनी लिमिटेड के विरुद्ध हुए विरोध ा–प्रदर्शन पर सरकार की प्रतिक्रिया कंबोडिया में श्रम संबंधों के भीतर उभर रहे सत्तावादी (नजीवतपजंतपंद) रुझान का द्योतक है। प्रदर्शन को "सार्वजनिक व्यवस्था हेतु जोखिम" के रूप में प्रस्तुत कर, राज्य यह संकेत देता है कि वह श्रम–आंदोलनों पर नियंत्रण को और कठोर बना रहा हैकृएक ऐसा रुझान जो व्यापक क्षेत्रीय प्रवृत्ति, अर्थात सत्तावादी पूँजीवाद, के अनुरूप है, जहाँ आर्थिक वृद्धि और विदेशी निवेश को श्रमिक अधिकारों तथा लोकतांत्रिक भागीदारी से अधिक प्राथमिकता दी जाती है।

यद्यपि कंबोडियाई ग्रामीण प्रवासी श्रमिकों का सामूहिक प्रतिरोध का एक इतिहास रहा है, किंतु उनके लिए उपलब्ध संगठित कार्रवाई का स्थान बीते वर्षों में अत्यंत संकुचित हो गया है। बेटर फैक्ट्रीज कंबोडिया के अनुसार, 2013 में 147 हड़तालें दर्ज की गई थीं, जो अगस्त 2018 तक घटकर मात्र 9 रह गईं। इसी अवधि में खोए हुए कार्य–दिवस लगभग 8,89,000 से घटकर 42,000 रह गए। मध्यस्थता परिषद को भेजे गए श्रम–विवाद 2016 में 248 थे, जो 2017 में केवल 50 रह गए। यह गिरावट श्रम संबंधों के सुधरने का संकेत कम और राज्य–प्रायोजित दमन का परिणाम अधिक हैकृजिसमें यूनियन नेताओं की गिरफ्तारी, कार्यकर्ताओं को धमकाना, तथा ट्रेड यूनियनों का सरकारी सहयोगी के रूप में सह–चयन शामिल है, विशेषतः 2013 के चुनावों के बाद से।

कंबोडिया में संगठन के लिए उपलब्ध कानूनी ढाँचा निरंतर क्षीण होता गया है, और स्वतंत्र विवाद–निपटान तंत्र अब अत्यंत विरल होता जा रहा है। सरकार द्वारा प्रयुक्त भाषा – जिसमें "सार्वजनिक व्यवस्था" और "सामुदायिक हित" पर बल दिया जाता है – एक गहरी वास्तविकता को ढँक देती है; पूँजी के हित, चाहे वह देशीय हों या विदेशी, श्रमिकों के कल्याण और अधिकारों पर स्पष्ट रूप से वरीयता प्राप्त करते हैं। कंबोडिया में यह प्रवृत्ति श्रम राजनीति के भीतर संरचनात्मक असंतुलन को और अधिक प्रकट करती है, जहाँ राज्य की नीति–प्रणालियाँ श्रमिकों के अधिकार–संरक्षण के बजाय निवेशोन्मुख आर्थिक मॉडल को प्राथमिकता देती हैं।

> अस्थिरता और प्रतिरोध की संभावनाएँ

वाई ऐंड डब्ल्यू गारमेंट कंपनी लिमिटेड में हुए विरोध–प्रदर्शन ने कंबोडियाई ग्रामीण प्रवासी परिधान श्रमिकों की बहुआयामी अस्थिरता और सीमित एजेंसी पर सत्तावादी पूँजीवाद के संदर्भ में एक तीक्ष्ण दृष्टि प्रदान की है। यद्यपि चीनी निवेश ने देश में आर्थिक वृद्धि और रोजगार–सृजन को गति दी है, यह समानांतर रूप से एक ऐसी व्यवस्था को भी सुदृढ़ करता है जिसमें जोखिम और असुरक्षा का लगभग सम्पूर्ण भार श्रमिकों पर ही डाला जाता है। अक्टूबर 2024 तक, चीनी पूँजी कंबोडिया के 2,236 औद्योगिक कारखानों में लगभग 54.7% स्वामित्व रखती है, जो 9.086 अरब अमेरिकी डॉलर के प्रभावशाली निवेश का प्रतिनिधित्व करता है। सबसे उल्लेखनीय तथ्य यह है कि कंबोडिया के लगभग 90% परिधान कारखानों पर अब चीनी निवेशकों का नियंत्रण हैकृएक संरचनात्मक प्रभुत्व जो श्रमिकों की सामाजिक–आर्थिक संवेदनशीलता को और अधिक गहरा करता है।

यह गहन परिवर्तन यह दर्शाता है कि चीन किस प्रकार "दुनिया की फैक्ट्री" की भूमिका से विकसित होकर एक अग्रणी वैश्विक निवेशक के रूप में उभरा है। चीन में बढ़ती घरेलू श्रम–लागत चीनी कंपनियों को उत्पादन इकाइयों को उन देशों की ओर स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित करती है, जहाँ कम वेतन उन्हें स्पष्ट प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करता है––ऐसे देशों में कंबोडिया प्रमुख है। कंबोडिया के प्रमुख उद्योगों में चीनी पूँजी का यह प्रभुत्व, कंबोडियाई राज्य को पूँजी–हितों के साथ स्वयं को संरेखित करने के लिए बाध्य करता है। यह संरेखणकृश्रम आंदोलनों के दमन, "सार्वजनिक व्यवस्था" पर अत्यधिक बल, और सामूहिक सौदेबाजी के अवसरों के लगातार संकुचन––में स्पष्टतः दिखाई देता है। परिण ामस्वरूप, श्रमिक–नेतृत्व वाले परिवर्तन और सामूहिक प्रतिरोध के लिए उपलब्ध स्थान और भी सीमित हो गया है।

कठोर परिस्थितियों के बावजूद कंबोडियाई ग्रामीण प्रवासी श्रमिकों की दृढ़ता बनी रहती है। विरोध–प्रदर्शन में उनकी सहभागिता की तत्परता, परिवार और समुदाय–आधारित नेटवर्क पर उनकी निर्भरता, तथा उचित वेतन और मानवीय कार्य–स्थितियों के लिए उनका सतत संघर्ष––ये सभी उनके भीतर विद्यमान मजबूत प्रतिरोध–भाव को प्रकट करते हैं। आगे का मार्ग इस पर निर्भर करेगा कि कंबोडिया के भीतर तथा अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पारकृदोनों स्तरों पर––नए प्रकार की एकजुटता, समर्थन तंत्र और वकालत के मॉडल किस प्रकार उभरते हैं, ताकि वैश्विक पूँजी और सत्तावादी शासन द्वारा गहराती अस्थिरता का प्रभावी प्रतिरोध किया जा सके। कंबोडिया का यह उदाहरण स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि वैश्वीकरण के युग में कार्य का भविष्य अंततः पूँजी के दबाव और श्रमिकों के सम्मान, सुरक्षा तथा न्याय के लिए चल रहे संघर्ष के बीच निरंतर टकराव से आकार लेगा। ■

संपर्क करें:
त्स ज चुंग लाई <22482261@life.hkbu.edu.hk>
कैक्सटन सियू <kaxton_siu@hkbu.edu.hk>

> उलझी हुई संचय प्रक्रिया के रूप में युद्ध: गाजा का मामला

गोंसाल्वेस, रियो डी जेनेरो स्टेट यूनिवर्सिटी, ब्राजील द्वारा

श्रेयः मार्कस विंकलर, वाया पेक्सेल्स

कानूनी विद्वानों ने समकालीन समाज में युद्ध के नए प्रतिरूपों को समझने में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टियाँ प्रदान की हैं। उनमें से एक, मसातो निनोमिया के सम्मान में तैयार किए गए एक अध्याय में, तोशिकी मोगामी तीन आयामों – राज्य प्रतिशोध, जनसंहार और उपनिवेशवादकृको आपस में जोड़ते हैं। हालाँकि इन प्रक्रियाओं को पूँजीवादी विकास की विशिष्ट परिस्थितियों के संदर्भ में पुनः पढ़ा जा सकता है, जहाँ भविष्य के राजस्व पर दावों से प्रेरित होकर अत्यधिक संचयित संपत्ति वित्तीयकरण के संदर्भ में नए बाजारों को खोलने के लिए दबाव उत्पन्न करती है। यह दृष्टिकोण कार्ल मार्क्स, रोजा लक्जमबर्ग और हन्ना अरेंट के विचारों से प्रेरणा लेता है, जिन्हें बाद में लैंडनाहमे थ्योरम पर होने वाली बहसों में पुनर्परिभाषित किया गया। इस दृष्टिकोण के अनुसार, स्थानिक और कालिक सीमाओं से बाधित पूँजीवादी विकास इन बाधाओं को हिंसा, औपनिवेशिक नीतियों और युद्ध के माध्यम से गैर–पूँजीवादी क्षेत्रों के अधिग्रहण द्वारा पार करता है। प्रश्न यह है कि हाल के सैन्य संघर्षों में यह प्रक्रिया किस प्रकार प्रकट होती हैकृएक ऐसी समस्या जिसे वित्तीय संचय की समग्र व्यवस्था के भीतर समझना आवश्यक है।

ब्याज–आधारित पूँजी, जो धन पर संपत्ति अधिकारों और ब्याज सहित पुनर्भुगतान की बाध्यता पर आधारित होती है, द्वितीयक बाजारों में काल्पनिक पूँजी का रूप धारण कर लेती है। यह संभावित पूँजीकरण के साथ बढ़ती आय–धाराओं की अपेक्षाओं को स्थापित करती है। निवेश अनुबंधों के रूप में यह व्यवस्था भविष्य के अधिशेष मूल्य पर दावों का अत्यधिक संचय उत्पन्न करती है, जिसकी प्राप्ति उन अधिग्रहण प्रक्रियाओं पर निर्भर करती है जो क्षेत्रों और जनसंख्याओं को मूल्य–सृजन के चक्र में सम्मिलित करती हैं। ऐसे अधिग्रहण अधिशेष पूँजी को अवसंरचना, आवास और संसाधन–उत्खनन में प्रवाहित करते हैं, साथ ही भूमि और अचल संपत्ति परिसंपत्तियों द्वारा समर्थित प्रतिभूतियों के माध्यम से आय–धाराएँ भी उत्पन्न करते हैं।

इस दृष्टि से देखा जाए तो फिलिस्तीन का विनाश युद्ध के संदर्भ में उलझी हुई संचय प्रक्रिया का एक चरम उदाहरण प्रस्तुत करता है।

> वैश्विक पूँजी के लिए एक रणनीतिक केंद्र के रूप में इजराइल

जैसा कि विलियम आई. रॉबिन्सन और होई–आन गुयेन ने उल्लेख किया है, 2003 में इराक पर आक्रमण मध्य पूर्व के वैश्विक अर्थव्यवस्था में तीव्र एकीकरण के साथ घटित हुआ। यह प्रक्रिया ग्रेटर अरब फ्री ट्रेड एरिया (GAFTA) की स्थापना तथा अतिरिक्त द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों के बाद और तेज हो गई। इसके परिणामस्वरूप रणनीतिक क्षेत्रों में कॉर्पोरेट और वित्तीय निवेश की एक लहर उत्पन्न हुई, जिसे खाड़ी देशों की विशाल पूँजीकृसॉवरेन वेल्थ फंडों में निहित खरबों डॉलर – का समर्थन प्राप्त था, साथ ही यूरोप, अमेरिका और चीन से आने वाले निवेश प्रवाह भी इसमें शामिल थे। इस परिप्रेक्ष्य में इजराइल वैश्विक पूँजी के लिए एक रणनीतिक केंद्र के रूप में उभरा।

इस संदर्भ में गाजा के घेराव को इस प्रकार समझा जा सकता है कि यह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संचित अतिरिक्त पूँजीकृजो पहले से ही इजराइली कॉर्पोरेट ढाँचे के माध्यम से प्रकट हो चुकी है – नए मूल्य–सृजन क्षेत्रों की खोज करती है। यह प्रक्रिया प्राथमिक संचय के एक रूप का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें भूमि, वस्तुओं और लोगों के अधिग्रहण के माध्यम से उन्हें बाजार–आधारित सामाजिक संबंधों में परिवर्तित किया जाता है।

> आतंकवाद का भय और आपातकाल की स्थिति: राज्य प्रतिशोध का मार्ग

यह अधिग्रहण अधिकारों और संवैधानिक गारंटियों के निलंबन पर आधारित होता है, जिससे बिना संस्थागत नियंत्रण या सुरक्षा उपायों के सैन्य तंत्र की तैनाती संभव हो जाती है। इस निलंबन को वैधता प्रदान करने के लिए एक कानूनी उपकरणकृआपातकाल की स्थिति कृका सहारा लिया जाता है। मोगामी द्वारा प्रतिपादित "राज्य प्रतिशोध" की अवधारणा इस परिवर्तन को स्पष्ट करती है; राजनीतिक रूप से प्रेरित हिंसा के प्रति राज्य की प्रतिक्रिया अब कानून द्वारा नियंत्रित नहीं रहती, बल्कि प्रतिशोध की भावना से संचालित होती है।

हमास के हमलों के बाद, बेंजामिन नेतन्याहू ने "प्रचंड प्रतिशोध" का वादा किया और "अमालेक ने तुम्हारे साथ जो किया उसे याद रखो" वाली बाइबिलीय पंक्ति का उल्लेख किया, जिसे अक्सर प्रतिशोध लेने की प्रेरणा के रूप में पढ़ा जाता है। यह परिस्थिति "आतंक" के प्रति भाषणात्मक अपीलों के माध्यम से भय को संगठित कर वैधता प्राप्त करती है। परिणामस्वरूप, एक प्रभावशाली विचारधारा सामाजिक भय और असुरक्षा को सामान्य बनाते हुए राज्य के असंतुलित प्रतिशोधात्मक उपायों को अधिकृत कर देती है। रक्षा मंत्री योआव गालांट द्वारा गाजा की "पूर्ण घेराबंदी" की घोषणा – "न बिजली, न भोजन, न पानी, न ईंधन" – युद्ध की रणनीति के रूप में सामूहिक दंड और भुखमरी के प्रयोग का एक प्रतीकात्मक उदाहरण बन गई है।

>>

> यूरोपीय उपनिवेशवाद की तर्क–प्रणाली का पुनरुत्पादन

राज्य प्रतिशोध की विचारधारा "आतंकवादी" के कलंक पर आधारित होती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में कार्य करती है जो कुछ समूहों को "अन्य" के रूप में चित्रित करती है और उन्हें हिंसक, बर्बर तथा अविवेकी विशेषताओं से जोड़ देती है। परिणामस्वरूप, ऐसे समूहों को दमन के वैध लक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह तंत्र उन समाजों की नैतिक आत्म–छवि को भी बनाए रखता है जो स्वयं को "सभ्य" मानते हैं। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो "आतंक के विरुद्ध युद्ध" यूरोपीय उपनिवेशवाद की उसी तर्क–प्रणाली को पुनः प्रस्तुत करता है, जहाँ लोगों और नस्लों के बीच पदानुक्रम स्थापित कर "सभ्य बनाने के मिशन" और उपनिवेशित जनसमूहों पर दमनकारी शासन को उचित ठहराया जाता था। इसी संदर्भ में, योआव गालांट द्वारा फिलिस्तीनियों को "मानव पशु" कहकर संबोधित करना उपनिवेशवादी परियोजनाओं में प्रचलित अमानवीकरण की भाषा की याद दिलाता है।

राज्य प्रतिशोध का यह औपनिवेशिक चरित्र समकालीन युद्धों को वित्तीय अतिसंचय की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उपकरणों में परिवर्तित कर देता है। "अन्यीकरण" पर आधारित कलंकित करने वाले विमर्श ऐसी हिंसा को वैधता प्रदान करते हैं जो क्षेत्रों और जनसमूहों के अधिग्रहण और विस्थापन को संभव बनाती है। इसका चरम रूप इजराइल – फिलिस्तीन संघर्ष में दिखाई देता है, जहाँ नेतन्याहू का अतिदक्षिणपंथी लोकलुभावनवाद उस औपनिवेशिक सैन्यवाद को और उग्र बनाता है जिसे एरान कापलान ने जाबोटिन्स्की की संशोधनवादी विरासत के रूप में पहचाना है। यह धार्मिक और प्राकृतिक विधि के तर्कों को अपनाकर अरबों पर यहूदी श्रेष्ठता की अवधारणा को स्थापित करने का प्रयास करता है, जिससे एक नस्लवादी उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिलता है जो समान सह–अस्तित्व की संभावना को ही नकार देता है। इस प्रकार का विमर्श गाजा युद्ध को जातीय शुद्धिकरण की अनिवार्यताओं के अंतर्गत राज्य प्रतिशोध के रूप में संचालित होने की अनुमति देता है, जिससे फिलिस्तीनियों के विरुद्ध जनसंहारात्मक कृत्यों का मार्ग प्रशस्त होता है। यह हिंसा वित्तीय अतिसंचय की समस्या के समाधान से भी जुड़ती है, जहाँ "टेरा नलियस" जैसी औपनिवेशिक अवधारणाओंकृअर्थात् ऐसी भूमि जिसे "खाली" या "अप्रयुक्त" घोषित कर उपनिवेशीकरण के लिए खुला बताया जाता हैकृका उपयोग विनाश और पुनर्निर्माण को उचित ठहराने के लिए किया जाता है, जिससे नए निवेश और परिसंपत्तियों के मूल्य–सृजन के अवसर उत्पन्न होते हैं।

> सैन्यीकृत संचय के साथ अंतर्संबद्ध क्षेत्रीय उपनिवेशीकरण

फोर्ब्स के अनुसार, मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष के दौरान रक्षा उद्योग से संबंधित शेयरों ने रिकॉर्ड ऊँचाइयाँ प्राप्त कीं। यह वृद्धि प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ताओं को दिए गए अनुबंधों के कारण हुई, जिसने सैन्य उद्योग को पुनः सक्रिय कर दिया। यह सैन्यीकृत संचय पूँजी के मूल्य–सृजन के अन्य रूपों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। अक्टूबर 2024 के अंत में, जब गाजा पर बमबारी जारी थी, तब इजराइल ने भूमध्य सागर में गैस और तेल की खोज के लिए बहुराष्ट्रीय ऊर्जा कंपनियों को लाइसेंस प्रदान किए। इसका उद्देश्य यूक्रेन युद्ध से और तीव्र हुई ऊर्जा संकट की पृष्ठभूमि में देश को एक गैस केंद्र में बदलना था, जैसा कि रॉबिंसन और न्गुयेन ने दर्शाया।

समय के साथ क्षेत्रीय उपनिवेशीकरण, अतिदक्षिणपंथी जातीय राष्ट्रवाद, और वित्तीय अतिसंचय के प्रवाह के बीच संबंध स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं। गाजा के पुनर्निर्माण से संबंधित प्रस्तावित योजनाओं में इजराइली सरकार द्वारा प्रस्तुत "गाजा 2035" तथा जोसेफ पेल्जमैन द्वारा तैयार "एन इकोनॉमिक प्लान फॉर रिबिल्डिंग गाजा : अ बीओटी एप्रोच", जिसे डोनाल्ड ट्रम्प की टीम के सामने प्रस्तुत किया गया था, प्रमुख हैं। दोनों योजनाएँ ऐसी अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्थाओं की वकालत करती हैं जो विदेशी निवेशकों द्वारा सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निजीकरण को प्रोत्साहित करती हैं।

नूर अराफेह और मैंडी टर्नर के अनुसार, अमेरिकी योजना इस क्षेत्र को "संपत्ति कानूनों से रहित" घोषित करती है और इसी आधार पर इसे पचास वर्षों के लिए पट्टे पर देने का प्रस्ताव रखती है। इसके अंतर्गत निवेशकों को "गाजा में इक्विटी हिस्सेदारी" प्राप्त होगी और वे अर्थव्यवस्था, अवसंरचना तथा प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करेंगे। इसके विपरीत, गाजा 2035 योजना पुनर्निर्माण को गाजा के ऊर्जा संसाधनों के दोहन से जोड़ती है – जहाँ लगभग 122 ट्रिलियन घन फीट गैस और 1.7 अरब बैरल तेल के भंडार का अनुमान है। दोनों योजनाएँ फिलिस्तीनियों के विस्थापन की पूर्वधारणा पर आधारित हैं। बीओटी योजना गाजा को "पूरी तरह खाली" करने की बात करती है, जबकि इजराइली परियोजना इसे "शून्य से पुनर्निर्मित" करने की कल्पना प्रस्तुत करती है। इसके अतिरिक्त, दोनों योजनाएँ बाहरी राजनीतिक नियंत्रण सुनिश्चित करने और निवेशकों के हितों के अनुरूप आर्थिक पुनर्गठन को संभव बनाने के लिए निरंतर सैन्य उपस्थिति का प्रावधान भी करती हैं।

> गाजा में हिंसा और वित्तीय निर्भरता के बीच फँसे फिलिस्तीनी

9 अक्टूबर 2025 को युद्धविराम के प्रथम चरण पर सहमति बनने के बाद गाजा के पुनर्निर्माण को लेकर बहस और तीव्र होने की संभावना है। ट्रम्प की 20–बिंदुओं वाली शांति योजना एक ऐसे प्रशासन का प्रस्ताव करती है जिसमें फिलिस्तीनी भागीदारी तो होगी, किंतु उसे तकनीकी प्रशासन के रूप में प्रस्तुत करते हुए राजनीतिक रूप से एक "बोर्ड ऑफ पीस" के अधीन रखा जाएगा, जिसकी अध्यक्षता अमेरिकी राष्ट्रपति करेंगे और जिसमें नवउदारवादी व्यवस्था के ऐतिहासिक पात्र – जैसे टोनी ब्लेयरकृभी शामिल होंगे। यह योजना दावा करती है कि जीवित बचे फिलिस्तीनी "जाने और लौटने के लिए स्वतंत्र" होंगे। इसके साथ ही गाजा को "ऊर्जा प्रदान" करने के उद्देश्य से एक आर्थिक पहल भी प्रस्तावित की गई है, जो निवेश आकर्षित करने के लिए पूर्ववर्ती ढाँचों का संलयन है और जिसे "मध्य पूर्व के समृद्ध आधुनिक चमत्कारी शहरों" के मॉडल पर आधारित बताया गया है (बिंदु 9 और 10)। युद्धविराम का स्वागत करते हुए ट्रम्प ने कहाः "गाजा को धीरे–धीरे पुनर्निर्मित किया जाएगा [...] दुनिया के उस हिस्से में अपार संपत्ति मौजूद है।"दोनों योजनाएँ फिलिस्तीनियों के विस्थापन की पूर्वधारणा पर आधारित हैं। बीओटी योजना गाजा को "पूरी तरह खाली" करने की बात करती है, जबकि इजराइली परियोजना इसे "शून्य से पुनर्निर्मित" करने की कल्पना प्रस्तुत करती है। इसके अतिरिक्त, दोनों योजनाएँ बाहरी राजनीतिक नियंत्रण सुनिश्चित करने और निवेशकों के हितों के अनुरूप आर्थिक पुनर्गठन को संभव बनाने के लिए निरंतर सैन्य उपस्थिति का प्रावधान भी करती हैं।

> गाजा में हिंसा और वित्तीय निर्भरता के बीच फँसे फिलिस्तीनी

9 अक्टूबर 2025 को युद्धविराम के प्रथम चरण पर सहमति बनने के बाद गाजा के पुनर्निर्माण को लेकर बहस और तीव्र होने की संभावना है। ट्रम्प की 20–बिंदुओं वाली शांति योजना एक ऐसे प्रशासन का प्रस्ताव करती है जिसमें फिलिस्तीनी भागीदारी तो होगी, किंतु उसे तकनीकी प्रशासन के रूप में प्रस्तुत करते हुए राजनीतिक रूप से एक "बोर्ड ऑफ पीस" के अध ीन रखा जाएगा, जिसकी अध्यक्षता अमेरिकी राष्ट्रपति करेंगे और जिसमें नवउदारवादी व्यवस्था के ऐतिहासिक पात्रकृजैसे टोनी ब्लेयरकृभी शामिल होंगे। यह योजना दावा करती है कि जीवित बचे फिलिस्तीनी "जाने और लौटने के लिए स्वतंत्र" होंगे। इसके साथ ही गाजा को "ऊर्जा प्रदान" करने के उद्देश्य से एक आर्थिक पहल भी प्रस्तावित की गई है, जो निवेश आकर्षित करने के लिए पूर्ववर्ती ढाँचों का संलयन है और जिसे "मध्य पूर्व के समृद्ध आधुनिक चमत्कारी शहरों" के मॉडल पर आधारित बताया गया है (बिंदु 9 और 10)। युद्धविराम का स्वागत करते हुए ट्रम्प ने कहाः "गाजा को धीरे–धीरे पुनर्निर्मित किया जाएगा [...] दुनिया के उस हिस्से में अपार संपत्ति मौजूद है।"

गाजा का युद्ध यह दर्शाता है कि विनाश और पुनर्निर्माण की उलझी हुई संचय प्रक्रिया किस प्रकार विस्थापन, वित्तीयकरण और शेष बचे समुदायों के बीच एक जटिल अंतर्संबंध उत्पन्न करती है। ओरवा स्वितात के अनुसार, जनसंहारात्मक हिंसा के विरुद्ध प्रतिरोध भूमि के साथ सामूहिक या सामुदायिक संबंधों की पुनः पुष्टि करता है और अधिग्रहण के विरुद्ध संघर्षों को प्रेरित करता है। वहीं "आर्थिक मूल्य–सृजन" को औपनिवेशिक तकनीक के रूप में प्रयोग करते हुए नागरिक समावेशन का वादा किया जाता है, किंतु वह एक स्तरीकृत इजराइली नागरिकता ढाँचे के भीतर सीमित रहता है, जो युद्धोत्तर परिस्थितियों में और अधिक भेदभावपूर्ण होता जा रहा है। बढ़ती हुई ध्वंसात्मक कार्रवाइयों और मौतों के साथ–साथ पुनर्गठित क्षेत्रों में आर्थिक समृद्धि के वादे भी प्रस्तुत किए जाते हैं। इस प्रकार, उलझी हुई संचय प्रक्रिया फिलिस्तीनियों को हिंसा और पुनर्निर्माण पर आधारित वित्तीय निर्भरता के बीच फँसा देती है। ■

संपर्क करें:
गिल्हेर्मे लेइटे गोंसाल्वेस <guilhermeleite@iesp.uerj.br>

ISA PUBLICATIONS

GLOBAL DIALOGUE

International Sociological Association

www.isa-sociology.org